

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

20 अक्टूबर, 1977

खण्ड 2, अंक 4

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 20 अक्टूबर, 1977

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4)1
नियम 45 के अधीन सदन के पटल पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(4)21
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4)28
अध्यक्ष द्वारा घोशणा	(4)51
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	(4)51
बहिर्गमन	(4)53
विशेषाधिकार प्रश्न:-	
(1) चौधरी हरद्वारी लाल एम.एल.ए. के विरुद्ध अध्यक्ष महोदय तथा पूर्ण सदन के विरुद्ध अप्रतिश्टाजनक टिप्पणियों सम्बन्धी	(4)55
(2) चौधरी सुरेन्द्र सिंह एम.एल.ए. को पुलिस द्वारा सदन में आने से कथित रोकने सम्बन्धी	(4)57

लोक लेखा समिति तथा औद्योगिक बोर्ड में चुनाव के लिए उम्मीदवारी की वापिसी	(4)58
बहिर्गमन	(4)58
लोक लेखा समिति तथा औद्योगिक बोर्ड में चुनाव के लिए उम्मीदवारी की वापिसी (पुनरारम्भ)	(4)59
कार्य मन्त्रणा समिति का प्रथम प्रतिवेदन	(4)60
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(4)61
संकल्प (गैर-सरकारी):-	
बाढ़ पीड़ित लोगों को अधिक वित्तीय तथा अन्य सभी प्रकार की सहायता देने सम्बन्धी	(4)61

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 20 अक्टूबर, 1977

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (ब्रिगेडियर रण सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

Co-operative Societies Audited

***62. Rao Dalip Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) the total number of Co-operative Societies audited during the year 1973-74, 1974-75, 1975-76, 1976-77 and 1977-78 to date, separately; and

(b) the number of embezzlement cases in Co-operative Societies detected by the audit referred to in part(a) above and the amount involved therein?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1-1-77 से 31-8-77

(ए)	13342	13886	14099	10339	1600
(बी)	371	379	593	553	79
	37.95	52.53	67.73	63.29	8.61
	लाख रूपये	लाख रूपये	लाख रूपये	लाख रूपये	लाख रूपये

राव दलीप सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कोओप्रेटिव सोसायटीज का आडिट साल में एक बार कराया जाता है या दो साल में एक बार कराया जाता है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: साल में एक बार आडिट कराया जाता है यदि कोई ितकायत की जाए तो स्पे ाल आडिट भी कराया जा सकता है ।

राव दलीप सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि आडिट डिपार्टमेंट रजिस्ट्रार आफ कोओप्रेटिव सोसायटीज के अन्डर आता है या सैपेरट डिपार्टमेंट हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: रजिस्ट्रार कोओप्रेटिव सोसायटीज के अन्डर है ।

श्री फतेह चन्द विज: मंत्री महोदय ने बताया है कि किसी साल 13 हजार, किसी साल 14 हजार गबन के केसिज की

फिाकायत आई और गबने के केसिज पकड़े गए हैं। पिछली सरकार को तो छोड़िए। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार क्या पग उठा रही है जिससे की भविश्य में ऐसे गबन के केसिज न हों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: हम आडिट स्टाफ को स्ट्रेग्थान कर रहे है। और जो बड़े बड़े इंस्टीच्यूांज हैं जैसे हैफेड, भागर मिल्ज बगैरह वहां पर कंकरेन्ट स्कीम लागू करने की सोच रहे हैं।

चौधरी भोर सिंह: क्या मंत्री महोदय की कृपा करेंगे कि आडिट डिपार्टमेंट को रजिस्ट्रार से अलग करने का कोई विचार हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: नहीं इस समय नहीं।

श्रीमति भान्ति देवी: कोआप्रेटिव सोसायटीज में जो सैक्रेटरी नियुक्त हैं वे 400, 450 रूपये वेतन पाते हैं लेकिन अगर उनका काम देखा जाए तो सौ रूपये के काबिल भी नहीं है। सारे ऐबसेन्ट रहते है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: पिछली सरकार ने कंज्यूमर स्टोर्ज तथा भागर मिल्ज और मिनि बैंक्स में कुछ ऐसे व्यक्ति लगाए हैं जिनकी क्वालिफिकेांन पूरी नहीं बनती थीं और न वे उतनी पे के अधिकारी थे जो उनको दी जा रही है। इस चीज को दूर करने

के लिए हमने एक सिक्रीनिंग कमेटी बनाई है और वह सिक्रीनिंग करेगी।

श्री दीप चन्द भाटिया: फरीदाबाद के सुपर बाजार में पिछले एम.एल.ए. श्री के.एन. गुलाटी और उनकी ही सारे आदमी उस स्टोर में काम कर रहे हैं और लाखों रूपए का गबन कर रहे हैं। पिछली सरकार के टाईम में भी वे लोग गबन कर रहे थे और अब भी गबन कर रहे हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उनके खिलाफ एक एन कब लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: डिसअलाड, यह सवाल सोसायटीज के बारे में है।

श्री दीप चन्द भाटिया: स्पीकर साहब, यह उसी से ताल्लुक रखता है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो रिक्वायत नोटिस में लाई है उस पर फौरी तौर पर एन कब लिया जाएगा।

चौधरी भजन लाल: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो आडिट करवाते हैं उसमें कितने ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ एक लाख रूपए से ज्यादा का गबन है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, यह फिगर इस वक्त मेरे पास नहीं है अगर अलग सेन नोटिस देंगे तो जवाब दे दिया जाएगा।

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, कोआप्रेटिव डिपार्टमेंट, में इतना लम्बा चौड़ा करणान हैं, इतनी बड़ी बीमारी के लिए कोई ड्रास्टिक कदम उठाने की आवश्यकता है। ड्रास्टिक बीमारी के लिए ड्रास्टिक रैमीडी चाहिए। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वे कौन से ड्रास्टिक कदम उठाने की सोच रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इस समय सरकार इन्टरनल और कनकरेन्ट आडिट इंट्रोड्यूस करने की स्कीम जारी करने की सोच रही है और अगर कोई और अच्छा सुझाव आएगा तो उस पर भी विचार किया जाएगा।

स्वामी आदित्यवेत: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि गबन के केसिज में जितने अधिकारी और कार्यकर्ता पकड़े गए हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: अगर माननीय सदस्य किसी खास केस का जिक्र करें तो बताया जा सकता है। वैसे जो एक्शन लिया जाता है उसका तरीका यह है कि गबन करने वाले के खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्ट्रर किया जाता है और कोर्ट में प्रोसिडिंग चलती है।

चौधरी लाल सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अम्बाला जिले की कोआप्रेटिव सोसायटी के जो लोग पकड़े गए हैं उनसे कब तक पैसा वसूल कियसा जाएगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: मैंने परसों भी कहा था कि अम्बाला जिले की एक रिाकायत चौधरी लाल सिंह ने काफी व्यक्तियों के दस्तखत और अंगूठे लगवाकर भेजी थी और वह कार्यवाही के लिए, विजिलैन्स को इंकवायरी के लिए भेज दी गई है।

श्री मूल चन्द मंगला: स्पीकर साहब, कोआप्रेटिव सोसायटीज में चैंकिंग आफिसर्ज होने चाहिए। वैसे तो अब भी हैं लेकिन बाकायदा चैंकिंग नहीं करते और चैंकिंग न होने की वजह से सारी गड़बड़ होती है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बाकायदा चैंकिंग कितने दिनों में होती हैं और अगर नहीं होती तो क्या बाकायदा चैंकिंग करवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, माननीय सदस्य किस किस्म की चैंकिंग का जिकर कर रहे हैं साफ तौर पर बताएं।

चौधरी पीर चन्द: स्पीकर साहब, गबन किए हुए रूपयों की वसूली नहीं हो रही है तो क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि किसी स्पे टाल सैल के द्वारा उन व्यक्तियों से रूपया वसूल करने की स्कीम सरकार के विचाराधीन है जिससे कि जल्दी से जल्दी रिकवरी हो सके ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, पन्द्रह हजार से ऊपर की रिकवरी के लिए चाहे वह एक लाख है या दस लाख है सरकार ने पिछले दो महीने से एक जबरदस्त अभियान चलाया हुआ है और दो महीने में कोई बीस लाख रूपए की वसूली की गई है। तीन चार डिस्ट्रिक्ट्स में रिकवरी नहीं की गई है जहां पर फ्लड आया हुआ है ?

चौधरी ई वर सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी स्कीम है जिसमें नान-एग्रीकलचरल कर्जा पंजाब ने नल बैंक के थ्रू मिलकर कोआप्रेटिव बैंक से मिले ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इस समय इस तरह की कोई स्कीम जेरे-गौर नहीं है।

श्रीमति भान्ति देवी: स्पीकर साहब, मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहती हूं कि सोसायटीज के जो चेयरमैन लगाए हुए हैं वे अपने कनवेन्स का, टैलिफोन का और मकान का दुरुपयोग करते हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अगर उनके नोटिस में इस तरह का कोई स्पैसिफिक केस लाया जाए तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: अव य की जाएगी।

मास्टर फिाव प्रसाद: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों ने गबन किया है उसमें से कितनों को सजा मिली है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: यह डेटा इस वक्त अवेलेबल नहीं है। अगर मैम्बर साहब नोटिस दें तो अवेलेबल किया जा सकता है।

श्री भामेरा सिंह: स्पीकर साहब, कोआप्रेटिव सोसायटीज में पब्लिक के इलैक्टिड मैम्बर्ज होते हैं चूंकि वे लोग अनपढ़ होते हैं इस कारण से वहां पर रूपये पैसे के मामलात में गड़बड़ का अन्देा हो सकता है जिसकी वजह से काफी क्लेसिज बनते हैं, क्या सरकार के जेरे-गौर कोई ऐसी तजबीज है कि कैा की हैंडलिंग उनसे लेकर के किसी सरकारी कर्मचारी को दे दी जाए और सुपरवीजन उन्हीं इलैक्टिड मैम्बर्ज की ही रखी जाए क्या इस किस्म की कोई कमेटी बनाने पर सरकार गौर करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: पहले ही ऐसी एक कमेटी बनाने की सरकार की योजना है जोकि कोआप्रेटिव मूवमेंट में जितनी भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है उसके लिए सुजैान दे। उस कमेटी में अपोजीान के वरिश्ठ मैम्बर्ज को भी रख रहे हैं।

श्री भले राम: अध्यक्ष महोदय, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोआप्रेटिव सोसायटीज से कोई पैसा नहीं लिया और उन लोगों के गलत अगूठे लगाकर के दूसरे लोग पैसा निकलवा कर ले गये हैं और पुलिस यू ही उन लोगों को तंग कर रही है जिन्होंने कोई

पैसा वगैरह नहीं लिया। क्या सरकार कोई ऐसा कदम उठायेगी ताकि किसी भले आदमी को यू ही तंग न किया जाए।

श्री वीरेन्द्र सिंह: इस किस्म की कोई रिक्वायत आयेगी तो सरकार उस पर गौर करेगी।

चौधरी हरस्वरूप बूरा: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने फरमाया कि जिन लोगों के पास 15 हजार से ऊपर सोसायटीज का कर्जा है उनकी इन्कवारी की जायेगी मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ कि जो 15 हजार से नीचे के लोग हैं क्या उनका कर्जा माफ कर दिया गया है या उनसे भी रिक्वारी की जाएगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: फिलहाल रिक्वारी सस्पेंड की है, क्योंकि बड़ा भारी फ्लड आया था और हरियाणा में हालात बड़े गम्भीर हो गए थे।

चौधरी भजन लाल: क्या मंत्री महोदय के नोटिस में यह बता है कि करनाल, हिसार और गुड़गांव जिलों में कुछ आदमियों की तरफ कई सालों से लाखों रूपए की रिक्वारी अभी बकाया है क्या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: यह बात सरकार के नोटिस में है और उनकी रिक्वारी कराई जा रही है।

चौधरी हरि चन्द हूडा: स्पीकर साहब, कोआप्रेटिव और गबन दोनों हरफ साथ साथ चल रहे हैं, कोआप्रेटिव जरूरी है और गबन जो है वह बहुत बुरी बात है जो बुरी बात है उस बात को खत्म करने के लिए क्या मिनिस्टर साहब कोई टाईम दे सकते हैं कि इतने टाईम में स बुरी बात को खत्म कर दिया जाएगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: टाईम तो देना बड़ा मुश्किल है पर सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि इस डिपार्टमेंट को बिल्कुल पाक बना दिया जाए।

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, जब हमारी जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, तब हम इस बारे में सवाल उठाते थे कि सोसायटीज जो लोन देती हैं, उनका प्रोसीजर बहुत लम्बा है, दो-दो महीने तक किसान बेचारा चक्कर लगाता रहता था और लोन के लिए रिश्तत भी देनी पड़ती थी। फिर कहीं जाकर लोन मिलता था। तो क्या अब सरकार इस लम्बे प्रोसीजर को ठीक करने की कोई कार्यवाही करेंगी, ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: प्रोसीजर ठीक है जैसे चौधरी भाम सिंह जी ने फरवाया कि लोग अनपढ़ हैं, अज्ञानी हैं पर आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप जाकर उन लोगों को समझाएं।

चौधरी संत कंवर: अनपढ़ की बात नहीं है चौधरी साहब, इसमें प्रोसीजर बदला जा सकता है, किसान के घर को चैक किया जा सकता है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: आप कोई सुझाव दें, उस पर गौर कर लियसा जाएगा।

श्री भाम ोर सिंह: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि सोसायटीज का जो आडिट होता है उसकी रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए कितना टाईम है और अगर कोई कोआप्रेटिव सोसायटी समय पर जवाब न दें, उसके खिलाफ क्या एक् ान लिया जाता है और कितनी ऐसी सोसायटीज है, जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: कितनी सोसायटीज ने अब तक जवाब नहीं दिया, इस वक्त यह फिर्ज हमारे पास नहीं है। ऑनेरबल मेंम्बर इसके लिए अलग से नोटिस दें तो हम बता देंगे। दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कह कि आडिट के बाद जो सोसायटीज जवाब न दें, उन पर क्या एक् ान लिया जाता है, इस बारे में जो हमारा सिस्टम है, वह बहुत अच्छा नहीं है। उसको हम ठीक कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: इस पर 15 मिनट तक बहुत सप्लीमेंटरी हो चुके हैं। तीन लास्ट सिप्लीमेंटरी होंगे। पहले स्वामी अग्निवे ा जी पूछेंगे।

स्वामी अग्निवे T: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा राज्य के अन्दर दूध के चार बड़े-बड़े मिलक प्लांट लगे हैं, जिनको 1 अप्रैल 1977 से सरकार ने अपने चार्ज में लिया है लेकिन उस पर 10 करोड़ रुपया सरकार का लगा हुआ है, अभी तक वहां पर उनके ऑडिट के लिए कोई ऑडिट पार्टी नहीं भेजी गई है, क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और किन कारणों से ऐसा हो रहा है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: कोआप्रेटिव डिपार्टमेंट में इनके विलय के लिए अभी तक ही मिलक प्लांट का प्रोसैस पूरा नहीं है। प्रोसैस जारी है। ज्यों ही प्रोसैस पूरा हो जाएगा फौरी तौर पर आडिट करया जाएगा।

श्री लछमन सिंह: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि हम मौजूदा ढांचे में जो कोआप्रेटिव मूवमेंट में लूट चल रही है, इसको सैट करने में एक साल के अन्दर सरकार कामयाब हो जाएगी ताकि आइन्दा एम्बैजलमेंट न हो सके ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: यह तो सरकार की विल पर हैं। यह काम एक साल की बजाए नौ महीनों में भी हो सकता है।

चौधरी गंगा राम: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट हैं वह जब बैंको से इंडस्ट्री लगाने के लिए कर्जा लेते हैं, तो उनको 3 या 5 रुपए सैकड़ा है, तो उससे साढ़े 13 परसेन्ट सैंकड़े के हिसाब से ब्याज की दर वसूल की

जाती है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो रेट आफ इंटरैस्ट कैपिटलिस्ट और बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट देते हैं, वही किसानों से भी लिए जाने की सरकार की कोई नीति विचाराधीन है ताकि किसानों को भी राहत मिल सके।

Sh. Verender Singh: I don't think this question is relevant to the main question.

राव दलीप सिंह: अध्यक्ष महोदय, इस वक्त कोऑप्रेटिव सोसायटीज के अन्दर भारी तादाद में एम्बैजलमेंट होती है। जिनका बड़ा कारण मेरे ख्याल में यह है कि कोऑप्रेटिव और आडिट डिपार्टमेंट्स एक ही आदमी के अन्दर हैं जिसके कारण ऑडिट करने वाले एक दूसरे के खिलाफ सही जांच नहीं कर पाते, इसलिए एम्बैजलमेंट के केसिज बढ़ते हैं, तो क्या मंत्री महोदय इस चीज को दूर करने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: इसके बारे में पहले अर्ज किया कि सरकार इस सारी गन्दगी को दूर करने के लिए एक कमेटी बना रही है और प्रतिपक्ष की ओर से दो माननीय सदस्य राव दलीप सिंह और चौधरी भामा देव सिंह उस कमेटी के सदस्य होंगे फिर इनके हाथ देखेंगे कि ये क्या करते हैं।

चौधरी खुरीद अहमद: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि कोऑप्रेटिव सोसायटीज के अन्दर जो गबन के केसिज होते हैं, उनकी पैरवी करने के लिए कोऑप्रेटिव डिपार्टमेंट की ओर से जिस तरह से पुलिस की एक प्रोसीक्यूटिंग एजेंसी होती है, उसी

तरह की कोई कोआप्रेटिव डिपार्टमेंट की स्पै ल एजेंसी है ?
अगर नहीं है तो क्या सरकार इस पर गौर करेगी कि इस प्राकर
की स्पै ल एजेंसी कोआप्रेटिव डिपार्टमेंट में होनी चाहिए ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: सुझाव बहुत अच्छा है, गौर किया
जाएगा।

Constitution of Committee

***95. Ch. Birnder Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to constitute a Committee consisting of the Member of the House to have effective control over the various public undertakings, semi-Government, autonomous orporations working in the State of Haryana ?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): नहीं जी।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, जैसे मुख्यमंत्री महोदय ने अभी अपना जवाब न में दिया है तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि एटप्रैजैन्ट हाउस की कोई ऐसी एक्सक्ल्यूसिव बॉडी जो पब्लिक अन्डर टेकिंगज को डील करती हो है ?

चौधरी देवी लाल: ऐसा मामला जेरे गौर है, क्योंकि यह मामला काफी कमलीकेटिड है, इसको सम्भालने के लिए जैसे पंजाब में एक कमेटी है अगर रूल इजाजत देंगे तो यहां भी बनाई जाएगी।

श्री भाम ेर सिंह: क्या मुख्य मंत्री महोदय बताएँगे कि इस वक्त ऐसा कोई अरेन्जमेंट या सिस्टम है जो इन सारी बॉडीज जो हैं, इनका हिसाब किताब देख सकें ? क्या गवर्नमेंट की तरफ सके कोई ऐसी मीनिरी है ?

चौधरी देवी लाल: एट प्रैजैन्ट कोई नहीं है, इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ।

श्री मूल चन्द जैन: क्या मुख्य मंत्री जी के नोटिस में कोई ऐसी बात है कि सैन्टर में पब्लिक अन्डर टेकिंगज की निगरानी करने के लिए पार्लियामेंट की तरफ से एक पार्लियामेंटरी कमेटी है। अगर वहां सैन्टर में ऐसा हो सकता है तो हमारी स्टेट में ऐसा होने में क्या दिक्कत है, क्या इस पर विचार करने के लिए हमारी सरकार तैयार है ?

चौधरी देवी लाल: श्री मूल चन्द जी ने जो सुझाव दिया है इसके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यह इतना कम्प्लीकेटिड मैटर है इसके लिए कुछ न कुछ जरूर होना चाहिए, इस पर हम विचार कर रहे हैं।

राव वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, जैसे मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि हम विचार कर रहे हैं कितने दिनों तक विचार करने के बाद इसका फैसला कर लेंगे ?

चौधरी देवी लाल: जल्द से जल्द।

Excesses Committed during Sterilization

***103. Sathi Ayodhya Parshad:** Will the Minister for Health be pleased to state:-

(a) whether any enquiry is being conducted by the Government for the excesses committed by the officers during sterilization; and

(b) whether the Government is aware of the excesses committed by the District Education Officer, Narnaul during sterilization, if so, the action taken in this connection so far?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमति डाक्टर कमला वर्मा):

(क) सरकार ने आयुक्त हिसार तथा अम्बाला मण्डल को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में नसबन्दी के सम्बन्ध में की गई ज्यादतियों तथा जोर जबरदस्ती के मामलों में जांच करने के लिए नियुक्त किया है।

(ख) सरकार के ध्यान में है कि जिला शिक्षा अधिकारी नारनौल के विरुद्ध नसबन्दी की ज्यादतियों के बारे में कुछ शिकायतें आयुक्त हिसार मण्डल के पास जांच के लिए लम्बित पड़ी हैं।

श्रीमति भान्ति देवी: क्या मंत्री महोदया बातएंगी कि जो औरतों और मरदों की नसबन्दी के दौरान मृत्यु हो गई, उनके बारे में सरकार कुछ सोचेगी ?

श्रीमति डाक्टर कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने एक कमेटी बिठा दी है जिसमें श्री मंगल सैन और श्री बीरेन्द्र सिंह जी हैं। ये उन सारी एप्लीके ान्ज के ऊपर गौर कर रहे हैं। अभी तक हमें 30 केसिज की सूचना आई है जिनकी डैथ हो चुकी है और उनको दो लाख बीस हजार रूपए कम्पनसे ान दिया गया है। हमारे पास टोटल 140 केसिज हैं।

कंवर राम पाल सिंह: क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि यह कमेटी कितने दिन से बनी हुई है और कितने दिन तक अपनी रिपोर्ट दे देगी ?

श्रीमति डाक्टर कमला वर्मा: जनता सरकार ने अता ही कमेटी बनाई है और उसकी भीघ्र ही रिपोर्ट तैयार हो जाएगी।

श्री रण सिंह मान: क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि जिन सरकारी कर्मचारियों को नसबन्दी के मामले में डील दिखाने के कारण विक्टेमाइज किया गया था उनकी विक्टेमाइजे ान बहाल की जाएगी।

श्रीमति डाक्टर कमला वर्मा: जो जो भी ऐसी बात हमारे नोटिस में आ रही है, उसको पूरी तरह से बैनेफिट देने की को ि ा कर रहे हैं।

चौधरी पीर चन्द: जैसे मंत्री महोदया ने अभी बताया कि उन्हें 30 आदमियों के मरने की इतलाह मिली है। अगर उनके

नोटिस में और ऐसे केसिज आएंगे तो क्या उनके परिवारों को भी मदद दी जाएगी ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदया, जैसे जैसे ये केसिज नोटिस में आएंगे उनको जरूर कम्पनसेट किया जाएगा।

चौधरी ई वर सिंह: क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि जितनी मौतें हुई हैं और िाकायतें आई हैं उनमें हरिजन कितने हैं ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा: अभी तक जो हमारे पास कम्लेंट्स आई हैं उनमें से हरिजनों की तरफ से 78 आई है।

चौधरी राम किान: क्या मंत्री महोदया उन लोगों के जिला वार नाम बताने की कृपा करेंगी जिनके साथ एमरजेंसी के दौरान पुलिस अफसरों ने ज्यादती की ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, हमारे पास कुल कम्लेंट्स जो आई है वह 1227 आई हैं। जहां तक जिलावार फिर्ज का ताल्लुक है, वह लिखित सवाल से सम्बन्धित तो नहीं है लेकिन फिर भी इनको बताती हूं कि अम्बाला से 172, भिवानी से 62, गुड़गांव से 117, हिसार से 137, जींद से 66, करनाल से 92 कुरुक्षेत्र से 92, नारनौल से 58, रोहतक से 94, सिरसा से 52 तथा सोनीपत से 74 तथा चण्डीगढ़ और दूसरी जगहों से 88 िाकायतें आई हैं।

चौधरी लाल सिंह: क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि जो महिलाएं और पुरुष आंप्रे ान की वजह से बेकार हो गए हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं ? दूसरे जिन कंवारे लड़कों का आंप्रे ान कर दिया है, उनका क्या होगा ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, जो भी गलत केसिज हुए हैं उनके इलाज के लिए सी.एम.ओ. को लिख दिया गया है कि उनको फ्री चिकित्सा सुविधा दी जाए और जो कंवारों के आंप्रे ान हुए हैं, उनकी संख्या 105 हैं जिनमें दो तीन लड़कियां भी थी। इन सबको हमने रि-कैनालाइज कर दिया है। आगे भी जो ऐसी िाकायतें आएंगी उनको भी पूरी सुविधा दी जाएगी।

श्री मूल चन्द जैन: क्या मंत्री महोदय फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम को ठीक समझती हैं और इस मामले में पीछे जो ज्यादाती हुई उनकी वहज से इस प्रोग्राम को धक्का तो नहीं पहुंच रहा है ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा: जब से जनता सरकार आई है इसने इस प्रोग्राम में किसी से भी ज्यादाती नहीं की बल्कि हमने कानूनी तौर पर ज्यादाती बन्द कर दी है, जो अपनी मर्जी से आंप्रे ान करवाना चाहे, उसके लिए हस्पताल खुले हुए हैं।

श्री गुलजार सिंह: मंत्री महोदया ने जो कमेटी के बारे में बताया उसके बारे में लोगों का कुछ ऐसा ख्याल है कि उसका

काम ढीला चल रहा है। क्या कमेटी के पास काम ज्यादा है या कोई और बात है ? मैं जानना चाहता हूँ कि इस काम के लिए तेजी लाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा: हम इस पर पूरी तरह से सोच रहे हैं और इसकी रिपोर्ट जल्दी तैयार हो जाएगी।

श्री दीप चन्द भाटिया: क्या मंत्री महोदया बातेंगी कि जिन कांग्रेसियों ने जबरदस्ती नसबन्दी के जुल्म किए उनके ऊपर सरकार क्या एक्शन ले रही है ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, कांग्रेसियों को तो पहले ही काफी सजा मिल चुकी है। उनकी तो गद्दी छिन चुकी है इससे ज्यादा सजा उनको और क्या मिलेगी ? फिर भी इनक्वायरी होने के बाद जो दोशी पाया जाएगा उसको सजा दी जाएगी।

चौधरी भजन लाल: जैसे कि अभी मंत्री महोदया ने बताया कि 105 अविवाहित नौजवानों के ऑप्शन किए गए हैं तो यह बहुत ही सीरियस मामला है इसलिए जिन अधिकारियों का इसमें हाथ था उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा: कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद दोशी को दण्ड दिया जाएगा।

श्री हीरा नन्द आर्य: क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि उस वक्त जो कांग्रेसी एम.एल.एज. और मिनिस्टर्ज थे उनमें से कितनों के आप्रेशन किए गए ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा: इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए।

चौधरी गया लाल: क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि जिन गरीब लोगों के आप्रेशन खराब हो गए हैं और वे एक-एक साल से इलाज करवा रहे हैं, उनका जो माली नुकसान हुआ है उसको पूरा किया जाएगा।

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा: हम चिकित्सा सुविधा तो सब को दे रहे हैं और फाइनेंसियल ऐड के लिए जो अधिकारी हैं उनके लिए पूरा विचार कर रहे हैं।

डाक्टर बृज मोहन गुप्ता: जैसे मंत्री महोदया ने बताया कि 105 अविवाहित लोगों के आप्रेशन हुए हैं तो 75 प्रतिशत ऐसे चांसिज हैं कि रिक्लेनेलाइजेशन जो है वह फेलुयर हो सकती है। इसलिए जिनका परमानेंट आप्रेशन हो गया है उसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है उनके ऊपर क्या एक आप्रेशन लिया जाएगा ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा: यह पालिसी मैटर की बात है। यह बात मुख्य मंत्री और सारे अन्य मंत्री कैबिनेट के, बैठकरी विचार कर लेंगे कि क्या लीगल पुनिशमेंट देनी है।

श्री मूल चन्द मंगला: स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने सब जगह मैडिकल हैल्थ देने की बात कही है। मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि कई ऐसे केसिज है जिनको फ्री मैडिकल हैल्थ नहीं मिलती क्योंकि हस्पतालो में न डाक्टर होते है न दवाईयां होती है। अगर उन्हे दूसरी जगह भेजा जाए तो गरीब लोग जा नहीं सकते। हमारे पास ऐसी कई रिक्वायते आती हैं क्योंकि दवाखानो में दवाई का कार्ड उचित प्रबन्ध नहीं है। क्या सरकार द्वारा भेजने के लिए कोई इन्तजाम किया गया है ?

श्री मति डाक्टर कमला वर्मा: वैसे तो ह पांच हजार आबादी के कस्बे में हैल्थ डिपार्टमेंट ने एक मल्टी परपज वर्कर रखा हुआ है और हर 25 हजार की आबादी पर एक प्राइमरी हैल्थ सैन्टर बनाया हुआ है। अगर ये लोग वहां तक नहीं पहुच सकते तो जनता सरकार ने अब जन स्वास्थ्य रक्षण योजना बनाई है जो कि एक हजार के पीछे एक व्यक्ति चिकित्सा सेवा करेगा ताकि सबको मैडिकल हैल्थ मिल सके दवाई आदि तो बजट के आधार पर पैसा दिया जाता है और विचार कर लेगे।

मास्टर रिाव प्रसाद: क्या मंत्री महादया बताएंगी कि जिन अफसरान ने कांग्रेस के भासन में कांग्रेस सरकार की खानूदि हसिल करने के लिए अपने अधीन काम करने वाले क्लर्क और चपड़ासियो का जबरदस्ती आप्रेान करवाया है और आप्रेान करवाने के बाद वे मृत्यु पैया पर पड़े हुए है उनके खिलाफ सरकार कोई एक्ान लेगी ?

श्रीमति डाक्टर कमला वर्मा: मैने पहले भी नम्र निवेदन किया था कि जैसे-जैसे हमें ऐसे केसिज का पता चलता जाएगा हम इनकी इनक्वायरी करवाएंगे और उनको पनि 1 किया जाएगा।

श्री मति भाकुन्तला देवी: क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि जो गरीब हरिजन जिन के पास न आप्रे 1 न के सर्टिफिकेट है ओर न ही कहीं इलाज के लिए जा सकते हैं उन का क्या हस्पतालो में इलाज करवाने के लिए सरकार ने कुछ सोचा है ?

श्रीमति डाक्टर कमला वर्मा: अध्यक्ष महोद, जनता के जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं अगर ये कोई ि 1 कायत करेंगे तो हम उनकी बात प्रमाणित मानेंगे।

श्री फतेहचन्द विज: स्पीकर साहब, जो कमेटी मुकर्रर की गई है उसका जिक्र यहां पर आया है कि केसिज को कमेटी को रैफर किया गया है। क्या 50 साल के उपर के लोग जिन का आप्रे 1 न हुआ है, उनके बारे में कोई इन्क्वायरी करवायेंगे ?

श्रीमति डाक्टर कमला वर्मा: हर प्रकार की एकसैसिज, जो फैमिली प्लानिंग के बारे में की गई है , कि इनक्वायरी करवाएंगे। 50 वर्ष से ऊपर 179 केस हैं ।

कानरेड भांकर लाल: स्पकीर साहब, कुछ कर्मचारी ऐसे है जिनको सरकार ने या उन के बड़े आफिसरो ने हुक्म दिया है कि आप्रे 1 न करवाओ लेकिन उन्होने आप्रे 1 न नही करवाया, इनका हुक्म नहीं माना और इस बिना पर उनको मुअतिल कर

दिया, बरखास्त किया गया, डिग्रेड किया गया । क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि इन कर्मचारियों का क्या हल है ?

श्रीमति डाक्टर कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी नम्र निवेदन कर चुकी हूँ कि ऐसी कई एप्लीके टन्ज जो हमारे नोटिस में आ रही हैं, हम उनको एग्जामिन करके री-इन्स्टेट कर रहे हैं और कोई हैरसमेंट नहीं की जायेगी ।

साथी अयोध्या प्रसाद: क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि 1976-77 में फ़ैमिली प्लानिंग पर कुल कितना खर्चा हुआ है ?

श्रीमति डाक्टर कमला वर्मा: यह सैपरेट क्वै चन है, इसके लिए नोटिस दे ।

श्री दीप चन्द भाटिया: मैं आपके द्वारा मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूँ कि हमारे फरीदाबाद में बाद ग़ाहखान हस्पताल है । इस हस्पताल की यह हालात है कि कोई दवाई ही नहीं मिलती । वहाँ पर नसबन्दी जबरदस्ती की गई लेकिन दवाई के नाम पर वहाँ एस्परो की गोली भी नहीं है

राव बीरेन्द्र सिंह: क्या इसको फ़ैमिली प्लानिंग में इस्तेमाल करते हैं ? (हंसी)

श्री दीप चन्द भाटिया: वह हस्पताल बाद ग़ाहखान के नाम से म ग़हूर है.....

श्री अध्यक्ष: आप सवाल पूछे ।

श्री दीप चन्द भाटिया: मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस हस्पताल में एस्परो की गोली तक नहीं है, क्या वहाँ नसबन्दी के लिए दवाईयां मौजूद होंगी ? मैं समझता हूँ नहीं होगी।

श्री मति डाक्टर कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय जरूर होगी। हम बजट के आधार पर होस्पिटल्ज को पैसा अलाट करते हैं, हिस्से के अनुसार उस हस्पताल को भी पैसा मिलेगा और मिलता है।

श्री मति भान्ति देवी: मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगी कि फ़ैमिली प्लानिंग के लिए इतना बड़ा स्टाफ जिसको कांग्रेस सरकार ने नियुक्त किया था कि आप्रें इन किए जाएं, इसमें से जो फालतू स्टाफ हो गया है उसको हटाने के लिए सरकार सोचेगी ? दूसरा सवाल भी मैं साथ ही पूछ लेती हूँ कि जो सरकारी कर्मचारी केवल आप्रें इन के भय से जिन्होंने स्कूल छोड़े या दफतर छोड़े उनको वेतन देने के बारे में सरकार सोचेगी ?

श्रीमति डाक्टर कमला वर्मा: फ़ैमिली प्लानिंग के लिए जो वर्कर लगाए गए थे, उनको पैसा सैन्ट्रल गवर्नमेंट दिया करती थी। जब उनकी परफार्मेंस ठीक नहीं निकली तो सैन्ट्रल गवर्नमेंट के आदेशानुसार उनको निकाल दिया गया। लेकिन फिर भी हमारी स्टेट ने फ़ैसला लिया है कि जो ऐसे व्यक्ति अन-एम्पलायड बैठे हैं, जैसे-जैसे हमारे नोटिस में आएं, उनको कहीं न कहीं

एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन सब को एडजस्ट किया जाना है, यह बात विचाराधीन है।

चौधरी राम किान: स्पीकर साहब, 105 बच्चों के यामर्दों के जबरदस्ती आपने इन किए गए हैं। क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि डिस्ट्रिक्टवाइज फिगर क्या हैं और उनके क्या-क्या नाम हैं ?

श्रीमति डाक्टर कमला वर्मा: इनके नाम मेरे पास है, लिस्ट बड़ी लम्बी है। माननीय सदस्यगण मेरे पास आकर देख लें। अगर मैं एक-एक नाम पढ़ूँ तो टाईम लगेगा।

स्वामी अग्निवेा: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नसबन्दी परिवार नियोजन से सम्बन्धित है। एक तरफ तो हम चाहते हैं। कि जनसंख्या घटे और दूसरी तरफ बाजारों में अलील साहित्य बिकता है जो परिवार नियोजन के रास्ते में रोड़ा अटकाता है। क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि नसबन्दी के साथ साथ अलील साहित्य क पढ़ने पर पाबन्दी लगाई जाएगी ?

श्रीमति डाक्टर कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, जहां तक अलील साहित्य का प्रश्न है, पब्लिक रिले इन डिपार्टमेंट वाले कुछ अच्छे प्रकार का साहित्य छपवाते हैं और उनकी कोशिश होती है कि अलील साहित्य को चैक किया जाए। जनता को शिक्षित करने के लिए सैन्टर ने नई योजना बनाई है कि हर एक पंचायत एक आदमी चुनकर, एक हजार आदमियों के बच्चों के पीछे

काम करेगा वह गांव में जाकर लोगों को हर प्रकार से शिक्षित करेगा कि इस तरह परिवार नियोजन के अन्दर सहायता हो सकती है।

श्री भले राम: क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि अब तक जिन लोगों के आपने पान हुए हैं, उनमें कितने आदमी 70 साल के बूढ़े और बूढ़ियां हैं (हंसी)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री हीरा नन्द आर्य: क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि जेलों में कितने आपने पान हुए हैं ?

श्रीमति डाक्टर कमला वर्मा: केवल डैटेन्यूज के बताऊं या दूसरों के (व्यवधान)।

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन): इसके लिए सैप्रेट नोटिस दें। (हंसी)

चौधरी पीर चन्द: क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि आपने पान करने से जो आदमी या औरतें बेकार हो गए हैं, कोई काम नहीं कर सकते, क्या उनके लिए पैं पान देने की कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन है ?

श्रीमति डाक्टर कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, पैं पान देने की कोई स्कीम नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल ऐड की स्कीम जरूर है।

चौधरी ई वर सिंह: मिनिस्टर साहबा ने अभी फरमाया कि एक हजार की बावादी के पीछे एक पंचायत से एक आदमी लेंगे स्वास्थ्य सम्बन्धी ट्रेनिंग देने के लिए। क्या मैं उनसे जान सकता हूँ कि ये आदमी कब से लिए जाएंगे और उन्हें लेने का प्रोसीजर क्या है ?

श्रीमति डाक्टर कमला वर्मा: मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य यह बात भूल गए हैं कि दो तारीख गांधी जयन्ती वाले दिन से यह योजना लागू कर दी गई है ?

चौधरी गंगा राम: अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के कानून के अनुसार कत्ल की सजा मौत होती है। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि एमरजेन्सी के दौरान आप्रै इन के नाम पर जिन कांग्रेसी आकाओं ने नौजवानों के कत्ल किए हैं क्या उन कांग्रेसी आकाओं के भी आप्रै इन करके उनको भी वही सजा देने के बारे में यह सरकार सोचेगी ? (विघ्न)

श्रीमति डाक्टर कमला वर्मा: यह काम कानून का है और कानून पूरी तरह लागू होने पर यह काम स्वयं हो जाएगा।

Deletion of the column from teh Girdawari

***110. Ch. Shiv Ram Verma:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to delete the column realltion to 'Kashat' from teh Khasra Girdawari and the name of the cultivator (tenanat); and

(b) whether a Committee was constituted for the purpose as referred to in part(a) above; if so, the details of the report of the aforesaid Committee togetherwith the time by which the action is likely to be taken thereon?

Ch. Chief Minister (Ch. Devi Lal):

(a) No.

(b) Yes. The Committee recommended that it is not advisable to abolish column of cultivation. This column, besides showing the cultivator's rights, also contains various other useful entries. No action to abolish the aforesaid column has been initiated.

चौधरी िव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, पूर्व इसके कि मैं अपना प्र न पूछूं मैं यह जानना चाहता हूं कि फैमिली प्लानिंग के प्र न पर कांग्रेसियों ने कोई पूरक प्र न क्यों नहीं पूछा ? (हंसी)

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी से मैंने यह प्र न पूछा था कि खसरा गिरदावरी में जो का त का खाना है, जिसमें का तकार का नाम लिखा जाता है, क्या सरकार उसको हटाने पर विचार करेगी। मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया नहीं। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां ऐसे कानून हैं जिनके अनुसार एक बार यदि गिरदउवरी

हो गई तो आपस में झगड़े भुरू हो जाते हैं। इस डर के कारण काफी जमीन खाली पड़ी रहती है। लोग डर के मारे उसे बौने को नहीं देते। बिना जमीन वाल को जमीन नहीं मिलती और जमीन वालों की पैदावार कम होती है। अगर खसरा गिरदावरी से का तकार का नाम हटाकर यह कर दिया जाए कि जिस तरह पट्टा लिखवा कर किराए पर मकान लिया जात है उसी प्रकार जमीन भी ली जा सकती हैं तो बेहतर होगा। इससे यह होगा कि एक तो वह मालिक के नाम रहेगी दूसरे बेजमीन को जमीन मिलेगी और दे 1 की पैदावार बढ़ेगी। क्या सरकार इस पर विचार करेंगी ?

चौधरी देवी लाल: मालिक अगर मौजूद न हो खुद का त न करता हो, और बहरहाल उसको किसी को जमीन देनी है तो उस का तकार का नाम खसरा गिरदावरी में न हो ऐसा नहीं हो सकता। किसी के नाम तो वह दर्ज होनी चाहिए। इसलिए इस कालम को हटाए जाने का वाल ही पैदा नहीं होता।

चौधरी िव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात कही थी कि जैसे मकान का भी खाना नहीं होता और वह किरायानामा लिखवाकर के किराये पर दे दिया जाता है इसी तरह अगर पट्टा लिखवा करके बेजमीनों को जमीन दे दी जाए तो पैदावार भी बढ़ेगी और झगड़े की बात भी खत्म हो जायेगी। (विध्न) मैं यही तो जानना चाहता हूं कि इस पर यदि सरकार विचार करें तो यह विचार समझ में आ जाएगा।

चौधरी देवी लाल: स्पीकर साहब, पट्टे का भी रिवाज है। चाहे पट्टे पर दें, चाहे हिस्से पर दें, का तकार का खाना तो रखना ही पड़ेगा।

चौधरी पीर चन्द: अध्यक्ष महोदय, चौधरी शिव राम वर्मा जी ने अभी फरमाया कि का त का खाना खत्म कर दिया जाए। मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि वे इस खाने को जो अब मुजारे हैं उनको मालिक बनाकर खत्म करेंगे या पहले खत्म कर देंगे ?

चौधरी देवी लाल: अभी नहीं करेंगे डरें नहीं।

Amount for the repair of School building in District Gurgaon

***132. Ch. Gajraj Ehadur Nagar:** Will the Minister for Education be pleased to state the amount that has been allocated to District Gurgaon during the current financial year for the repair of school buildings and the period during which the repairs to the badly affected schools in District Gurgaon are likely to be carried out?

शिक्षा मंत्री (कर्नल राव राम सिंह): सरकार स्कूलों के भवनों को मुरम्मत के लिए जिलावार पैसा ऐलोकेट नहीं करती। हर वर्ष लोक निर्माण विभाग एवं पंचायत विभाग को सरकारी भवनों की मुरम्मत के लिए एकमु त पैसा दिया जाता है। इस वर्ष

क्योंकि बाढ़ के कारण स्कूलों के भवनों को जो नुकसान हुआ है, उस कारण सरकार लोक निर्माण विभाग को अधिक पैसा एलोकेंट करने के लिए सोच रही है। लोक निर्माण विभाग को कह दिया गया है कि वह भीघाति गिघ स्कूलों के भवनों की मुरम्मत का काम पूरा करें। अतः मुरम्मत के काम को पूरा करने की निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती।

श्रीमति भान्ति देवी: अध्यक्ष महोदय, पी.डबल्यू.डी. को मुरम्मत के लिए सरकार तो राशि निर्धारित कर देती है लेकिन अभी तक देखा यह गया है कि वे कभी कश्ट ही नहीं करते कि जाकर देखें कि कौन सी छत गिरने वाली हैं, कहां मुरम्मत होनी है और कहां सफेदी की आवश्यकता है। इसलिए मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में उनको कड़े आदेश जारी करेगी ताकि वे इन बातों को देखा तो करें ?

कर्मल राव राम सिंह: स्पीकर साहब, फ्लड अफैक्टिड डिस्ट्रिक्टस में एक सर्वे की गई है। इसे ऐज्यूकेशन डिपार्टमेंट और पी.डबल्यू.डी. ने मिलकर किया है। अब तो यह फ्लड अफैक्टिड डिस्ट्रिक्टस में ही नहीं बल्कि सारे जिलों में कम्प्लीट हो चुकी है। पी.डबल्यू.डी. को इंडिकेट कर दिया गया है कि ये-ये बिल्डिंग्स हैं, जिसकी रिपेयर जल्दी से जल्दी करनी चाहिए।

चौधरी गजराज बहादुर नागर: मेरा सवाल, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह था कि स्कूल की बिल्डिंग्स जो इस

फ्लड से या दूसरी तरह से टूट गई है वे कब तक मुरम्मत होंगी। इसका जवाब अभी नहीं आया। इसलिए अब मैं मंत्री जी से दो बातें जानना चाहूंगा एक तो यह कि बिल्डिंग्ज की मुरम्मत कब तक भुरू हो जाएगी ? दूसरी बात यह है कि जिस तरह की बिल्डिंग्ज पी.डबल्यू.डी. बनाता है उससे मैं समझता हूं मिनिस्टर साहब बखूबी वाकिफ हैं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या सराकर कोई कमेटी या विजिलैन्स पी.डबल्यू.डी. के ठेकेदारान के ऊपर बिठाएगी ताकि वे पूरी तरह मुरम्मत का काम करें ?

कर्नल राव राम सिंह: स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर के इनिशियल सवाल का जवाब मैंने जूरा दे दिया था। इन्होंने पूछा था कि डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में बिल्डिंग्ज की कब तक मुरम्मत हो जाएगी ? मैंने कहा तारीख देना मुश्किल है लेकिन जल्दी से जल्दी रिपेयर की कार्यवाही भुरू कराई जाएगी। पैसे का प्रबन्ध किया जा रहा है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि कोई विजिलैन्स लगाई जाए, पी.डबल्यू.डी. बी.एंड.आर. के ऊपर इसका इस वक्त कोई विचार नहीं है। मेरा ख्याल है कि इसमें एक डैडिके इन की भी बात होती है। मैं सब माननीय सदस्यों से और गांव पंचायतों से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक पब्लिक इनवोल्वमेंट नहीं होगी, पब्लिक का डैडिके इन नहीं होगा तब तक यह बात ठीक नहीं हो सकती। जो काम हो रहा है, खास कर प्राईमरी स्कूलज की बिल्डिंग्ज का उसकी तरफ वे ध्यान दें, थोड़ा चौक रखे क्योंकि मैं समझता हूं हर चीज के ऊपर विजिलैन्स

बिठाना काम भुरू होने से पहले, यह कांफिडैन्स पैदा करने वाली बात नहीं है।

श्री मूल चन्द जैन: अध्यक्ष महोदय, सरकारी स्कूलों की मुरम्मत की समस्या हरियाणा में इतनी लम्बी चौड़ी हो गई है कि जितनी रकम सरकार इनकी मुरम्मत के लिए ईयरमार्क करती है वह बिल्कुल नाकाफी है। इसके पे े नजर मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार पंचायत, पंचायत समिति और मार्किट कमेटी को कानून में तरमीम करके यह सुझाव देगी कि वे सबसे पहले इन स्कूलों की मुरम्मत में हिस्सा लें ताकि स्कूल बिल्डिंग की मुरम्मत हो और बच्चे ठीक ढंग से बैठ सकें ?

कर्नल राव राम सिंह: जैसा कि मूल चन्द जैन जी ने अभी फरमाया है कि बिल्डिंगों की बड़ी भारी समस्या है। इस साल जो बजट एलोकेट हुआ है, वह तो पहले ही एलोकेट हो चुका है, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि फ्लड की वजह से जिन बिल्डिंगों को नुकसान हुआ है उनके लिए वह काफी नहीं है। फ्लड की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मांगा गया है, वह पैसा जब आयेगा तो उसमें से कुछ हिस्सा तो जरूर अलाट किया जायेगा। जहां तक मार्किटिंग बोर्ड का सम्बन्ध है उनसे पैसा ले कर लगाने का, उनसे भी इस वक्त पैसा नहीं ले सकते हैं। इसलिए अगर कोई सुझाव आयेगा तो मैं जरूर मार्किटिंग बोर्ड या मंत्री मंडल के सामने इस बात को पुट अप करूंगा।

श्री अध्यक्ष: मैं मेम्बर साहिबान से दरखास्त करूंगा कि सवाल पूछने वाले मैम्बरान बहुत ज्यादा है इसलिए सवाल छोटा करके पूछें ताकि ज्यादा से ज्यादा मेम्बरों को सवाल पूछने का मौका मिल सके।

चौधरी राम किान: क्या शिक्षा मंत्री महोदय, यह बताने का कश्ट करेंगे कि हरियाणा का 1/3 हिस्सा फलड की जद में आ गया है जिसके कारण स्कूलों की इमारतें बेकार हो गई हैं और जो लोग गांव में अपने प्राइवेट स्कूल चला रहे रहे थे, अब वे उनको चलाने में असमर्थ है, उनके पास कोई साधन नहीं है, सरकार का कोई विचार है कि जिन स्कूलों की बिल्डिंग हैं, स्ट्रैन्थ पूरी है, मैदान है, उनको टेक-ओवर कर लिया जाये ?

कर्मल राव राम सिंह: यह स्कीम अन्डर एग्जामीने ान हैं लेकिन मेरा विचार है कि फाइनेन् ाल इम्पलीके ान्ज इतनी गम्भीर होंगी कि सारे स्कूलों को टेक-ओवर करना ना मुमकीन हैं। वैसे यह मामला अन्डर एग्जामीने ान है।

चौधरी हरस्वरूप बूरा: मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेंगे कि जिन स्कूलों की मुरम्मत होनी जरूरी है और वहां पर बिल्डिंग फन्ड पड़ा हुआ है, क्या उस फंड को वही पर लगाने की इजाजत दे देंगे ताकि उन लोगों को सुविधा हो जाये ?

कर्नल राव राम सिंह: यह बहुत अच्छी सुजै आन है। अगर किसी स्कूल का बिल्डिंग फंड पड़ा हुआ है तो उस पर जरूर गौर करेंगे।

श्री गुलजार सिंह: मंत्री महोदय बताएंगे कि जो बिल्डिंग मुरम्मत कराने का तरीका है, इसमें बदनामी बहुत होती है, कई किस्म की बाते कही जाती है, कोई कहता है कि गबन हो गया, मेरा सवाल यह है कि पी.डबल्यू.डी. के थ्रू या पंचायत के थ्रू, कोई ऐसा तरीका मुरम्मत का नहीं निकाला जा सकता है जिससे पैसे की हेराफेरी न हो ?

कर्नल राव राम सिंह: जनता पार्टी ने सबसे पहले हेर फेर और भ्रष्टाचार को बन्द करने का प्रोग्राम बनाया है। उसी प्रोग्राम के तहत हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि बिल्डिंगों की मुरम्मत में कोई हेरा-फेरी या कर्पण न हो।

स्वामी आदित्यवे तः स्पीकर साहब, मेवात में बहुत से ऐसे स्कूल हैं, जहां पर बिल्डिंगों में अभी तक पानी भरा हुआ है और बच्चों के लिए बैठने के लिए भी प्रबन्ध नहीं है, कुछ ऐसी बिल्डिंगें हैं, जिनकी मुरम्मत होनी है, तो मैं मिनिस्टर साहब से निश्चित टाईम चाहता हूं कि कब तक मुरम्मत हो जाएगी ?

कर्नल राव राम सिंह: अभी-अभी मेरे पास खबर आई है कि स्कूलों की बिल्डिंगों की मुरम्मत शुरू हो चुकी है। पी.डबल्यू.डी. ने शुरू कर दी है। जहां तक मेवात के इलाकों का ताल्लुक

है, जिन इलाकों में अभी तक दो-दो और तीन-तीन फुट पानी भरा हुआ है, उनकी मुरम्मत तभी भुरु की जाएगी, जब पानी ड्रे आउट किया जाएगा। बाकी सारा काम भुरु है। जैसा कि पहले अर्ज किया है कि डेट आफ कम्प्लीशन का वक्त देना ना-मुमकिन है।

चौधरी लाल सिंह: मंत्री महोदय, यह बताने का कश्ट करेंगे कि जो पहले कांग्रेस सरकार थी, उसने बहुत सारी स्कूलों की बिलिडिंग का पैसा खाया है और वह बिलिडिंग अधूरी पड़ी हुई है, क्या उनके लिए भी कुछ किया जाएगा ? (हंसी)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, जो सब माउन्टेनियस एरियाज हैं जैसे कालका और नारायणगढ़, उनमें जितने भी स्कूल हैं, वे तमाम के तमाम लीक कर रहे हैं तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनकी मुरम्मत का सारा काम पी.डब्ल्यू.डी. के हवाले कर दिया गया है, अगर किया गया है तो क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट भी वाच करता है ?

कर्मल राव राम सिंह: मुरम्मत का जहां तक सवाल है। प्राइमरी स्कूल की मुरम्मत पंचायत विभाग करवाता है। प्राइमरी स्कूल से ऊपर के जो स्कूल हैं उनकी पी.डब्ल्यू.डी. करवाता है। जहां तक एजुकेशन डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, हमारे लोकल आफिसरज, बी.ई.ओ. हैडमास्टरज या दूसरे आफिसरज हैं, वे वाच

करते हैं बाकी कोई खास सैल नहीं हैं जो रिपेयर के बारे में सुपरविजन करें।

श्री लछमन सिंह: लेकिन उनकी मुरम्मत का जो काम होता है उसका डाटा तो अपनी नालेज के लिए रखते होंगे।

कर्नल राव राम सिंह: स्कूलों की रिपेयर का डाटा तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है। जैसे जैसे मुरम्मत के आर्डर दिए जाते हैं वे अपना काम भुरु कर देते हैं।

चौधरी देस राज: क्या मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेंगे कि हरियाणा में कितने स्कूल काबिले मुरम्मत हैं ?

कर्नल राव राम सिंह: हरियाणा को डिस्ट्रिक्टवाइज लिस्ट बना रखी है। 612 स्कूल हैं जिनकी अर्जेन्ट मुरम्मत की जरूरत है।

श्री मूल चन्द मंगला: मंत्री महोदय से मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि सरकारी बिल्डिंगों की हालत बहुत खराब है, केवल तीन सरकारी बिल्डिंगें हैं और पचास प्राइवेट बिल्डिंगें किराए पर स्कूलों के लिए ली हुई है, प्राइवेट स्कूल वाले उनकी मुरम्मत कराने के लिए तैयार नहीं है, उनकी हालत बड़ी खस्ता है, कड़ियां टूटी हुई हैं और सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगज की हालत भी तसल्लीबख्भा नहीं है, तो क्या सरकार उन बिल्डिंगज की मुरम्मत कराने के लिए तैयार है या उन प्राइवेट बिल्डिंगज को एक्वायर

करने के लिए तैयार है ? दूसरे क्या प्राइवेट स्कूल के मालिकों को मुरम्मत के लिए मजबूर करने के लिए तैयार है ?

श्री अध्यक्ष: आप छोटा सवाल किया करें।

श्री मूल चन्द मंगला: मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: आपने सवाल ही इतना लम्बा कर दिया, उसमें कसूर आपका है ? अब आप बैठिए आपको फिर मौका दिया जाएगा।

श्री रघुनाथ गोयल: मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि भाहरों में जो प्राइमरी स्कूल हैं वे पंचायतों को दिए हुए हैं, अगर वे नगरपालिकाओं को दे दिए जाएं तो कैसा रहेगा ? दूसरी बात यह है कि बहुत से ऐसे स्कूल हैं, जिनकी छतें गिरी हुई हैं, न किवाड़ है न कुछ है उनकी तरफ कब ध्यान दिया जाएगा ?

कर्मल राव राम सिंह: मेरा ख्याल है कि मैबर साहब ठीक तरह से समझ नहीं सके। पंचायतों को स्कूल नहीं दे रखे हैं। पंचायत महकमे के पास पी.डब्ल्यू.डी. का एक इंजीनियरिंग सैल होता है, क्योंकि स्कूल गांव में है इसलिए सिर्फ उनकी रिपैअर पंचायत का महकमा करता है स्कूल पंचायतों के पास नहीं है। जो भाहरों में स्कूल हैं, उनको म्युनिसिपल कमेटी को देने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

चौधरी ई वर सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेंगे कि हाई स्कूल तो सरकार ने पी.डब्ल्यू.डी. के अन्डर कर दिए लेकिन प्राइमरी स्कूल जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है उनको कब तक पी.डब्ल्यू.डी. के अन्डर ले लिया जाएगा ?

कर्नल राव राम सिंह: जितने भी स्कूल हैं, पी.डब्ल्यू.डी. टेकओवर करने को तैयार है, वह तो अपने चार्ज में लेना चाहती है लेकिन कई स्कूलों की बिल्डिंगों की हालत बहुत खराब है इसलिए पी.डब्ल्यू.डी. उनको फिलहाल टेकओवर करने को तैयार नहीं है। जैसे जैसे रिपेअर होती जाएगी तो पी.डब्ल्यू.डी. उन स्कूलों की बिल्डिंगे लेती जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता प्रोसैस जारी है।

श्री दीप चन्द भाटिया: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि फरीदाबाद में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा आमदनी वाला हिस्सा है वहां पर स्कूलों की बिल्डिंगज की हालत तो खराब है ही, लेकिन वहां पर बच्चों के लिए पीने के पानी का भी ठीक तरह से प्रबन्ध नहीं है, क्या वहां स्कूलों में सरकार नलके का प्रबन्ध कराने के लिए तैयार है ?

श्री अध्यक्ष: अब भाटिया साहब, बैठिए, क्वै चन आवर खत्म हो गया।

Declaration of Narwana as Backward area

***134. Sh. Shamsheer Singh:** Will the Minister for Social Welfare be pleased to state:-

(a) whether the erstwhile Punjab Government vide its notification No. WGII- (I)-61/30613, dated 13-12-1960 and No. 3530- SWII-62/16393, dated 6-8-62 declared Jind Sub-Division as Backward Area and that at that time Jind Sub-Division comprised of Jind and Narwana Tehsil;

(b) whether Narwana Tehsil was upgraded into a Sub-Division in 1964;

(c) whether it is a fact that vide Government Notification No. 3895- SK-174/10611 of 11/17-6-74 Jind Sub-Division only was declared Backward;

(d) whether it is fact that Narwana was left out because of inadvertance; and

(e) whether the Government intends to rectify the mis take and declare Narwana Sub-Division as Backward one?

समाज कल्याण मंत्री (श्री प्रीत सिंह):

(ए) जींद उप मण्डल जिसमें नरवाना तहसील भी सम्मिलित थी, को पिछड़ा क्षेत्र पंजाब सरकार के परिपत्र क्रमांक डब्ल्यू.जी. II-(1) - 61/30613, dated 13-12-1961 द्वारा घोशित किया गया था। क्रमांक डब्ल्यू.जी.(1)-61/30613, dated 13-12-1961 को कोई ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। परन्तु क्रमांक 3530 एस.डब्ल्यू. 0-2-62/16393 दिनांक 8-6-1962 द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। किन्तु एक परिपत्र क्रमांक

3530-5 डब्ल्यू.जी. 0-11-62/16343 दिनांक 6-8-1962 जारी किया गया था, जिसमें गुरदासपुर तथा अमृतसर जिले के कुछ ग्रामों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है।

(बी) हां।

(सी) कोई अधिसूचना क्रमांक 3895 स क - 1-74/10611 दिनांक 11/17-6-74 द्वारा जारी नहीं की गई हैं, अपितु इस नम्बर से एक परिपत्र जारी किया गया था जिसका सम्बन्ध जींद उप मण्डल को पिछड़ा घोषित करने से नहीं था, अपितु इस परिपत्र में जिला भिवानी की बवानी खेड़ा तहसील को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है।

(डी) मामले पर विचार कर लिया जाएगा।

(इ) इस समय नरवाना उप मण्डल को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने का कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है, तथापि इस प्र न पर विचार कर लिया जाएगा।

Selection Grade to B.A. B/Ed. and J.B.T Teachers

***141. Sh. Bhale Ram:** Will the Minister for Education be pleased to state the number of B.A., B.Ed. and J.B.T. teachers who were given the selection grade during the period from 1-11-69 to 1-9-77 in the State Separately?

शिक्षा मंत्री (कर्नल राव राम सिंह):

बी.ए.बी.एड. अध्यापक 968

जे.बी.टी. अध्यापक 3695

Distribution of Water

***147. Sh. Mool Chand Jain:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) the date on which the decision regarding the distribution of water between Pakistan and India, from which Haryana and Punjab are being its share, was arrived at;

(b) the share given to Haryana & Punjab out of the wter mentioned in part (a) above;

(c) the date and the manner in which the said water is being distributed between the State of Haryana and Punjab;

(d) whether the Haryana State is utilising its share;

(e) whether it is a fact that Haryana Government cannot get benefit from this water unless a long and wide canal is constructed through the Punjab Territory; and

(f) if so, the steps taken to construct the canal mentioned in part (e) abvoe?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह):

(ए) 19 सितम्बर, 1960। पूर्व तिथि 1-4-1960 में लागू।

(बी) हरियाणा 3.5 एम.ए.एफ.

पंजाब 3.5 एम.ए.एफ.

(सी) 1-11-1968 से अस्थाई आधार पर हरियाणा 35 प्रति एत, पंजाब 65 प्रति एत रावी ब्यास के फालतू पानी का सरहिन्द फीडर में प्रयोग के कारण भाखड़े में हुई बचत के अनुसार।

(डी) हां, केवल भागां 1 का ही प्रयोग किया जा रहा है।

(ई) हां, परन्तु वर्तमान भाखड़ा नहर द्वारा आंिक रूप में लाभ उपलब्ध है।

(एफ) हरियाणा में नहर पर कार्य पूर्ण गति पर है। पंजाब में नहर पर कार्य भीघ्र प्रारम्भ करने के लिए पंजाब सरकार तथा भारत सरकार के साथ बातचीत चल रही है।

J.B.T. Teachers

***63. Rao Dalip Singh:** Will the Minister for Education be pleased to state:-

(a) the total number of J.B.T. teachers serving in the Education Department on permanent and temporary basis, separately, in the State to-date;

(b) the total number of J.B.T. teachers out of those referred to in part (a) above who have not been confirmed for more than three years and five year separately in the State to-date; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to confirm the temporary J.B.T. teachers as referred to in part (a) above?

INTERIM REPLY

अर्धसरकारी पत्रांक 14143—फि I.III(7 फि I)77/33061

कर्नल राम सिंह

मंत्री

फि ाक्षा विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

अक्टूबर, 1977

विशय: तारांकित विधान सभा प्र न संख्या 63 राव दलीप सिंह, विधान सभा सदस्य, द्वारा पूछा गया जे.बी.टी. अध्यापकों के सम्बन्ध में ।

प्रिय ब्रिगेडियर साहब,

कृपया उपरोक्त विशय की ओर ध्यान दें ।

उक्त प्र न में पूछी गई सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि अस्थाई जे.बी.टी. अध्यापकों की नियुक्तियां फील्ड में मुख्य अध्यापकों/उपमण्डल शिक्षा अधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधिकारियों के स्तर पर की जाती हैं। कुछ समय पूर्व सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जो अध्यापक वर्ष 1973 की हड़ताल से पूर्व तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये थे और जिन्हें हड़ताल में भाग लेने के कारण सेवा मुक्त कर दिया गया था, उन्हें पुनः सेवा में ले लिया जाये। इस निर्णय के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा ऐसे अध्यापकों की नियुक्तियां की जा रही है। अतः यह सूचना जिला शिक्षा अधिकारियों, उपमण्डल शिक्षा अधिकारियों तथा मुख्याध्यापकों के अधीनस्थ कार्यालयों से एकत्रित की जानी है जो कि इस समय एकत्रित करना संभव नहीं है।

मैं आपका आभारी हूंगा यदि इस प्र न का उत्तर देने हेतु 2 मास का समय और प्रदान कर दिया जावे।

सादर,

ब्रिगेडियर रण सिंह

आपका

अध्यक्ष,

हस्ता

हरियाणा विधान सभा,

(राम सिंह)

चण्डीगढ़।

Running Capacity of water from the Canal System

***123. Ch. Birinder Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) the annual surplus irrigation water running capacity in M.A.F. available after cutting of supplies to the extent of 1700 cusecs capacity from the Bhakra Canal system to Rajasthan as a result of transferring Rajasthan areas to Sirhind Feeder;

(b) total capacity of carrying irrigation water annually in M.A.F. of the Bhakra Main Canal, and Nangal Hydel channel if the supplies were to run in full capacity throughout the year together with actual supplies running in M.A.F. during the last three years; and

(c) the annual running capacity of the existing Narwana Branch Links with Western Yamuna Canal, if the supplies were to run to the full capacity of the canal throughout the year in M.A.F. together with actual supplies running in M.A.F. during the last three years?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(ए) राजस्थान नहरों का भाखड़ा नहरों से सरहिन्द फीडर पर तबदील होने के कारण फालतू पानी की क्षमता 1.24 एम.ए.एफ. वार्षिक है।

(बी) भाखड़ा मेन लाईन के चलने की मूल क्षमता 9.125 एम.ए.एफ. है, परन्तु वास्तविक क्षमता 8.40 एम.ए.एफ. है। इस नहर में पिछले तीन वर्षों में वास्तविक सप्लाई 5.400, 6.795 और 6.468 एम.ए.एफ. चलती रही है। नंगल हैडल चैनल की क्षमता 9.125 एम.ए.एफ. है। इस नहर में पिछले तीन वर्षों में वास्तविक सप्लाई 8.229, 9.042 और 9.114 एम.ए.एफ. चलती रही है।

(सी) नरवाना ब्रांच करनाल लिंक की क्षमता 1.983 एम.ए.एफ. है। इस नहर में पिछले तीन वर्षों में वास्तविक सप्लाई 0.663, 0.704 और 0.734 एम.ए.एफ. चलती रही है।

Electric Connections Given to Agricultural Tubewells

***111. Ch. Shiv Ram Verma:** Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state:

(a) the number of electric connections given to agricultural tubewells in Karnal and Kurukshetra districts separately, during the period from 1st April[1977 to 30th June, 1977;

(b) the number of tubewells to which electric connections are likely to be given in the districts as referred to in part (a) above during the period from 1st July, 1977 to 30 September, 1977;

(c) the number of electric connection given for the improvement of 'Kallar' land out of those referred to in part (a) above; and

(d) the number of electric connections given to the tubewells installed on Kallar land out of those mentioned in part (b) above?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) 1 अप्रैल, 1977 से 30 जून, 1977 तक करनाल तथा कुरुक्षेत्र जिलों में क्रम 1: 819 और 628 कृषि नलकूपों को बिजली के कनेक्शन दिए गए थे।

(ख) जुलाई तथा अगस्त 1977 के दौरान 495 कृषि नलकूपों को जिला करनाल तथा 523 को जिला कुरुक्षेत्र में बिजली के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। मास सितम्बर, 1977 के दौरान 175 नलकूपों को जिला करनाल तथा 48 नलकूपों को जिला कुरुक्षेत्र में बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं।

(ग) वांछित सूचना इस प्रकार है:—

जिला	1-4-77 से 30-6-77 तक कल्लर क्षेत्र में दिये गये नलकूप कनेक्शनों की संख्या
करनाल	78

कुरुक्षेत्र	14
-------------	----

(घ) जुलाई और अगस्त, 1977 के दौरान करनाल जिला के कल्लर क्षेत्र में 147 नलकूपों तथा कुरुक्षेत्र जिला के कल्लर क्षेत्र में 20 नलकूपों को बिजली के कनेक्शन दिए गए। सितम्बर, 1977 में करनाल जिला के कल्लर क्षेत्र में 41 नलकूपों तथा कुरुक्षेत्र जिला के कल्लर क्षेत्र में 12 नलकूपों को बिजली के कनेक्शन दिए गए।

Development of 17 Gram Panchayats

***133. Ch. Gajraj Bahadur Nagar:** Will the Industries Minister be pleased to state whether there is any proposal to construct streets and to provide electricity, water sewerage and street lights to 17 Gram Panchayats included in Faridabad Administration?

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन): फरीदाबाद कम्पलैक्स प्रशासन के बनाते समय फरीदाबाद कम्पलैक्स में 16 ग्रामों की पंचायतें शामिल की गई थीं। जैसा कि फरीदाबाद कम्पलैक्स (विनियमन तथा विकास) अधिनियम 1971 की अनुसूची 11 में उल्लेखित है। इस प्रकार इन ग्राम पंचायतों की संख्या 16 है न कि 17। इस प्रश्न का उत्तर निम्नानुसार है:—

(क) गलियां / सड़कें

फरीदाबाद कम्पलैक्स प्र गासन द्वारा 13 ग्राम पंचायतों में गलियां / सड़कें पहले ही बना दी गई हैं। वर्ष 1977-78 के दौरान कम्पलैक्स प्र गासन की 3 ग्राम पंचायतों में गलियां / सड़कें बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) गलियों में प्रकाश (बिजली)

कम्पलैक्स प्र गासन द्वारा 10 ग्राम पंचायतों में पहले ही प्रकाश की व्यवस्था कर दी गई है और इस वर्ष के दौरान भोश 5 ग्राम पंचायतों की गलियों में प्रकाश की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

(ग) जल सप्लाई

इस समय कम्पलैक्स प्र गासन में 4 ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में जल सप्लाई स्कीम बनाई गई है।

(घ) मल निकास

जब तक जल सप्लाई स्कीम क्रियान्वित नहीं हो जाती तब तक ग्राम पंचायतों में मल निकास की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

***135. Sh. Shamsheer Singh:** Will the Minister for Finance be pleased to state:-

(a) the population of Narwana town at present; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to include Narwana Town in the grade of those cities where the Government employees are entitled to House Rent Allowance?

वित्त मंत्री (चौधरी सतबीर सिंह मलिक):

(क) 1971 की जनगणना के अनुसार नरवाना कस्बे की जनसंख्या 21319 थी। वर्तमान संख्या के यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) नहीं।

Enhancing the time of recess in the Schools

***142. Sh. Bhale Ram:** Will the Minister for Education be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that different timings of recess are being observed in the school i.e., of 15 minutes during the summer and of 30 minutes during the winter; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to enhance the time of recess?

शिक्षा मंत्री (कर्नल राव राम सिंह):

(क) जी हां, स्कूलों में विश्राम का समय भिन्न-भिन्न है, परन्तु एक पारी स्कूलों के लिए ग्रीष्म काल में विश्राम का समय 20 मिनट और भारद् ऋतु में विश्राम का समय 30 मिनट हैं फिर भी दो पारी स्कूलों में ग्रीष्मकाल में विश्राम का समय 15 मिनट है। भारद् ऋतु में अक्टूबर से नवम्बर तथा फरवरी से मार्च में विश्राम 20 मिनट को होता है तथा दिसम्बर से जनवरी तक केवल 10 मिनट का होता है क्योंकि दिन छोटे होते हैं।

(ख) जी नहीं।

Grievances Committee

***148. Sh. Mool Chand Jain:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that the Government has abolished the Grievances Committees set up at District and Sub-Divisional level in the State;

(b) whether it is also a fact that only the Legislators used to be non-official members of the said Committees, set up at the district level;

(c) whether the Government has received some representations from Legislators and other people against the abolition of the Grievances Committees; and

(d) if so, whether the Government intends to set up these Committees again; if so when?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल):

(क) हां।

(ख) राज्य के संसद सदस्य तथा विधायक इन विधायक समितियों के सरकारी सदस्य होते थे। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक स्तरीय जिला समिति में 10 गैर-सरकारी सदस्य तथा प्रत्येक उप-मण्डल समिति में 7 गैर सरकारी सदस्य होते थे।

(ग) कोई भी लिखित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

(घ) समितियां दोबारा गठित कर दी गई है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Out Door and Indoor Patients

27. Rao Dalip Singh: Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state:-

(a) the total number of out door and indoor patients treated in Civil Hospital Mahendergarh during the years 1975-75, 1976-77 to-date;

(b) the number of Doctors and staff sanctioned for the Hospital as referred to in part (a) above; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to appoint more senior doctors in the aforesaid Hospital keeping in view the increased number of Patients?

खाद्य एवं पूर्ति मंत्री (श्रीमति डाक्टर कमला वर्मा):

(ए) वित्त वर्ष अनुसार सूचना उपलब्ध नहीं है। कैलेण्डर वर्ष अनुसार सूचना नीचे दी जाती है:-

वर्ष	आऊट डोर मरीज	इन डोर मरीज
1975	103485	8030
1976	91890	7600
1977 (30 सितम्बर तक)	70183	5341
हस्पताल के लिए वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 के लिए डाक्टरों तथा अमले की संख्या एक सी थी जो कि निम्न प्रकार से थी:-		
(बी)	एच.सी.एम.एस.:-II डाक्टर सहायक दन्तक सर्जन नर्सिंग सिस्टर	2 1 1 4

	स्टाफ नर्सिंग	2
	फार्मसिस्ट	1
	प्रयोग ाला सहायक	1
	तहसील सफाई निरीक्षक	1
	रेडियोग्राफर	12
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	
(सी)	नहीं जी।	

**Amount Spent on purchase of Medicines for the Hospitals
in the State**

28. Rao Dalip Singh: Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state:-

(a) the districtwise total amount spent on purchase of medicines for the Hospitals in the State during the years 1975-76, 1976-77 to-date;

(b) whether the Government has received any complaint in connection with the selling of the medicines of the Hospitals;

(c) if so, the copies of the complaints as referred to in part (b) above be laid on the table of the House together with the action taken thereon.

(d) whether the Government has received any complaint regarding the non-availability of medicines in the Hospitals; and

(e) if the reply is in the affirmative the copies of the complaints be laid on the table of the House and the action taken thereon?

खाद्य एवं पूर्ति मंत्री (श्रीमति डाक्टर कमला वर्मा):

(ए)

		1975-1976	1976-1977	1977 (1-4-77 से 30-9-77 तक)
1	अम्बाला	576000	653000	284806
2	भिवानी	689046	746176	272177
3	गुड़गांव	600000	620000	600000
4	हिसार	935227	833048	382000
5	जीन्द	509755	625323	354131
6	करनाल	567510	632766	126318
7	कुरुक्षेत्र	656746	642050	67734

8	महेन्द्रगढ़	460506	508500	264850
9	रोहतक	722100	860799	257067
10	सिरसा	446085	478571	130915
11	सोनीपत	644847	654956	103363
	कुल जोड़	6807822	7255189	2843361

(बी) हां जी ।

(सी) एनैक्सचर 'ए' में संलग्न हैं ।

(डी) हां जी ।

(ई) एनैक्सचर 'बी' में संलग्न है ।

एनैक्सचर 'ए'

क्रम संख्या	परिवाद का संक्षिप्त परिचय	की गई कार्यवाही
1	एक गुप्त परिवाद प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था कि डा० छतर सिंह चिकित्सा अधिकारी, पी.एच.सी. बावल की दवाईयों को सुन्दर मैडीकल हाल, बावल को बेचता है।	इस परिवाद की जांच की गई है तथा इसे निराधार पाया गया है।
2	एक गुप्त रिपोर्ट डा. रामभज रहेजा, चिकित्सा अधिकारी रुरल डिस्पेंसरी, डाढरथ, जिला जीन्द के बारे में प्राप्त हुई कि यह डाक्टर सरकारी दवाईयों को प्राईवेट पार्टियों को बेचता है।	इस परिवाद की जांच की गई है तथा इसे निराधार पाया गया है।

3	<p>बवानी खेड़ा के निवासियों ने यह शिकायत की थी कि डा. गुरप्रीत सिंह, चिकित्सा अधिकारी, रूरल डिस्पेंसरी, बवानी खेड़ा इन्जैव न बेचता है।</p>	<p>यह शिकायत दिनांक 26-9-77 को प्राप्त हुई थी तथा दिनांक 12-7-77 को जांच एवं रिपोर्ट हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भिवानी को भेजी गई थी। उनकी जांच रिपोर्ट अभी तक प्रतीक्षित है।</p>
4	<p>एक परिवार श्री राम सिंह तथा अन्य व्यक्तियों से प्राप्त हुआ कि प्राइवेट डाक्टर कि गोरी लाल को सिविल हस्पताल हिसार के कमचारी दवाईयों बेचते हैं।</p>	<p>यह मामला अभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के जांच अधीन है।</p>
5	<p>रिवाड़ी निवासियों से एक शिकायत प्राप्त हुई कि श्री सोहन सिंह, फार्मसिस्ट, सिविल हस्पताल, रिवाड़ी की दवाईयां बाजार में बेचता है।</p>	<p>इस शिकायत की जांच की गई थी तथा निराधार पाई गई।</p>

6	डा० कालरा तथा श्री महेन्द्र सिंह, फामसिस्ट, रिवाड़ी द्वारा दवाईयां बेचने के बारे श्री राम किान, रिवाड़ी निवासी की िाकायत।	इस परिवाद का परिवादी उपलब्ध नहीं हो सका फिर भी इस मामले में जांच की जा रही है।
7	डा० गेरा तथा डा० गुप्ता, सिविल हस्पताल, रिवाड़ी के विरुद्ध दवाईयां बेचने के बारे श्री राम किान द्वारा िाकायत।	इस परिवाद का परिवादी उपलब्ध नहीं हो सका, फिर भी इस मामले में जांच की जा रही है।
8	श्री अजय कुमार यादव सम्पूर्ण क्रान्ति संघ, रेलवे रोड़, रिवाड़ी का दवाईयां बेचने के लिए डा० क मीरी लाल, डा० गेरा तथा नर्सिंग सिस्टर मिश्रा के विरुद्ध परिवाद।	इस परिवाद की निदे ालय स्तर पर जांच की जा रही है।
9	श्री दु यन्त कुमार महामंत्री रिवाड़ी क्षेत्र का डा० क मीरी लाल, डा० गेरा तथा नर्सिंग सिस्टर मिश्रा के विरुद्ध दवाईयां बेचने के बारे में परिवाद।	इस परिवाद की निदे ालय स्तर पर जांच की जा रही है।

एनैक्सचर 'बी'

क्रम संख्या	संक्षिप्त परिवाद	की गई कार्यवाही
1	<p>एक नोट सिंचाई एवं उद्योग मंत्री महोदय का स्वास्थ्य मंत्री महोया के माध्यम से 8-9-77 को प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था कि रूरल डिसपेंसरी, पाली (जिला हिसार) में औशधियां नहीं हैं तथा औशधियां सप्लाई करने के बारे आदे । दिये जायें ।</p>	<p>मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस मामले में छानबीन करने तथा की गई कार्यवाही से सूचित करने बारे कह दिया गया है ।</p>
2	<p>एक परिवाद श्री प्यारे लाल और श्री िव चन्द, पंचायत मैम्बर गोरी वाला की ओर से स्वास्थ्य मंत्री महोदया के माध्यम से प्राप्त हुआ कि रूरल डिसपेंसरी, गोरीवाला में</p>	<p>आवक औशधियों की सप्लाई का प्रबन्ध कर दिया गया है ।</p>

	दवाईयां उपलब्ध नहीं हैं।	
3	श्री बाबू सिंह, गांव कोट द्वारा एक परिवाद श्री के.एल. पोसवाल, एम.एल.ए. के माध्यम से प्राप्त हुआ कि रूरल डिसपैंसरी, कोट (जिला अम्बाला) में दवाईयां उपलब्ध नहीं है।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अम्बाला को इस मामले में छानबीन करने तथा की गई कार्यवाही से सूचित करने बारे कह दिया गया है।
4	गांव समैन (हिसार) के निवासियों द्वारा मुख्य मंत्री / स्वास्थ्य मंत्री महोदया के माध्यम से एक परिवाद प्राप्त हुआ है जिसमें लिखा गया है कि रूरल डिसपैंसरी, समैन में दवाईयां नहीं मिलती।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हिसार को इस मामले में छानबीन करने तथा की गई कार्यवाही से सूचित करने बारे कह दिया गया है।
5	श्री कंवर अबदल खान द्वारा पटौदी में दवाईयां उपलब्ध न होने बारे परिवाद।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिनांक 5-10-77 को कहा गया है कि वह इस मामले को ध्यान पूर्वक देखें तथा की गई कार्यवाही से निदेशालय को

		सूचित करें।
6	<p>श्री चन्द्र प्रकाश, एडवोकेट, झज्जर (रोहतक) ने शिकायत की थी कि जनरल हस्पताल, झज्जर में पट्टियां तथा दवाईयां नहीं हैं। यह शिकायत केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय को सम्बोधित थी तथा इसकी एक प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी रोहतक को प्राप्त हुई थी।</p>	<p>इस मामले में निदेशालय स्तर पर जांच की गई थी। इस जांच के दौरान यह पाया गया कि दिनांक 20-6-77 को सिविल अस्पताल, झज्जर में पट्टियां उपलब्ध नहीं थी। परन्तु दिनांक 23-6-77 को कश्चि संस्था में सप्लाई प्राप्त हो गई थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि वे कृपया सुनिश्चित करें कि इन संस्थाओं में आम प्रयोग में आने वाली सभी औषधियां तथा पट्टियां उपलब्ध हों।</p>

सेवा में,

श्री मान चीफ मैडिकल आफिसर,

नारनौल (महेन्द्रगढ़)

विशय: श्री गणे दत्त कम्पाउंडर का डा. छोजेड़ के साथ गठजोड़ करके मनमानी करना और गरीब जनता की जेबें काटना।

श्रीमान् जी,

हम बावल निवासी आपका ध्यान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बावल में मुख्य अस्पताल का विवरण भेज रहे हैं। आता है कि आप सच्चाई का पता लगाकर उचित कदम उठायेंगे।

1. श्री गणे दत्त ने एक बहन कृष्ण गुप्ता ए.एन.एम को बताया हुआ है कि जोकि हर इन्चार्ज के हवाले करके गर्भपात गलत कंवारी लड़कियों के कराते है हर डिलिवरी केस को कृष्णा ही देखती है और उन्हें भय देकर बच्चा उल्टा बता के डा. छोजेड़ को मन मांगे पैसे दिलाती हैं। ये आप प्रा.स्वा. केन्द्र मे काम कर रही दूसरी ए.एन.एम. से पूछ सकते हैं।

2. कृष्ण गुप्ता ए.एन.एम. को सबसे ज्यादा बिना हिसाब के छुट्टियां मिलती हैं जोकि आप स्वयं देख सकते हैं। केवल हाजरी रजिस्टर में लिखी जाती है जिनका कोई हिसाब नहीं है। ये आप स्वयं देख सकते हैं कि दिनांक 16-5-77 से 20-5-77

तक सी.एल. लिखी हैं परन्तु काटी नहीं गई इसी प्रकार सारे साल होता है।

3. जो भी दवाईयां केन्द्र में आती है वे सब सुन्दर मैडिकल हाल बावल में श्री गणे । दत्त बेचते हैं और डा. छोजेड़ को हिस्सा देते है। खर्चा परिवार नियोजन के केंसों पर डाले जाते हैं। ये रिकार्ड देख सकते है।

4. दिनांक 30-6-77 को एक औरत महादेई पत्नी श्री रत्न लाल ग्राम इकबाहीमपुर से आई थी उसके दो महीने का गर्भ था श्री गणे । दत्त ने 20 रूपये लिए एक इंजैव । न डा. जी. नोन जो हस्पताल का होता है लगाया और कहा कि अगर साफ नहीं होता तो 200 रूपये ले आना डा. से करवा दूंगा ये आप अचानक पूछ सकते हैं।

5. डा. छोजेड़ गणे । दत्त, कृष्ण गुप्ता के घरों में दो साल से हस्पताल का सामान इस्तेमाल हो रहा है। जैसे पंखा, रेडियो, स्टूल, कुर्सियां, चादर, कम्बल, डोलियां आदि जबकि सरकारी सामान घरों मे इस्तेमाल करना जुर्म है। ये आप स्वयं देख सकते है।

6. श्री गणे । दत्त की दो लड़कियों जिनके नाम पर सिंडीकेट बावल में खाता खुला हुआ है और 8.00 रूपये प्रतिदिन जमा होते है। हमारे विचार से छोटा कर्मचारी 8.00 रूपये रोजाना

जमा नहीं करवा सकता और इनकी ईमानदारी उनके खाते से जान सकते हैं।

(7) इनके इंचार्ज बनने के बाद देखा जाये कि इन्होंने तथा श्री गणे । दत्त ने कितनी झूठी रसीदे बनाकर झूठे बिल लिये है जो इनके पास सामान भी नहीं है वे भी आप रजिस्टर से व सामान देखकर जान सकते है।

(8) किसी भी स्टाफ मेंबर की अगर आप अलग अलग इन्कवारी करें तो और बातें मिल सकती है। कि इन तीनों ने स्टाफ में क्या वातावरण बना रखा है और कहते है कि एक एक करके सीधे करेंगे। और हम तीनों एक ही रहेंगे।

(7) डॉ. छोजेड़ प्राइवेट प्रैक्टिस करता है और दिन दहाड़े दुनियां को लूटता है जबकि वह सरकार से एन.पी.ए. भी लेता है। इसका सबूत इसके घर पर एक चमड़े का बैग है जिसका रंग काला है उसमें तमाम दवाई हस्पताल की है। जिसके पैसे लिये जाते है तथा हिस्सा बांटा जाता है तथा इनकी रसीदे देखी जाये।

कृपया करके इस प्रार्थना पत्र पर गम्भीरता से विचार करने का कशअ करें तथा इसकी इन्कवायरी चीफ मैडिकल आफिसर स्वयं ही करे।

आदर सहित,

भवदीय,

दिनांक

(एक समाज सेवक)

सेवा में,

श्रीमान हैलथ मिनिस्टर/मुख्य मंत्री साहिब जी,
हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन यह है कि हमारे ब्लाक में 10-10 गांवों के खिलाफ बहुत ही हवा उड़ रही है। मैंने कई गांवों में जाकर कर्मचारियों से बातचीत कीं बातचीत से पता चला है कि प्रत्येक कांग्रेस के खिलाफ निम्नलिखित कारणों से है तथा इन हल्कों में जो भी सरकारी मुलाजम है।

1-हद से ज्यादा रिक्त खोर महकमों के अलावा आपके महकमे से संबंध रखते मुलाजिम जो गरीब जनता से ज्यादाती करते हैं। उनका मैं ब्यान करता हूं:-

राजोन्द के हस्पताल के डाक्टर को रंगे हाथ पकड़ा गया था लेकिन उनके साथ सिवाए ट्रांसफर के और कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसका जनता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। अब भी वहां जो डॉ. है वे अपनी मानमानी करता है। सफ़ीदों हस्पताल में सीधे ही अंधेरगर्दी है किसी गरीब को हस्पताल से दवाई नहीं मिलती। डा. साहब मंहगी से मंहगी दवाई मरीज को लिख देते हैं जोकि गरीब नहीं खरीद सकते। डॉ. साहबों का

कैमिस्टों से मेलजोल है जिससे कैमिस्ट अच्छा लाभ उठा रहे है और गरीब मरीज को मजबूर होकर प्राईवेट डाक्टरों के पास जाना पड़ता है। हस्पताल की बिल्डिंग तो बहुत बढ़िया है लेकिन वहां का डा. मरीजों से सीधे मुंह बात ही नहीं करता। एमरजेंसी केस के लिये बाहर ले जाने वालों से भी बुरा व्यवहार होता है और वहां तो कईयों से ये सुना गया है कि इस डॉ का किसी मिनिस्टर से मेल जोल है या ये हैल्थ मिनिस्टर का खास आदमी है। इसके उपरांत डाढरथ की रुरल डिसपेंसरी वालों का बहुत ही बरा हाल है वहां डा. रहेजा ओर कम्पाउडर औम प्रका ।। कम्पाउडर तो गौरी भांकर एम.एल.ए. का रि तेदार है और कम्पाउडर किसी डी. सी. का रि तेदार है। इन्होंने तो इतनी अंधेर गर्दी मचाई है कि जनता दुहाई मचाती है। इन दोनों ने गांव के पांच दस आदमी जो किस अच्छी कंडी ान मे है और 5-7 गुण्डा टाईप आदमी अपने हाथ मे कर रखे है तथा गरीब जनता का कतरा कतरा खून चूस रहे हैं सरे आम मरीजों से इलाज के पैसे लिये जाते है और हस्पताल मे फरोखत हुई दवाईया इसी गांव के एक दुकानदार सेठ मांगे राम पुत्र टेक चंदर के पासदे दी जाती है और फिर मरीजों को मजबूर करके इस दुकान से दवाईयां खरीदने को कहा जाता है। गरीब मरीज मांगे राम दुकान मे दवाईया खरीदने को कहा जाता है ओर कई बचारे गरीब मरीज महंगी दवाई न खरीद सकसते मे तड़पकर रह जाता है। इस बात पर डाढरथ के नजदीक के 5-7 गांव अति दुखी है और प्रत्येक ये कहता है ऐसी कांग्रेस को वोट मत दो जिसके कर्मचारी गरीब जनता पर इतनी जुल्म

ढाते है लगभग एक हजार वोट जो कांग्रेस के लिये बिलकुल पक्की थी आप जनता पार्टी को जीताने की कोशिश में है जिसका कारण सिर्फ एक है आपके कर्मचारियों द्वारा अंधेरगर्दी और गरीब पर अनर्थ जुल्म।

डा. रहेजा की गरीब जनता ने कई बार कम्प्लेंट की पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। डायरेक्टर से सी.एम.ओ. को लिख देता है और सी.एम.ओ. जो जींद में है उनके बारे में बहुत आदमी जानते हैं कि लालची टटू है। कई लोग कहते हैं कि सी.एम.सी. से प्रत्येक डाक्टर से (जो जींद से बाहर है) 100-200 रुपये महीना बांध रखा है। इसलिये वो किसी डा. से जायज कार्यवाही नहीं करता। आपसे निवेदन है कि अगर अब भी तुरन्त कार्यवाही तो गरीब न जानता की कुछ तसल्ली हो जाये। आशा है कि आपकी कोई कार्यवाही से इस ब्लॉक के नुमायदे चौधरी जसवंत सिंह को वोट मिल जायें मुझे पूर्ण आशा है। नहीं तो आप को यहां से वोटों की कोई आशा नहीं है।

नोट:- विरोधी पार्टी में बातें उछाल रही हैं नसबन्दी के दिनों में डा. रहेजा हर ओपरेशन करवाने वाले से 5 प्रतिशत बिल्डिंग फंड कटवाया और उसकी रसीद किसी को भी नहीं दी गई इस बात की बहुत चर्चा है।

धन्यवाद

दुखी गरीब जनता और एक कांग्रेसी वर्कर

(ढाढरथ जींद)

कापी टू, हैल्थ मिनिस्ट

कापी टू, चीफ मिनिस्ट

कापी टू, निदे ाक

सेवा में,

श्रीमान चीफ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी साहिब,

बवानी खेड़ा हरियाणा।

मान्यवर महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम बवानी खेड़ा के निवासी आपका ध्यान बवानीखेड़ा के उस हिस्से की तरफ मे दिलाना चाहते है जहां भ्रष्टता और रि वतखोरी जोरो से चल रही है।

सविनय निवेदन है कि हमारे ग्राम बवानीखेड़ा के सरकार अस्पताल का डाक्टर सरदार जी भ्रष्ट और रि वत खोर है। जो मरीज हस्पताल मे दवाई लेने के लिये जाता है तो यह ठीक तरह से मरीज की देखभाल नही करता और 2- या 3 रूपये प्रति टीका लेता है ? पूछने पर बताता है कि सरकार किसी भी प्रकार का टीका नही भेजती । कहता है कि ये टीके मैंने घर

लाकर रखे हुए है। इनका 2 रूपये प्रति टीका लगेगा और यदि बाजार से लगावाओं तो 2.50 रूपये टीका पड़ेगा।

अतः गांव के भोले भाले ग्रामीण इसकी बातों में आकर टीके लगवा लेते हैं। यहां तक कि यह एक मरीज को 3 या चार टीकों में ही स्वास्थ्य ही नहीं करता बल्कि एक एक मरीज को दस दस टीकों में होना पड़ता है। गांव की जनता के लिये सरकारी और प्राईवेट अस्पताल में कोई फर्क नहीं है। गांव की जनता बहुत परे जान है कि मलेरिया का मौसम है और सरकार टीके नहीं भेजती। यदि सरकार टीक भेजती है तो यह डाक्टर बेचता क्यों है ? दो प्रार्थना पत्र हमने चीफ मैडिकल आफिसर भिवानी भेजी है मगर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः हम बवानी खेड़ा निवासी आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस ओर भी ध्यान दें।

हम सब,

बवानी खेड़ा

निवासी

Copy of the letter No. Nill dated 11/7/77 from Shri Ram Sing and others to Health Minister Haryana, Chandigarh (Hissar).

With due respect we the residents of Mahabir Colony Hissar, beg to submit as under:-

That there is a doctor named Kishori Lal, in our Mohalla Mahabir Colony, Hisar. He tells us that he is an employee in the Civil Hospital at Hisar, and says that he purchases medicines from the Civil Hospital Hisar. He sells the medicines to the needed persons.

That we have come to know that his man is in the Civil Hospital at Hisar and he issues slips to the outdoor patients. He says that he gets some medicines free of cost to give to the poor for their treatment.

That this doctor keeps with him some badmash whose names are 1. Surjit Lal Saini and 2. Hari Sing Sardar. These persons used to take drink in the evening time and do some nuisance.

This Mahabir Colony is populated by the poor men. The poor men of this colony are very much harassed at the hand of this doctor named Kishori Lal.

It is therefore, humbly prayed that immediate enquiry be made against this doctor and he may be dealt accordingly.

It will be not of place to say that Shri Ram Singh Mistri of the Railway department was beaten by him along with his two badmashes. There are some blows on Ram Singh, and Mistri is also in bed in the Civil Hospital, Hisar.

As Dr. Kishori Lal is in Civil Hospital, so no action taken so far against Dr. Kishori Lal noted above.

Hoping to be favoured soon.

DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES HARYANA

Enorsement No. 27/215-3EIII-77/3793 dated
Chandigarh 31-8-77

A copy is forwarded to the Chief Medical Officer,
Hisar with request that he should submit report after
investigating the matter.

Sd/-

Dy. State Drugs controller,
for State Drugs Controller, Haryana

सेवा में,

आदरणीय मुख्य मंत्री,

हरियाणा राज्य, चण्डीगढ़ ।

विशय:- सिविल हस्पताल, रिवाड़ी के मुख्य चिकित्सक श्री नित्थी
नंद गेरा फार्मासिस्ट श्री सोहन सिंह तथा स्टोर इंचार्ज
श्री गोयल की अकुशलता तथा अकर्मिता तथा इन
कर्मचारियों की भीष्म बदली करने की प्रार्थना ।

आदरणीय महोदय,

हम रिवाड़ी (जिला महेन्द्रगढ़) के निवासी जिनके
हस्ताक्षर नीचे दिये हैं सादर निवेदन करते हैं कि सिविल हस्पताल,

रिवाड़ी के निम्नलिखित कर्मचारियों ने आपातकालीन स्थिति के दौरान तगि इस समय भी ऐसा आंतक जनता के अंदर फैला हुआ है जिससे अब यह डर पैदा हो गया है कि अगर इन कर्मचारियों का जल्दी से जल्दी स्थानान्तरण नहीं किया गया तो एक रोज इस पिछड़े इलाके से सरकार का नाम हमें ग के लिये खत्म हो जायेगा और जनता में विद्रोह की भावना जागृत हो जायेगी अतः इस मामले में अति भीघ्न कार्यवाही करने की आव यकता है। और सरकार चाहे तो इन कर्मचारियों को स्थानान्तरण करने के बाद इन कर्मचारियों की जांच पड़ताल करें तो सारे तथ्य सामने आ जायेंगे।

1-श्री निथा नन्द गेरा मुख्य चिकित्सा डाक्टर ने आपत स्थिति के दौरान जबरन नसबंदी अभियान में खुल्म खुल्ला काम करके काफी रूपया कमाया। यही डाक्टर है जिसने 70 वर्ष के बूढ़ों को 40 वर्ष लिखकर जबरन नसबंदी की। दूसरे इसने अपने बहुत से चाहने वालों का 'पै गब में भाकर' बताकर झूठा सर्टीफिकेट बनाकर दे दिया और हजारों रूपया कमाया दूसरी ओर उनके केस नाजायज होते हुये भी नसबंदी न की गई अकु गलता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा, आज से 15 दिन पहले एक रेलवे के कर्मचारी श्री दुर्गा प्रसाद की हाथ की उंगली टूट गई थी उसके हाथ का उसी समय पलस्तर नहीं किया गया और उसके आदमियों से 250 रूपये मांगा गया और रेलवे कर्मचारी के न देने पर उसके हाथ की उंगलियों को बराबर न कर वैसे ही पलस्तर

कर दिया गया। यह गरीब कर्मचारी दिल्ली जाकर अपनी उंगली का ठीक पलस्तर करवा सका इसका खुला सबूत आज भी हमारे पास है।

यह डाक्टर किस तरह गरीब जनता का खून चूसता है और पैसा कमाता है यह अचानक छापा मार कर देखा जा सकता है। श्री सोहन लाल फार्मासिस्ट एक ओर हमारी सरकार रिवाड़ी हस्पताल को सब से ज्यादा दवाई का कोटा देती है पर यह सब काफी ज्यादा दवाइयों को बाजार मे बेचकर ऐसा अभाव पैदा कर देता है कि आम मरीज यह समझता है कि सरकार इस हस्पताल के लिये कुछ नहीं। यह भाख्स सवेरे आठ बजे दवाइयों का थैला लेकर बाजार मे निकलता है और हमे 11 10 बजे लौटता है जबकि हस्पताल का समय 8 बजे का है। आगे यह मरीजों की एंटीरेविक इंजेक्शन लगाने मे ज्यादा दिलचस्पी लेता है क्योंकि बदले मे उसको काफी रकम मिल जाती है। तीसरे यह भाख्स यहीं रिवाड़ी का रहने वाला है और इसे इसी हस्पताल के तकरीबन 6 साल हो गये है अतः इसको यहां से तबदील कर दिया जाये तो जनता को काफी राहत मिलेगी। श्री गोयर स्टोर इंचार्ज यह भाख्स डा. गेरा के साथ मिलकर पेसा कमाने मे बड़ा माहिर है। अच्छे से अच्छा सामान को कंडम बनाकर उसे बेचकर तथा ऊपर के मैडीकल अधिकारियों के पास तोहफे भिजवा कर किसी तरह पैसा पैदा करता है। यह भाख्स अच्छी तरह जानता है। अगर इसके स्टाफ की जांच पड़ताल की जाये तो लाखों का घोटाला सामने

आयेगा और पता लगेगा कि जनता के माल को कितनी बेरहमी के साथ हड़प किया जाता है ।

अतः हमारी आपसे प्रार्थना है कि इन उपरोक्त कर्मचारियों का भीघ्र यहां से स्थानान्तरण किया जाये और उनकी जगह से अन्य कर्मचारियों को भेजकर इस इलाके की जनता का आतंक दूर करके इस अस्पताल की नई बिल्डिंग की भांभा को चार चांद लगा दें ताकि जनता को वि वास फिर से अपनी सरकार मे पैदा हो जाये । आपकी इस कृपा के लिये हम सब साथ रिवाड़ी भाहर आपका आभारी रहेगा ।

हम आपके भाहर मे दुःखी
जनता हस्ताक्षरित निवासी
रिवाड़ी

नं. 1 से लेकर 277 तक

इसकी प्रतिययां निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा भीघ्र कार्यवाही के लिये भेजी जाती है ।

1-श्री राजनारायण जी, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री, नई दिल्ली ।

To

The Chief Minsiter,

Haryana, Chandigarh,

Sir,

I wish to bring to your notice extreme degree of corruption at Narnaul in Health Department.

1. Dr. Kashmiri Lal, Dr. Kalra, Dr. Gupta, calls every Medical Officer and other officers of the Distt. Headquarters for playing cards every evening or nights with high stakes. The winning money goes to Dr. Kashmiri Lal whether he wins or losses.
2. Because of this medical officers absent themselves from duty without being marked absent. Notable example are Dr. Amalok Sing who remained absent from duty for about two to three months off and on during the period form Dec. 1976 to April, 1977, but was marked present. However, family planning programme of consent of the operated cases record will reveal his absence from duty. Similarly Dr. B.S. Chauhan also remained absence but was present in the register. This will be proved by the casualty handing over and taking over registers and nigh report register maintained by casualty medical officers.
3. Dr. S.S. Kalra injects pethidine; compose injections on the accuse of heart attack. In fact he is addict and taken eight to ten injections daily. These injections are injected by Shri Mohinder Singh Pharmacist or Sister Krishna. Sh. Mohinder holds the charge of the medicine store of the Hospital. No. account is kept of the injections given to Dr. Kalra.

4. Therefore Dr. Kalra cannot check Shri Mohinder Singh Pharmacist who is selling Hospital medicine. The ward patients and the outdoor patients are getting no medicines from the Hospital.
5. About three thousand injection of Pethidine were purchased by the Chief Medical Officer, Narnaul about six months ago. Now they have been consumed in very short time. When compared to previous list, because Dr. Kalra is consuming these injection. Again fresh orders for the injections are being placed by the Chief Medical Officer Dr. Kashmiri Lal who is practising Physician at Delhi.
6. To help the store keeper and Sh. Mohinder Pharmacist to manipulate in corrupt distribution. All the indents are made by Medical officer. The practice of the indenting sections or authorities to write the indents have been given up as was approved by the Government.
7. Dr. Kalra is setting a very example by taking money from the patients see in his house and does not deposit in the Government treasury. He cannot take money or see the cases in our that Dr. Kashmiri Lal and Dr. Kalra are very bad examples and encourage corruption by junior officers. Therefore they should be trapped while taking money so that others may learn a lesson. The records mentioned above also should be impounded immediately, so that, no charges can be made in them.

Please oblige by immediate action.

Yours sincerely,

Ram Kishan.

Copy to Sh. Charan Singh (Home Minister) Govt. of India, New Delhi.

Copy to Sh. Raj Narain (Minister of Health and Family Welfare) Government of India, New Delhi.

Copy of Commissioner of Health, Haryana (Chandigarh) for information and necessary action.

Sh. Morarji Desai,

Hon'ble Prime Minister of India, Delhi

Sh. Raj Narain,

Hon'ble Health Minister, Delhi

Ch. Devi Lal,

Hon'ble Chief Minister, Haryana

Hon'ble Minister of Health, Haryana

Subject:- Mismanagement and mal treatment in Civil Hospital, Rewari (Haryana).

This is to our great sorrow and surprise that inspite of bring the facts that there is no proper arrangement or proper medical facilities in the Civil Hospital, Rewari and no efficient doctors and nurse are working and medicines are not supplied to the patients. Dr. Gera and Dr. Gupta about whom the people of Rewari and its surrounding area had very well brought into the notice of the Centre and State Govnerment about their inefficiency, mismanagement, sale of medicines in the market, mal treatment with the pubic, but the Government has not so far given any consideration ot these mass difficulties and towards increasing corruption and mis managements in the Hospital which is matter of great dis appointemnt by the Janta Government who made promises on the Public platforms so may times.

The District Red Cros Society, Narnaul has provided an ambulance car to the Civil Hospital Rewari, which workds under the supervision of Dr. Gera S.M.O. It is a matter of great surprise that the meter of the vehicle always remains out of order and the driver of the vehicle charges from the vehicle at his own accord. The vehicle is also been made available on the persons who pay them more and not to needy. The Government has provided this vehicle for the benefit and facility to the needy patient byt unluckily these rouges had made it their success of income. The vehicle may be raided surprisely and thorough and through enquiry into its working may be and income be made and all those ivelved by tried as killer cuprits.

I however, the Janta Government is truly intends provide proper medical facilities to the masses, then it is once

again requested to appoint a LOKPAL to enquire into the forking management and corruption in the Civil Hospital, Rewari. So that the people of this area could have a proper medical aid. In order to give a clear and true pitcute of the situation, it a very essential to transfer the present doctors and nurses those are not capable to work independently.

We hope the Government will definitely save the lives of hundreds by taking proper and appropraite action into these unfortunates happening in the Civil Hospital, Rewari.

Thanking you.

Yours faithfully,

Sd/- Ram Kishan

CC forwarded;-

All the Editors of the Daily News papers.

Director of Health Serviices, Haryana.

Chairman, District Red Cross Socitey, Narnaul.

प्रतिलिपि क्रमांक आ:रे:ओ5 77/03, दिनों 28-8-77
प्रेषक सम्पूर्ण क्रांति संघ, रेलवे रोड़ रिवाड़ी सेवा मे श्रीमती डा.
कमला वर्मा स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार।

विशय:- भ्रष्ट एवं निश्कृएट स्टु के तुरन्त तबादले की मांग।

माननीय मंत्री जी,

हरियाणा सरकार ने लाखों रूपये का व्यय कर रेवाड़ी भाहर व देहात की आम जनता के स्वास्थ्य लाभ के लिये सिविल हस्पताल रिवाड़ी का निर्माण किया है किन्तु सरकार द्वारा व जन स्वास्थ्य के लिये की गई सभी कोशिशों में, कुछ गलत स्टाफ (डा. क मीरी लाल सिक्का, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नारनौल, नर्सिंग सिस्टर मिश्रा, एम.एस.ओ. डा. गेरा रिवाड़ी) के नियुक्त होने के कारण न केवल अनेपयोगी हुई है अपितु जनता के सिरदर्द का कारण बन गई है हस्पताल में नर्सिंग सिस्टर मिश्रा द्वारा रोगियों से ऐडमीशन व डिसचार्ज के समय गैर कानूनी ढंग से पैसे पसूल किये जाते हैं और मरीजों के लिये आने वाली दूध आदि सामग्री उनके घर पर भेजकर नाजायज इस्तेमाल किया जाता है और रोगियों को दवाईयों से इन्कार कर, दवाईयां चोर दरवाजे से बाजारों में भेजकर पैसे ऐंठे जाते हैं।

जब जब भी डा. क मीरी लाल सिक्का दौरे पर जाते हैं तो वे अपना सारा ध्यान अपने हफ्ते की वसूली और धारूहेड़ा स्थित काम्पलेक्स पर दारू के दौरो पर केन्द्रित करते हैं। यहां डा. सिक्का ऐमरजेंसी के दौरान निकम्मी कांग्रेस सरकार की चापलूसी में निर्दोश जनता पर अमानवीय अत्याचार करने में सबसे आगे रहे हैं।

हरियाणा सरकार ने उन सुविधाओं पर व्यय किये गये लाखों रूपये एवं नेक इरादे डा. सिक्का, नर्सिंग सिस्टर मिश्रा और डा. गेरा की वजह से जनता की पिड़ितता का कारण बने हुए हैं।

इन तीनों भ्रष्ट व निकृष्ट सटाफ के तुरंत तबादले की परम आवश्यकता है और इनके तबादलों से ही जन स्वास्थ्य कार्यक्रम खत्म हो सता है।

पहले भी अनेकों बार इन लोगों के विरुद्ध विवादायक कार्रवायें होती रही हैं किन्तु ऊपरी सिफारिशों से करवा कर ये अभी तक चिपके रहेने में सफल रहे हैं। इनके तुरंत तबादले कर यदि जांच की जाये तो तुरंत बहुत से घोटाले एवं निर्दोशों की मौत के जिम्मेदार निकलेंगे।

हम उम्मीद करते हैं कि जनता की प्रिय सरकार तत्काल ही डा. सिक्का नर्सिस सिस्टर मिश्रा व डा. गेरा के तबादले कर जनता के साथ न्याय करेगी। यदि तुरन्त ही इस संदर्भ में पग ना उठाये गये तो हमे आंदोलन के लिये विवश हो जायेंगे।

सक्रिय सहयोगी आ आ के साथ।

हस्ता: (दायंत कुमार)

हस्ता,

महामंत्री (रिवाड़ी क्षेत्र सम्पूर्ण क्रांति संघ)
यादव)

(अजय कुमार

स्वास्थ्य तथा खाद्य मंत्री कार्यालय, हरियाणा,

अध्यक्ष

प्राप्ति संख्या 2945 दिनांक 7-9-77

प्रतिलिपि क्रमांक माध्यम-77/10, दिनांक 10-9-77 प्रेशक सम्पर्ण
क्रांति संघ रेलवे रोड़ रिवाड़ी 123401 सेवा मे स्वास्थ्य मंत्री
हरियाणा सरकार।

विशय:- भ्रष्ट अधिकारियों के निलम्ब व तबादले के लिये।

माननीय मंत्री जी,

इस पत्र के साथ एक पत्र आपके नाम की एक प्रति भी
जुड़ी हुई है आपके रिवाड़ी दौरे के समय आपसे सी.एम.ओ. डा.
क मीरी लाल सिक्का एस.एम.ओ. डा. गेरा व नर्सिंग सिस्टर हुसैन
मिश्रा के विरुद्ध तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया गया था
और आपने हमे इस बारे मे कदम उठाने का आ वासन भी दिया
था।

उसके बाद राम आसरे, रसोईया की रिवायत की
एक कापी हमने अपने पत्र के साथ भेजी थी। हमे खेद है कि
आपके मंत्रालय का रुख बड़ा उदासीन है और नर्सिंग सिस्टर
हुसैन मिश्रा को अभी तक निलम्बित न कर कोई जांच भी नही
बैठाई गई है। ना ही डा. सिक्का ने डा. गेरा का बतादला हुआ
है। जन आकांक्षाओं को पूरा करना आपका फज्र है ओर आप
तत्काल कदम उठाकर नर्सिंग सिस्टर हुसैन मिश्रा को निलम्बित कर

जांच बैझायेंगी और डा. सिक्का व डा. गेरा का तबादला करेंगी राम आसरे व अन्य स्टाफ को बदले की भावना के कारण अधिकारी तंग कर रहे है और उनके साथ अन्याय की आंका है। यदि बार बार की प्रार्थना पर ध्यान न दिया गया तो हम आंदोलन के लिये मजबूर होंगे।

धन्यवाद।

आपका,

हस्ता:

(दध्यन्त कुमार महामंत्री)

रिवाड़ी क्षेत्र सम्पूर्ण क्रांति

संघ

भीघ्न एवं आव यक कदम उठाने के लिये

एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाती है:—

1. उपायुक्त नारनौल
2. सी.एम.ओ. नारनौल
3. निदेशक, स्वास्थ्य सेवाये, हरियाणा।

गांव पाली तहसील हांसी जिला हिसार के दौरे के समय गांव निवासियों ने यह बताया कि इस गांव में प्राईमरी हैल्थ सेंटर तो है परन्तु दवाईयों का प्रबंध ठीक नहीं है। उन्होंने यह मांग की कि इस प्राईमरी हैल्थ सेंटर में इवाईयों का प्रबंध किया जाये तथा स्टाफ स्थाई तौर पर लगाया जाये। प्रार्थना उचित है। मैं। स्वास्थ्य मंत्री महोदया से प्रार्थना करूंगा कि वह प्राईमरी हैल्थ सेंटर पाली, हिसार में दवाईयों को भिजवाने तथा स्टाफ स्थाई तौर पर लगाये जाने के आदे । जारी करवाने की कृपा करे।

हस्ता:

(विरेन्द्र सिंह)

आई.पी.एम.

स्वा. मंत्री महोदया,

आव यक कार्यवाही के लिये

हस्ता:—

कमला वर्मा

एच.एम.

31-8-77

स्वास्थ्य तथा खाद्य मंत्री कार्यालय हरियाणा।

संख्या 2943

दिनांक 7-9-77

डी.एच.एस.

ग्राम पंचायत गोरीवाल ।

तहसील डबवाली (हिसार)

दिनांक

20-7-77

नं.

श्रीमान आदरणीय देवी लाल जी,

मुख्य मंत्री डबवाली सरकार ।

विशय:- हस्पताल का स्टाफ पूरा करना व दवाईयों का इंतजाम करना ।

सेवा मे,

निवेदन है कि हमारे गांव मे हस्पताल बन चुके है और इसे सरकार ने सम्भाल लिया है । मगर अभी तक इसमे पूरा स्टाफ

नही आया और कुछ दवाईयों की कमी है। इस हस्पताल मे 15 व 20 मरीज आते है पूरा स्टाफ व दवाईयां न होने के कारण कुछ तकलीफ होती है। कृपया करके प्रबंध किया जाये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

ग्राम पंचायत गोरीवाल तहसील सिरसा।

हस्ता:

प्यारे लाल

भयोम चंद,

मैबर पंचायत

3-8-77

1062-एच.वी.एस.-77

29-7-77

CM is requested to kindly
consider sympathetically
and
issue necessary orders.

Sd/-K.L. Poswal,

To

The Chief Minister, Haryana,
Chandigarh.

Subject:- Grievances of the people of village Kot Kalsiya and nearby villages.

Sir,

(i) Road from Chhachhroli to Kot, Dadupur and Taherpur is under construction for the last many years. This is one of the very important roads connecting about 50 villages. It is requested that this road may be constructed at the earliest and at least earth work should be done at the earliest so that the patch from Dadupur to Kot can be utilised by the people.

(ii) There is a village lane in Kot village. Lot of money and labour has been spent by the villagers. Local Officials and promised to make it pakka lane. It is requested that this may be constructed very soon. This village has been declared focal village by the Haryana Government.

(iii) The majority of the people are very poor and mostly Harijans. There is one Dharamsala in the village where their relatives and Baratt stay. It is requested this may not be taken for that.

(iv) There is one Dispensary run by the Government in the village Kot. But on medicine are available there. Doctors and other staff sit idle. It is requested that medicines may be supplied immediately.

(v) It is requested that bus services should be extended to village Kot instead of village Dadupur only.

(vi) It is requested that Bus stand be provided at Dadupur and Therapur.

(vii) Sh. Ajmet Chand S/o Sh. Telu Ram of village Kot Mustka was operated upon. In the means time he lost his only son. It is requested that Chief Medical Officer, Ambala should be directed to reopen this case.

Thanking you,

Yours faithfully,

Sd/-Babu Singh Sarpanch.

Village Kot Kalsiya, Teh. Jagadhri.

सेवा मे,

श्रीमान मुख्य मंत्री महोदय,

हरियाणा ।

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन है कि सैमन डिस्पेंसरी मे कोई दवाई नही मिलती है। प्रार्थना करने पर डाक्टर स्पष्ट रूप से इंकार कर देता है। आपसे विनती है कि हमारे हस्पताल मे दवाई का प्रबंध होना चाहिए।

हम है:-

ग्राम निवासी, सैमन।

मुख्य मंत्री हरियाणा

(निवासी)

नं. 678 दिनांक 2-9-77

स्वास्थ्य मंत्री

हस्ता:- 14-9-77

पी.ए./एस.एम.

स्वास्थ्य तथा खाद्य मंत्री कार्यालय हरियाणा

प्राप्त संख्या 3422

दिनांक 15-9-77

डी.एच.एस.

सेवा मे,

श्रीमान हैलथ मिनिस्टर हरियाणा चण्डीगढ ।

विशय:- प्राईमरी हैलथ सेंटर पटौदी मे दवाईयां न मिलना ।

श्रीमान जी,

हमारे कस्बे पटौदी मे हरियाणा सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलकर बड़ा एहसान किया है । लाखों रूपया स्टाफ के वेतन आदि पर हर मास खर्च हो रहा है । परन्तु जनता को इस का कोई फायदा नहीं है ।

आजकल बाढ़ के कारण इलाकें मे मलेरिया का बहुत जोर है कौई घर बुखार आदि से बचा हुआ नहीं । अब रोगी हस्पताल जाते है तो दो दो तीन तीन दिन तो खून टैस्ट के बाद उस के रिजल्ट मे लग जाते है । कौई बदकिस्मत तो तेज बुखार या कमजोरी के कारण खुद हस्पताल नहीं जा सकता तो दूसरे आदमी को कोर्स या मलेरिया की गोलियां भी नहीं मिल सकती । मामूली छोटी छोटी दवाईयां भी डा. साहब बाजार से लाने को लिख देते है । क्योकि स्टाफ मे दवाई हनी होती मिसाल के तौर पर छोटे बच्चों के चूरनों की दवा भी हस्पताल पटौदी मे नहीं

मिलती। 24-9-77 को पर्ची नं. 27367 रजिस्टर मे चढ़ाई मगर बच्चों के चूरने की दवाएं बाजार से लाने का हुक्म मिला।

श्रीमान जी ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से क्या फायदा ? जहां गरीब जनता को कोई फायदा न हो और सरकार पानी की तरह पैसा खर्च करे। कृपया हमारे हस्पताल पटौदी मे अधिक से अधिक दवायें भेजने की कृपा करे।

भवदीय,

कंवर अब्दुल सत्तरी

खांपटौदी

दिनांक 27-9-77

एक कापी श्रीमान मुख्य चिकिस्ता अधिकारी गुड़गांव को भेजी गई।

हस्ता:

पी.ए.एच.एम.

29 / 9

स्वास्थ्य तथा खाद्य मंत्री कार्यालय हरियाणा,

प्राप्ति क्रमांक 3979

दिनांक

डी.एच.एस.

From

Chander Parkash Sharma,

Advocat Jhajjar,

District, Rohtak

To

Sh. Raj Narain,

Hon'ble Mnister for Health,

Government of India, New Delhi

Sir,

I am an advocate at Jhajjar District Rohtak (Haryana) living with my family for years together. My wife has been ailing for some diseases (Breast Boil) and Civil dispensary, Jhajjar is the only relief to the patients here.

I had to take my wife to the dispensary this morning but to utter surprise of mine, my wife was taken to the operation theatre for medical examination and for surgery. The work was started but neither any bandage nor medicine, was reported to be found in dispensary nor I was told that the same were to be procured from outside market at the time of physical examination by the I/C Medical Officer temporarily posted at Jhajjar. When my wife felt aggrieved with pain and penic situations neither this I/C M.O. temporarily posted nor the staff nurse attending the patients could satisfy me as well

as my wife. Instead of giving satisfaction they behaved in a beurocratic manner. They look the serious matte so lightly as it were a jok or fun.

It is added in articular that the civil dispensary, Jhajjar is not rendering any medical help to the atients and I am not the only witness but the compaints are wanting simply they think actions would not be taken against the officials. I know, I have experienced/difficulties which need not be emphasised as can be realised from the circumstances leading to the sending of this complaint that my wife was ill. I took her to the dispensary, but the behaviour meted out to me as well as to my wife by the I/C.M.O. and staff and the disabilities enforced on me in as much as I was asked to purchase the medicine from market side and the harrasement as such is an ample proof that is not sense of responsibility here. When this is the position of the main dispensary of Sub Dividion, Jhajjar what to talk of centres subordinate to this.

This complaint of mine is a ventilaiton of the substantive grievances of the people and I am one of them. I can simply request you to kindly see that the existance state of affairs be discouraged and the medical authorities be ordered not only to behave properly with the people but they should remove their difficulties at least genuinely. It is one again requested that the medical officer incharg temporarily posted at Jhajjar, permanantly posted at Dujana and other subordinate statt be dealt with deterrantly.

I will lead evidence at the time of enquiry;

Yours faithfully,

Sd/-

(Chander Parkash)

20-6-1977

Copy of the above is forwarded to the Chief Medical Officer, Rohtak and SDO, (Civil) Jhajjar for information and necessary action.

Yors faithfully,

Sd/-

(Chander Parkash)

अध्यक्ष द्वारा घोशणा

Mr. Speaker: I have to inform the House under Rule 282 of the Rules of procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly that the Senior Superintendent of Police, Chandigarh has intimated vide his Memorandum No. 29996/UT (ES), dated the 19th October, 1977, that "Shri Mange Ram, M.L.A., Jind constituency has been arrested by the Local Police on the 19th October, 1977, under section 188 I.P.C.P.S. Central, Chandigarh. F.I.R. Ni. 1097 dated 19-10-1977."

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

Mr. Speaker: Rao Birender Singh, M.L.A. has given a notice of Call Attention Motion under Rule 73 of the Rules of Procedure to the effect that brutal lathi charge was done by the Police on peaceful Haryana Beoparies on 19th October, 1977, and their arrests were made in hundreds including a Member of the Haryana Vidhan Sabha.

The Hon. Member desires that the Chief Minister should make a statement.

The Government may like to say something.

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): स्पीकर साहब, यह जो अरैस्ट हुए हैं, यह यूनियन टैरीटरी में हुए हैं। हरियाणा गवर्नमेंट का इससे कोई वास्ता नहीं है। इसके लिये मुझे वक्त चाहिए, ताकि मैं सारी इनफॉर्मेशन लेकर इस बारे में स्टेटमेंट दे सकूँ ?

राव बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, आज तक का ही सैंशन है। आज फिर सैंशन खत्म हो जायेगा। आज तो फिर हाउस एडजर्न हो जायेगा। कोई समय फिक्स कर दीजिये।

चौधरी देवी लाल: स्पीकर साहब, हरियाणा गवर्नमेंट का कोई वास्ता नहीं है। यूनियन टैरीटरी का वास्ता है। इसलिये जल्दी नहीं हो सकता।

राव बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, यह तो इन्होंने कह दिया कि जल्दी नहीं हो सकता मगर मैं आपसे एक चीज अर्ज करूंगा आज के अखबारों में साफ तौर पर लिखा है और खास

बात पर झगड़ा हुआ कि एक इन कौन ले। ज्यादा मार कौन मार सकता है। और उसके ऊपर हरियाणा आर्म्ड पुलिस (व्यवधान) यह अखबारों में आया है (व्यवधान) इस बात को क्लैरिफाई तो चौधरी साहब ही कर सकते हैं कि एक इन किसने लिया ?

चौधरी देवी लाल : हरियाणा में वाक्या हुआ हो, तो स्टेट गवर्नमेंट को पता हो सकता है कि उसके यहां कोई ऐसी बात हुई है। (व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : आप अखबार तो पढ़ते होंगे

चौधरी देवी लाल : यह आपको पता होगा। आप वहां पर मौजूद होंगे।

राव बीरेन्द्र सिंह : या बंसी लाल की तरह अखबार पढ़ते ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : राव साहब मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि इनको टाईम चाहिए (व्यवधान) क्योंकि यह यूनियन टैरीटरी का मामला है।

चौधरी राम लाल वधवा : आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर। जो इनफर्मे इन पेपर में आई है वह यह है कि जो हरियाणा के डी० आई० जी० थे, उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन यूनियन टैरीटरी वालों ने कहा कि आप दखल नहीं दे

सकते और वे वहां से वापिस चले आए। इसलिए हरियाणा का उसमें कोई दखल नहीं है।

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कोई टाईम फिक्स कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : सरकार को और टाईम चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : सारी इनफॉर्मेशन अगर लीडर आफ दी हाउस चाहें, तो आधे घंटे में आ सकती हैं। किसी भी वक्त हाउस के बिजनैस को इन्ट्रूट करके, आप चीफ मिनिस्टर साहब को यह कह सकते हैं कि हाउस को इत्तलाह दे दें।

श्री अध्यक्ष : राव साहब, यह छोटी सी बात है

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, यह छोटी सी बात नहीं है। बेगुनाह व्यापारियों को इस तरह से (व्यवधान व भाोर) मेरी इत्तलाह तो यहां तक है कि जनता पार्टी के कुछ लीडरों ने ही उन व्यापारियों को यहां पर बुलाया। मेरी बड़े मोहतबर ज़रिए से यह इत्तलाह है कि जनता पार्टी के कुछ लीडरों ने उनको यहां पर बुलाया (व्यवधान)

उद्योग मन्त्री (डाक्टर मंगल सैन) : बड़ी दूर की सूझी।

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, यहां पर खून हो रहा है। (व्यवधान) स्पीकर साहब, यह हकीकत है और मैंने इस बात की तसदीक कर ली है कि इसमें जनता पार्टी के मेंबरान भी

भाामिल हैं। यह इस बात से साबित होता है कि जनता पार्टी का एक एम0 एल0 ए0 भी अरैस्ट हुआ है; और एक दूसरा मेंबर व्यापार मण्डल का प्रेजीडेंट है।

श्री मूल चन्द जैन : आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर। मेरा प्वांयट आफ आर्डर यह है कि जहां तक हमें सूचनाएं हैं, आज फिर हरियाणा के हरेक कस्बे में मुकम्मल हड़ताल है, अगर ऐसी सिचुए ान है तो फिर हमारे लीडर को इस मामले पर जरूर स्टेटमेंट देनी चाहिए। यह कोई मामूली बात नहीं है कि इसे इस तरीके से निबटा जाए।

Mr. Speaker : Please let me make an observation.

इनका यह मो ान कल भाम को भी मेरे पास आ सकता था, क्योंकि यह इंसीडेंट कल दो और तीन बजे के बीच हुआ था मैं फिर उसको गवर्नमेंट के पास भेज सकता था। उनको टाईम भी मिल जाता। अभी यह तकरीबन 15 मिनट पहले ही मेरे पास आया है। We should give reasonable time so that the Minister concerned can collect the necessary data to give a suitable reply.

Rao Birender Singh: Will reasonable time be after the House adjourns, Sir ? This is my submission that this is such a matter which must not be postponed. There must be some statement from the Government. My reliable information is that Janata Party leaders called the Beoparies, organised them and one Member of the Janata Party from the House has

been arrested. Another Member of the Janata Party is a leader. He is a President of the Beopar Mandal (Interruptions).

Mr. Speaker: There is a point of order, Rao Sahib

Rao Birender Singh: Was it to make the Beoparies a scape-goat so that Chaudhari Devi Lal could beat them and say that his Government is not less strong than that of Bansi Lal

Mr. Speaker: Rao Sahib

Rao Birender Singh: This was to strike a terror in Haryana.

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वांयट आफ आर्डर, सर! क्या आप इस ढंग से इर-रैलेवैन्ट बात कहने की इजाज़त दे सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, राव साहब

चौधरी देवी लाल : ये उस जगह पर एलीगे उन लगा रहे हैं, जहां पर हमारी सरकार का कोई वास्ता नहीं। वाक्या चूंकि चण्डीगढ़ की टैरीटरी में हुआ है, इसलिए कुछ टाइम चाहिए। यदि आप चाहें, तो हम सै उन बुलाने के लिए भी तैयार हैं।

बहिर्गमन

Mr. Speaker: Rao Sahib, you have been rather unreasonable. You have raised certain issues which you

should not have raised, making allegations about the members on the other side (Interruptions). I am sorry, there was a point of order but you did not take your seat (Interruptions).

Rao Birender Singh: I am sorry so say that when they were trying to hoot me down, you did not say anything

Mr. Speaker: I did check. Please sit down. Please take your seat.

(At this stage Rao Birender Singh, Rao Dalip Singh, Shri Jagit Singh Pohloo, Chaudhari Birender Singh, Shri Inderjit Singh and Shri Narain Singh staged a walk-out)

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, यह हाउस की कार्यवाही से निकाला जाए।

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन) : स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। स्पीकर साहब, बड़ा अफसोस है कि अपोजी उन के एक मेंबर ने आपकी नम्रता का, भालीनता का दुरुपयोग करते हुए चेयर को डिफाई किया है और कुछ ऐसे भाब्दों का प्रयोग किया है, जो उन्हें नहीं कहने चाहिए थे। मेरा सुझाव है कि उन भाब्दों को हाउस की कार्यवाही से एक्सपंज किया जाए।

Mr. Speaker: All that was said after I said 'Please sit down' will be expunged.

Education Minister (Col. Rao Ram Singh) : I wish to bring one point. May I have your permission ?

Mr. Speaker: Yes.

Col. Rao Ram Singh: Certain words were used against the Army Officers. I think that the Defence forces of India have acquitted themselves in a most remarkable and commendable manner and for any member of this House to cast aspersions on Army Officers in a derogatory manner, I submit, is most objectionable behaviour and due notice should be taken of this fact

एक सदस्य : वह तो सारा एक्सपंज हो गया है ।

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, चाहे एक्सपंज हो जाए, लेकिन कोई हाउस का मੈबर आर्मी आफिसर्ज के खिलाफ ऐसी बात कह सके, मैं समझता हूँ कि यह एक निहायत भार्म की बात है । हिन्दुस्तान की फौज ऐसी फौज है, जिसने एक दफा नहीं दस दफा हिन्दुस्तान का प्रोटैक इन करके पअने कारनामं दिखाए । ऐसी फौज की भान के खिलाफ किसी हाउस का एक मੈबर रिमाक्स पास करे कि आर्मी आफिसर की तरह बिहेव करते हैं । इसका मतलब यह है कि आर्मी आफिसर्ज को बिहेव नहीं करना आता । किसी मੈबर का ऐसा कहना यह भार्म की बात है ।

Mr. Speaker: I say this much that this was most unfortunate for him to have used that language. We all know in this House that the best service that our country has or our Defence Forces who have, done wonderfully well for the

country. I wish to make it very clear that he was very high handed. In spite of having been asked repeatedly to sit down. On the other hand he started making irresponsible allegations against the Members of the Ruling Party which is not the correct thing to do. He should have given a reasonable time to the Minister concerned, in this case the Leader of the House, and he should have been reasonable to accept such reasonable replies. Any way, the matter ends and I wish and request that all the hon. Members should please follow the Rules of Produce and behave in a decent manner.

वि शेषाधिकार प्र न

(1) चौधरी हरद्वारी लाल एम० एल० ए० के विरुद्ध अध्यक्ष महोदय तथा पूर्ण सदन के विरुद्ध अप्रतिश्टाजनक टिप्पणियों संबंधी।

Chaudhari Hardwari Lal : On a point of order, Mr. Speaker.

** ** *

Mr. Speaker: ** ** **

Chaudhri Hardwari Lal: ** ** **

Mr. Speaker: ** ** **

Chaudhri Hardwari Lal: ** ** **

Mr. Speaker: ** ** **

Chaudhri Hardwari Lal: ** ** **

Mr. Speaker: ** ** ** **

Chaudhri Hardwari Lal: ** ** ** **

Mr. Speaker: ** ** ****

Chaudhri Hardwari Lal: ** ** ** **

Mr. Speaker: ** ** ****

Chaudhri Hardwari Lal: * * * *

उद्योग मंत्री : * * * *

Mr. Speaker: * * * *

Finance Minister (Chaudhari Satvir Singh Malik): *

* मुख्य मंत्री (चौधरी देवीलाल) : * *

* *

एक सदस्य : * * * *

Chaudhari Hardwari Lal: * * * *

A Member: * * * *

Chaudhari Hardwari Lal: * * * *

श्री भाम ेर सिंह : * * * *

Mr. Speaker: * * * *

श्री भाम ेर सिंह : * * * *

Mr. Speaker: * * * *

श्री भाम ोर सिंह : * * * *

श्री मूल चन्द जैन : * * * *

चौधरी हरद्वारी लाल : * * * *

Dr. Mangal Sein: Sir, I beg to move-

That Chaudhari Hardwari Lal has used very derogatory remarks against the Speaker and the House as a whole and this matter may be referred to the Privileges Committee..

..... (Interruptions)

Mr. Speaker: Should I refer this matter by taking the sense of the House or should I put it to the vote of the House ?

श्री कन्हैया लाल पोसवाल : * * * *

चौधरी भजन लाल : * * * *

चौधरी हरद्वारी लाल : * * * *

Development and Panchayat Minister (Sardar Tara Singh): * * * * *

Mr. Speaker : Question is-

That this matter be referred to the Privileges Committee.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The matter will be referred to the Privileges Committee.

Chaudhri Hardwari Lal: * * * *

Mr. Speaker: * * * *

(2) श्री सुरेन्द्र सिंह एम० एल० ए० को पुलिस द्वारा सदन में आने से कथित रोकने सम्बन्धी।

Mr. Speaker: I have received a notice of question of privilege from Chaudhari Hardwari Lal M.L.A. regarding the alleged entry of Mr. Kapur, S.P. Vigilance, Haryana in the Members' lobby on 18th October, 1977, seeking to pull out Mr. Surinder Singh M.L.A. for the alleged purpose of interrogation in connection with some criminal case.

Chaudhri Surinder Singh, M.L.A. raised the question of obstructing him to enter the House and his apprehension of arrest on the 18th October, 1977. Thereafter, he met in the Chamber on that very morning. He did not pursue the matter further and did not move any privilege motion which indicated that he was satisfied. Otherwise, he could have given a notice of a question of privilege in writing on the same day i.e. 18th October, 1977. Chaudhri Hardwari Lal, M.L. A. could have done the same thing on that very day but he did not do so.

On page 258 of the book entitled 'Practice and Procedure of Parliament by Kaul and Shakhder' it has been clearly stated that-

“While seeking to raise a question of privilege, a member should lay before the House all the necessary evidence in support of his contention; production of further evidence at a subsequent date is not admissible. No privilege issue can, therefore, be raised on a matter that has previously been decided on a question of privilege even though the member might have in his possession fresh material to support his contention

Moreover, in the said book, it has also been stated that-

“A question of privilege should be raised by a member at the earliest opportunity and should require the interposition of the House. Even a delay of one day might prove fatal to the notice of privilege provided the specific matter sought to be raised was of urgent importance at a particular time.”

In view of the above, I hold the notice out of order and refuse to give my consent.

श्री सुरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मेरा निवेदन है कि
(तौर)

Mr. Speaker: I have given my ruling and there can be no discussion on it.

(इस समय श्री सुरेन्द्र सिंह फिर बोलने के लिए खड़े हुए)

Mr. Speaker: I have said, I have given my ruling.

एक माननीय सदस्य : स्पीकर साहब, जब आपने रूलिंग दे दी तो फिर कोई मँबर आपकी इजाजत के बगैर बोल नहीं सकता।

श्री सुरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूँ (तोर)

Mr. Speaker: You please take your seat. There is a point of order. (Interruptions).

श्री सुरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मेरी बात तो सुनिए
..

Mr. Speaker: Will you take your seat ?
(Interruptions)

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है कि आपने अपनी रूलिंग दे दी, आपकी रूलिंग देने के बाद क्या कोई मँबर आपकी इजाजत के बिना बोल सकता है ? (तोर एवं व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवा : स्पीकर साहब, आपने इतना तो बता दिया। इनके बाप के जमाने में तो हमें खड़ा ही नहीं होने देते थे।

Mr. Speaker : I wish to inform the hon. Member that once a ruling is given you cannot discuss it.

Chaudhri Hardwari Lal : * * * *

Mr. Speaker: * * * *

Chaudhri Hardwari Lal : * * * *

Mr. Speaker: * * * *

Chaudhri Hardwari Lal : * * * *

Mr. Speaker: * * * *

Chaudhri Hardwari Lal : * * * *

Mr. Speaker: * * * *

लोक लेखा समिति तथा औद्योगिक बोर्ड के चुनाव में से उम्मीदवारी की वापसी

Mr. Speaker: Shri Mool Chand Jain has withdrawn his candidature for election to Public Accounts Committee and Board of Industries after due date and time

बहिर्गमन

चौधरी देवी लाल : स्पीकर साहब, यह जितनी भी इस दौरान में आपस में तलखकलामी हुई है, मैं चाहूंगा कि यह सारी एक्सपंज हो जाए।

श्री अध्यक्ष : हां, मैंने तो पहले भी कहा था कि that is all expunged. अब तक जो यह बदकलामी हुई है that is all expunged except those words pertaining to the Privileges Committee.

श्री मूल चन्द जैन : * * * *

Chaudhri Hardwari Lal : * * * *

Mr. Speaker: * * * *

Chaudhri Hardwari Lal : * * * *

Mr. Speaker: * * * *

Chaudhri Hardwari Lal : * * * *

Mr. Speaker: * * * *

Chaudhri Hardwari Lal : * * * *

Mr. Speaker: * * * *

Chaudhri Hardwari Lal : * * * *

Mr. Speaker: * * * *

Chaudhri Hardwari Lal : * * * *

Mr. Speaker: * * * *

चौधरी देवी लाल : स्पीकर साहब, अब कोई रास्ता नहीं रह गया कि इस भाखस से सिवाय मा र्ल के डील किया जाए। चेयर की बहुत इंसल्ट हो चुकी है। अब मा र्ल के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं रहा।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, जिस किस्म की बातें अभी इन्होंने यहां पर कहीं यह बिल्कुल नाकाबिले बरदा त हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मेंबर को हाउस से बाहर निकाला जाए। (गोर एवं व्यवधान)

Chaudhri Hardwari Lal: It is not necessary. I do not want to sit. I walk out. (Interruptions)

(At this stage Chaudhri Hardwari Lal staged a walk out)

(Thumping from the Treasury Benches and voices: Shame, shame)

Industries Minister (Dr. Mangal Sein): You are a shame of Harayna.

लोक लेखा समिति तथा औद्योगिक बोर्ड के चुनाव में
से उम्मीदवारी की वापिसी (पुनरारम्भ)

Mr. Speakder: Order please. It is the sense of the House that Shri Mool Chand Jain be allowed to retire from the contest

श्री अध्यक्ष : यह 1973 में पहले भी हुआ है। अगर हाउस राजी है तो हो सकता है। It is the sense of the House that Shri Jain be allowed to retire from contest ?

(Voices : Yes)

Mr. Speaker : After the withdrawal of Shri Jain, the number of candidates will be equal to the number of seats and there will now be no election to the Public Accounts Committee and Board of Industries.

कार्य मन्त्रणा समिति का प्रथम प्रतिवेदन

Mr. Speaker: I report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various items of business.

The Committee met at 11.00 A.M., on Wednesday, the 19th October, 1977 in the Chamber of the Speaker.

The Committee, after some discussion, recommended that the Assembly will meet on the 20th October, 1977 at 9.30 A.M., and transact the business as follows :-

1. Questions.
2. First Report of the Business Advisory Committee.

3. Motion under rule 16 regarding sine-die i.e. –
“That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.”

4. Non-Official Resolution.

1. Resolution regarding Financial help to the Flood affected people.

(By Chaudhri Ram Lal Wadhwa, M.L.A.)

2. Resolution regarding Industries in the Backward Area of District Mohindergarh (By Rao Dilip Singh, M.L.A.)

3. Resolution regarding the Constitution of the Committee to examine all Undemocratic Laws in the State (By Shri Mool Chand Jain, M.L.A.)

Industries Minister (Dr. Mangal Sein): Sir, I beg to move-

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker: Motion moved-

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker: Question is-

That this House agrees with the recommendation contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन) : स्पीकर साहब, मैं नियम 16 के अधीन प्रस्ताव करता हूँ—

कि सभा अब आज की बैठक उठने के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित रहेगी।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker: Question is-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

The motion was carried.

संकल्प (गैर-सरकारी) ---

बाढ़ पीड़ित लोगों को अधिक से अधिक वित्तीय तथा अन्य सभी प्रकार की सहायता देने सम्बन्धी

चौधरी राम लाल वधवा : आदरणीय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ—

कि यह सदन राज्य सरकार से सिफारिष करता है कि बाढ़ पीड़ित लोगों को अधिक से अधिक वित्तीय तथा अन्य सभी प्रकार की सहायता दी जाए, क्योंकि अपूर्व बाढ़ ने उनकी जान, सम्पत्ति तथा फसलों को बहुत हानि पहुंचाई है।

यह सदन यह भी सिफारिष करता है कि राज्य में भविष्य में ऐसी बाढ़ों को आने से रोकने के लिए ठोस पग उठाए जाएं।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the House recommends to the State Government that the maximum financial and every kind of other help be given to the flood affected people as the unprecedented flood has caused heavy damage to their lines, properties and crops.

This House further recommends that concrete be taken to prevent the occurrence of such flood in future in the States.

चौधरी राम लाल वधवा : डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें एक अमेंडमेंट आई है अगर वह भी ले ली जाय, तो डिस्कान

इकट्ठी
हो जाएंगी।

Mr. Deputy Speaker: I have received a notice of an amendment to this resolution from Shri Partap Singh Thakran. He may please move his amendment.

Chaudhri Partap Singh Thakran: Sir, I beg to move-

That in line 2 in between the word 'Government' and the word 'that', insert the words 'to move the Central Government.'

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That in line 2 in between the word 'Government' and the word 'that', insert the words 'to move the Central Government.'

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस संशोधन को मान लेता हूँ क्योंकि किसी तरह से यह बात रह गई थी इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ। डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा में इस वर्ष जो बाढ़ आई है, ऐसी पिछले 104 साल के अन्दर हरियाणा के इतिहास के अन्दर कभी नहीं आई। इस बाढ़ से 1974 गांव पीड़ित हुए हैं। जिला महेन्द्रगढ़, भिवानी और रोहतक के जिले खास तौर पर इससे अफैक्टिड हुए हैं, बाकी गुड़गांव, बहादुरगढ़ और झज्जर के इलाकों पर भी इसका काफी असर पड़ा। 30 लाख एकड़ रकबे पर इस सैलाब का

असर हुआ है और उसमें से 17 लाख एकड़ धरती ऐसी थी जिस पर फसल खड़ी थी, जो कि सारी की बरबाद हो गई। इसके अलावा इस बाढ़ से एक लाख 42 हजार मकानों को नुकसान पहुंचा है और बहुत सी सड़कें भी टूट गई हैं, जिससे लगभग सात करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह बाढ़ इतनी भयंकर बाढ़ थी कि इससे हरियाणा के तीस लाख लोग बेघर हो गए और जितना भी ड्रेन सिस्टम और चैनलज़ सिस्टम था वह सारा टूट गया जिसकी वजह से 7-8 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। जो फसलें बरबाद हुई हैं उनका लगभग 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मकाने गिरने से 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, तो इस बाढ़ के कारण हरियाणा में इतना भारी नुकसान हुआ है। डिप्टी स्पीकर साहब, इस बाढ़ का कारण सिर्फ भगवान का प्रकोप ही नहीं है, बल्कि इसके लिए जो पिछली कांग्रेस की सरकार थी वह बहुत हद तक जिम्मेदार है। मेरी सूचना के अनुसार मुझे जहां तक सरकारी तौर पर पता चल पाया है कि 1968 से लेकर 1977 तक हरियाणा में बंसी लाल और बनारसी दास की कांग्रेस सरकारें बरसरे इकतदार थीं। उन्होंने सैलाब के बचाव के लिए कुछ खर्च नहीं किया और न ही कोई स्कीम बनाई और अगर कोई स्कीम बनी भी तो तो वह कागजों के अन्दर ही रही। अगर किसी समय सैलाब की रोकथाम के लिए कुछ लाख का प्रोवीज़न किया भी गया तो वह खर्च नहीं किया गया और साल के अन्त में उस पैसे को दूसरी मद में ट्रांसफर कर दिया जाता रहा। तो उनकी गलत नीतियों के कारण ही आज हरियाणा को इतने भारी नुकसान का

सामना करना पड़ा। जो वे कहते थे कि हमने हरियाणा की उन्नति के लिए इतना खर्च किया है और हरियाणा में एग्रीकल्चर और इरीगे इन के सिस्टम को खड़ा किया है ताकि किसान और देहात के अन्दर रहने वाले 70 प्रति शत लोग उससे फायदा उठा सकें वह सारा रुपया बेकार गया है क्योंकि उनकी गलत नीतियों के कारण हमें यह सारा भुगतना पड़ा। मुझे अब यह कहने में हिचकिचाहट नहीं है कि आज देवी लाल की जनता सरकार इस बात के लिए धन्यवाद की पात्र है। सराहना के योग्य है कि उसके चार्ज लेने के वक्त इतनी कठिनाईयों के बावजूद उसने इतनी तेजी के साथ काम किए हैं। जैसे बाढ़ का पानी निकालने का काम और लोगों को रिलीफ देने का काम है। आज हमें बाढ़ पीड़ित लोगों के पुनर्निर्माण, जो एड्रकें टूटी और मकान गिरे हैं उनके लिए करोड़ों रुपये की जरूरत है। कई गांवों में तो अब भी लोग सड़कों के किनारों पर बैठे हुए हैं क्योंकि उन गांवों के अन्दर अब भी पानी खड़ा है। इसमें कोई भाक नहीं कि हरियाणा सरकार ने तेजी के साथ कुछ कार्य और योजनाएं भुरु की हैं और इनमें कुछ योजनाएं उल्लेखनीय हैं। हमें यह पता है कि हरियाणा चारों तरफ से दूसरी स्टेट्स के साथ घिरा हुआ है जैसे राजस्थान है, यू0पी0 है और दिल्ली है। पानी की निकासी का जहां तक ताल्लुक है वह हम दूसरी स्टेट्स की इच्छा के बिना नहीं निकाल सकते। यह सिस्टम इतना जरूरी था कि पिछली सरकार ने इन प्रान्तों की सरकार से मिलकर इस प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई। अगर ऐसी कोई योजना बनाई जाती, तो वे स्टेट्स भी सैलाब से बच

सकती थीं और हम भी बच सकते थे। इस बाढ़ का सबसे ज्यादा असर मेवात पर हुआ है। आज हमारी सरकार ने इस योजना के लिए सोचा है कि जो गवर्धन ड्रेन यू० पी० के साथ बनाने की तजवीज थी और वह कागजों में रह गई थी। अगर उसे बनाया जाता तो वह सौ किलोमीटर लम्बी बननी थी। तो आज इस सरकार ने यह सोचा है कि उसको बनाने के लिए यू० पी० सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी और कई साल उसको बनाने के लिए लग जाएंगे इसलिए हमारी सरकार ने इस दौरान अपने ही एरिए में यह ड्रेन बनाने का निश्चय किया है। अगर पहले सारा टुकड़ा सौ किलोमीटर का बनाया जाता तो उस पर 30 करोड़ का खर्चा आना था, और अब जो अपने एरिया में बनाने जो रहे हैं इस पर 18 करोड़ रुपया खर्चा आएगा जो कि 40 किलोमीटर के एरिया में होगी। इसके साथ ही डिप्टी स्पीकर साहब, यह ड्रेन जो बननी थी इस ड्रेन से पहले केवल छः सौ क्यूसिक्स पानी निकलता था लेकिन अब ड्रेन बनने के बाद इससे 2800 क्यूसिक्स पानी की निकासी होगी और छः सौ क्यूसिक्स पहले निकलता था, उसको मिलाकर 3400 क्यूसिक्स पानी का निकास इस नहर से हो जाएगा।

इस प्रस्ताव के आने से पहले कल मुख्य मंत्री महोदय ने काल अटैंशन मोड पर जो सैलाब के बारे में थी, उत्तर दिया था। इसके इलावा कभी-कभी प्रैस के अन्दर भी सरकार इस प्रकार की घोशणा करती चली आ रही है। नजफगढ़ ड्रेन और

साहिबी नदी जो हमारे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ का बायस बनी हुई है, इसका सिस्टम ऐसा है कि राजस्थान से साउथ की ओर इसका पानी चलता है और चुटाना के पास आकर पहुंचता है। इसके दूसरी तरफ ड्रेन नं० 8 का पानी नार्थ से साउथ की ओर आता है और ये दोनों पानी ईस्ट की तरफ मिलते हैं और नजफगढ़ ड्रेन की तरफ इसका रुख हो जाता है। यह बहुत बड़े इलाके को बरबाद करती है। इसके ऊपर धांसा बांध है जो बार्डर के ऊपर बना हुआ है। इस बांध के आगे नजफगढ़ झील है और इस झील की पानी निकलाने की कैपैसिटी तीन हजार क्यूबिक फीट है। हरियाणा के लिए यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बाढ़ के कारण इसमें 1 लाख क्यूबिक पानी आया है जबकि इसकी कैपैसिटी तीन हजार क्यूबिक फीट की है। इतना ज्यादा पानी निकास होने के लिए आया, लेकिन वहां पर इन्तमाज कम था, केवल तीन हजार क्यूबिक का इन्तजाम था। दादरी में भी तीन हजार क्यूबिक पानी पहुंचा है और यह पानी 10 किलोमीटर तक फैल गया है। गुड़गांवा रिवाड़ी रोड़ पर पानी ही पानी फैला हुआ है इसके बारे में सरकार की योजना है कि जो पानी रिवाड़ी-गुड़गांव पर है इस रोड़ पर एक मसानी गांव है, यहां पर 1 लाख एकड़ फीट का बांध बनाया जाएगा। चुड़ानी के लिए भी एक ड्रेन बनाने की तजवीज है जो रोहटछाड़ा सड़ के के नीचे से पानी का निकास करेगी और वह पानी नजफगढ़ की ड्रेन के अन्दर चला जाएगा। बहादुरगढ़ के साउथ में एक एडी इनल ड्रेन बनाये जाने की तजवीज है। इसके अतिरिक्त वैस्ट्रन जमुना पर **मगजपुर**

झील है इसकी कपैसिटी तीन गुणा से बढ़ा कर चार गुणा करने की तजवीज हैं। सड़कों का ऐसा इन्तजाम था कि फिरनी तक ही रोड़ज बनाई जाती थी जिस के कारण और सैलाब आने के कारण जब पानी आबादी और फिरनी के बीच में आ जाता है तो सहायता कार्य करने के लिए तकलीफ होती है। सरकार ने इन सड़कों को आबादी तक बनाने का फैसला किया है ताकि आयन्दा आमदोरफत में और रिलीफ का कार्य करने के रास्ते में कोई अड़चन न आए क्योंकि सरकार ने भीघ्रता से रिलीफ के काम करने हैं। जहां तक फायडर का ताल्लुक है। फाडर 29 रुपये प्रति क्विंटल पड़ता थ लेकिन सरकार ने इस पर 15 रुपये फी क्विंटल तकावी देने का फैसला किया है। व्हीट सीड 240 रुपये प्रति क्विंटल पड़ता था, लेकिन अब 175 रुपये प्रति क्विंटल देने की घोशणा की है। स्वास्थ्य की दृशिट से डिप्टी स्पीकर साहब, जितना कार्य हरियाणा सरकार से हो सकता था, इन्होंने किया। चीप मिनिस्टर रिलीफ फण्ड खोला गया था, इससे भी काफी सहायता दी गई है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी इस प्रस्ताव के लाने का जो भावार्थ था वह यह था कि अभी भी बहुत रिलीफ की आव यकता है और इस सारे कार्य को पूरा करने के लिए 74 करोड़ रुपये की आव यकता है। मेरी जानकारी के अनुसार स्टेट सरकार ने भारत सरकार को इस सिलसिले में लिखा है क्योंकि सदन के सदस्य भली प्रकार से इस बात को जानते हैं कि पिछली सरकार जाते-जाते डैफिसिट का बजट छोड़ कर गई है, खजाना खाली करके गई है और ऊपर से बाढ़ का प्रकोप आया है। इसके कारण

आज हरियाणा सरकार को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इतना रुपया कहां से लेकर आएँ जिससे बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करें। इसलिये मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जिनको सहायता दी जानी है, उनके पुनर्वास, पुनःनिर्माण के लिए, इस प्रस्ताव को स्वीकार करके स्टेट गवर्नमेंट से अनुरोध करें कि वह भारत सरकार से रुपया लेकर बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करें।

श्री भामेरा सिंह (नरवाना) : डिप्टी स्पीकार साहब, इससे पहले कि मैं फ्लड के बारे में कुछ कहूँ, हमारे इरीगे एंड पावन मिनिस्टर चौधरी वीरेन्द्र सिंह, जो बकहस का जवाब देने के लिये बड़े उत्सुक हैं, उनका ध्यान इस प्रस्ताव की ओर दिलाना चाहता हूँ। वधवा साहब ने प्रस्ताव किया है और ये अपनी कार पर भी नैशनल फ्लौग फ्लार्ड करते हैं और टूर प्रोग्राम में भी लिखते हैं “To hear public grivences” जब सरकार खुद प्रस्ताव पेश करे तो उसका जवाब देने की जरूरत नहीं होती। इसके लिए चौधरी वीरेन्द्र सिंह को तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के सामने फ्लड की गम्भीर स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इससे पहले, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात फिर जनता पार्टी की सरकार के दोस्तों से कहूंगा और उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस का नाम लेकर कांग्रेस का बहाना लेकर कितने दिन तक लोगों की आंखों में धूल झाँकना चाहते हैं। असल जो मसला है उसको हल करने की

बजाए, कितने सालों तक यह बात कहते रहेंगे कि कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, यह कर दिया, वह कर दिया। इन्होंने फरमाया कि इनके राज में जो पिछले दिनों बरसात हुई है वह पिछली कांग्रेस सरकार ने बरसायी है। अभी चौधरी राम लाल जी ने कहा कि इस बरसात के लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेवार है (व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवा : आप तो भाब्डों का अर्थ भी नहीं समझ सके, बड़े दुर्भाग्य की बात है। (व्यवधान)!

श्री भामोर सिंह : हरियाणा में जो फ्लड आए हैं, इस पर सबसे पहले मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि कल हाउस में सरकार ने जो एप्रोप्रिएशन बिल पास करवाया है और जो डिमांड फ्लड के खर्च के लिए आएगी। हरियाणा में जो बाढ़ का प्रकोप आया है, उसमें सहायता देने के लिए लिए, लोगों को राहत देने के लिये और आगे के लिए परमानेंट फ्लड कंट्रोल मैयर उठाने के लिए, हाउस से रुपये की मन्जूरी के लिए डिमांड लेकर आयेंगे लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निहायत अफसोस और मायुसी हुई है कि सरकार कितनी इन्डिफ्रेंट है इस फ्लड के मामले में। आज हाउस के सामने बड़ी बड़ी फ्लडज की बात करते हैं लेकिन फ्लड रोकने के लिए डिमांड न रख कर जनता सरकार ने यह साबित कर दिया है कि ये फ्लड को भी उसी तरह से लेना चाहते हैं जिस तरह से दूसरे मसलों को लेते हैं। आप इस मसले को फेस नहीं करना चाहते, मैं सरकार से डिप्टी स्पीकर साहब, आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि बगैर हाउस की मन्जूरी से वह कौन सा रुपया

है और कहां से आएगा जिसको ये फ्लायड रिलीफ के लिए खर्च करेंगे। जो रुपया तकावी के रूप में, कर्जों के रूप में बीज और खाद के रूप में और दूसरे मैयर हैं ड्रेन बनाने हैं, उनके लिये जो रुपया खर्च करेंगे वह रुपया कौन से आसमान से करेंगे जिससे फ्लड इफैक्टिव लोगों को राहत दिलवायेंगे। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि फ्लड का सबसे ज्यादा प्रकोप कुदरत की तरफ से गुड़गांव जिले और रोहतक जिले में आया है। उस इलाके में जो दिल्ली प्रान्त के साथ लगता है, साहिबी नदी के आसपास के इलाके हैं, उसमें बाढ़ का सबसे ज्यादा प्रकोप हुआ और इससे मैं समझता हूं कि जनता पार्टी की सरकार की सबसे ज्यादा जो कमी रही है वह यह है कि यह दो अढ़ाई महीने के निरन्तर वक्त में जबकि सारे हरियाणा की भूमि पानी के नीचे थी, दिल्ली की अथारिटीज के ऊपर भारत सरकार से दबाव डलवाकर धासा बांध के गेट नहीं खुलवा सकी और उस पानी के निकालने का इन्तजाम नहीं करवा सकी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात भी कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी के कंवीनर चौधरी रणबीर सिंह जी, उन्होंने दिल्ली अथोरटीज को अल्टीमेटम दिया कि अगर वे उस बांध के गेट नहीं खोलेंगे तो वे पार्टी की तरफ से उसके ऊपर डारैक्ट एक्शन लेंगे। (विघ्न) उपाध्यक्षा महोदय, हमारी पार्टी के प्रोफैसर हरि सिंह और दूसरे बहुत से कांग्रेस के हजारों वर्कर्स ने रोहतक जिले के झज्जर सब डिविजन में न सिर्फ सत्याग्रह किया, हजारों की तादाद में इकट्ठे हुए बल्कि हिन्दुस्तान के प्रधान मन्त्री और दूसरे लोगों से जाकर मिले और उस दबाव के कारण दिल्ली की

अथोरटीज मजबूर हुई और उन्होंने वे गेट खोले जिससे हरियाणा के लोगों को काफी राहत हुई पानी के निकालने में।
(विघ्न) ये कल जो मुजाहिरा हुआ यह किस के वर्कज ने किया ? (विघ्न)

चौधरी मेहर सिंह राठी : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि प्रोफ़ेसर हरि सिंह वहां गए थे और हजारों कांग्रेस वर्कज उनके साथ थे। लेकिन मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि यह गलत बात है। वे और चौधरी रणबीर सिंह जी केवल वहां गए थे। मैं भी वहां देखने के लिए गया था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सिवाय हम तीन व्यक्तियों के वहां कोई नहीं था।
(विघ्न)

श्री भाम ोर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो पता लग गया कि राठी साहब के साथ भी कोई नहीं गया। ये भी अकेले थे। (विघ्न)

श्री लहरी सिंह महेरा : राठी साहब के साथ एक हजार आदमी मेरे सामने गए थे। (विघ्न)

श्री भाम ोर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस फ़्लउ के बारे में यह बात कहना चाहूंगा कि हमारे जो मुख्य मी हैं, मैं इस बात में कोई संकोच नहीं करूंगा कहने में, इन्होंने जाति तौर से, पर्सनल तौर से, काफी इलाकों का दौरा किया, और लोगों की बात सुनकर उनकी तकलीफ़ों को दूर करने का प्रयत्न किया।

हमारे सिंचाई मंत्री जी ने भी कई इलाकों का दौरा किया। लेकिन समूचे तौर से सारी सरकार और सारी मीनिरी के बारे में यह बात करना चाहूंगा कि इस दिना में बहुत कम काम हुआ है। हरियाणा में पिछले साल भी, 1976 में भी फ्लड आया था। उस वक्त भी हमारे नरवाना सब-डिवीजन में फ्लड आया था। उस समय मुझे वहां बार बार जाने का इत्तफाक भी हुआ था। जिस प्रकार से इस प्रान्त की सरकारी मीनिरी ने उस वक्त पानी को निकालने का कार्य किया था, उस पैमाने पर इस बार काम नहीं हुआ। कलायत के हल्के में जो नरवाना सब-डिवीजन का इलाका है और जनता पार्टी के एक मिनिस्टर साहब श्री राठी साहब का हल्का है, उसमें पानी के निकालने के लिए सरकार ने प्रबन्ध नहीं किया, बावजूद इस बात के कि मैंने खुद न सिर्फ पोलिटिकल अथॉरिटीज़ से, जिनमें मुख्य मंत्री और सिंचाई मंत्री भी शामिल हैं, प्रार्थना की, बल्कि स्टेट लेवल और जिला स्तर के अफसरों का भी ध्यान दिलाया कि इस दिना में जल्दी से जल्दी कोई कार्यवाही की जाए। आज भी थोड़ी नहीं, हजारों एकड़ जमीन में वहां पानी है। न सिर्फ जमीन में पानी है बल्कि कम से कम एक दर्जन देहात ऐसे हैं, जिनकी आबादियों में पानी है, जिनकी आबादियों में दाखिल होने के लिए जगह नहीं है और लोगों को, औरतों को, बच्चों को पानी के अन्दर से जाना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बात बताना चाहता हूं कि कलायत के हल्के में डी-वाटरिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा एक दर्जन पम्प लगे हुए हैं, एक दर्जन से ज्यादा इंजन और मोटरें

नहीं लगी हुई हैं, जो निहायत इन ऐडिक्वेट हैं। यह दुःख की बात है।

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात भी आपके माध्यम से सदन के साने रखना चाहूंगा कि नरवाना सब-डिवीजन के तीस के करीब देहात बहुत बुरी तरह से फलड के िकार हुए हैं। इसमें पांच गांव नरवाना के हैं, चार-पांच उचाना हल्के के हैं और बीस-पच्चीस गांव कलायत हल्के हैं हैं। इसलिए मैं आज भी हाउस में यह बात कहना चाहूंगा कि अभी टाईम है, अभी दो हफते का वक्त है। अगर सरकार बड़ी तादाद में बिजली और डीज़ल की मोटरें इंस्टाल करके डी-वाटरिंग का काम तेज़ करे तो हजारों एकड़ जमीन में बीजाई हो सकती है। इसके साथ ही मैं सरकार से यह भी प्रार्थना करूंगा कि यह फलड अफैक्टिड एरिया में किसानों का मालिया माफ करे, तकावी दे, बीज और खाद के लिए कर्जा देकर उनकी मदद करें। उपाध्यक्ष महोदय, इतनी बात कहकर मैं अपना स्थान लेता हूँ।

चौधरी प्रताप सिंह ठाकरान (गुड़गांव) : डिप्टी स्पीकर साहब, जो मोान चौधरी राम लाल जी ने मूव किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। हरियाणा प्रदेश में बाढ़ से जो गम्भीर स्थिति पैदा हुई है, वह बड़ी भाोचनीय है। फलड तो हमें ही प्रदेश में आता है लेकिन वह दफा जो फलड आया है वह बहुत ही ज्यादा है और इसका उदाहरण नहीं मिलता। इसकी वजह क्या है ? डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा में यह जो पानी आता है, यह हरियाणा

प्रदे 1 का पानी नहीं है। दरअसल महेन्द्रगढ़, गुड़गांव और रोहतक के काफी हिस्से में जो बाढ़ का पानी है। यह सारा पानी राजस्थान का है। राजस्थान सरकार, जहां पानी की कमी है, जहां नहरें हैं नहीं, अन्डर ग्राउंड वाटर है नहीं, बारि 1 का पानी कन्ट्रोल करने में फेल रही है। पहाड़ी इलाका होने के वजह से बरसात का पानी साहबी नदी से हरियाणा के इलाके में आता है। नैचुरल फलो पानी का राजस्थान से हरियाणा में जहां से आता है उस हिस्से में आज तक हरियाणा की पिछली सरकार ने कोई कोर् 1 1 नहीं की कि इस पानी को ड्रेन आउट किया जाए, इसका कोई प्रबन्ध किया जाए। सारे इतिहास में मुगल भासन में अकबर बाद 11ह ने एक दफा कोर् 1 1 की थी इस पानी को कन्ट्रोल करने के लिए, लेकिन वह अपने टाईम में असमर्थ रहा और कोई बन्दोबस्त नहीं हो सका। उसके बाद ब्रिटि 1 भासन में कभी कोर् 1 1 नहीं की गई कि इस पानी का कोई इंतजाम किया जाए। लेकिन इस बार इमीजिएट रिलीफ के लिए हमारी सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उसके लिए मैं अपनी सरकार का बड़ा भारी म कूर हूं। मेरा गांव मेरा हल्का और मेरा जिला इस बार फ्लड से सबसे ज्यादा अफैक्टिड है। यह पहली दफा हुआ है, जब गवर्नमेंट ने हरेक गांव में, हरेक घर में हरेक आदमी को पूरा रिलीफ, रा 1न, दवाई और यहां तक कि जिन गांवों में बाढ़ का पानी ज्यादा होने की वजह से ईंधन तक नहीं रहा था, वहां मिट्टी का तेल और दूसरी चीजें सप्लाई की हैं। यहां तक कि खाना भी सप्लाई किया है। हमारे लोगों ने तो खाना सप्लाई

किया और जनता को काफी रिलीफ दिया। चौधरी भाम े र सिंह जी किसी भी गांव में चले जाएं, वहां से मालूम कर लें, हमने हर गांव में हर प्रकार की इमदाद की है, हमोर चीफ मिनिस्टर साहब ने बार-बार दौरा किया और जनता पार्टी के हरेक वर्कर ने पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया, हरेक चीज का पूरी तरह से बन्दोबस्त किया। उन्होंने यहां हाउस में कहा कि धांसा बांध का गेट कांग्रेस पार्टी के लोगों ने खुलवाया, वे गेट तो हमे ा खुल ही रहते हैं, लेकिन उनकी पानी निकालने की कैपेसिटी बहुत कम है। निकास तो तीन हजार क्यूसिक्स पानी का है और साहबी नदी का जो पानी आता है, वह लाखों क्यूसिक्स है। सवाल तो है कि जो पानी का नैचुरल फलो है उसका कोई बन्दोबस्त नहीं किया गया। इसलिए इस बाढ़ का असर हमारे ऊपर ज्यादा हुआ है।

इसके अलावा मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि मैं उस इलाके का रहने वाला हूं। अजरा गांव राजस्थान का बार्डर है और हमारे हरियाणा के हैं रानोली, प्राणपुरा और झाबवा आदि गांव हैं, वहां पर एक बड़ी लेक बनाई जा सकती है। उसके बाद फिर वही पानी साहबी नी का, कोट काँ ान जो राजस्थान के गांव हैं, उनमें जाकर फिर हरियाणा के गांव में आता है, वहां पर भी इसके लिए लेक बनाई जा सकती है। इस पानी को इरीगे ान के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। आजकल जो नहर जवाहर लाल नेहरू कैनल के नाम से अन्डर कन्स्ट्रक् ान है, उस कैनल को डबल भी कर सकते हैं,

क्योंकि उसमें जो पानी जाएगा, वह लिफ्ट स्कीम से जाएगा और उस पानी का बहाव ईस्ट से वैस्ट को है, लेकिन कैनल का पानी वैस्ट से ईस्ट को जाना है। अगर उस पानी का इस्तेमाल कर लिया जाए, तो ठीक रहेगा। साहिबी नदी का सारा पानी इकट्ठा करके उसी नहर में चैनेलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा धांसा बांध का नैचुरल फलो जमना में था। पटौदी, झज्जर, बहादुरगढ़ और दिल्ली के जो भी देहात हैं, इन सबका नैचुरल फला जमना रिवर में है। तो यह धांसा बांध बनवाया गया। उस टाइम पर दिल्ली में बड़े बड़े कालोनाइज़रों ने कालोनियां बनाई थीं। उन कालोनाइज़रों ने लाखों रुपया कमाया और वहां पर आजकल लाखों और करोड़ों रुपयों की कोठियां बनी हुई हैं। उन एरियाज़ को बचाने के लिए ये बांध बांधा गया था, लेकिन इस बांध से हरियाणा के गरीब किसानों को और मजदूरों को बड़ा भारी नुकसान हुआ। यह नुकसान केवल इसी साल ही नहीं, बल्कि हर साल होता है। इस नुकसान का कोई अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता कि कितना हो चुका है। अब यही है कि बांध बन गया है और मकान वहां बन गए हैं, कुछ नहीं किया जा सकता है। इस विशय में मेरा अपना सुझाव है कि जहां पर यह बांध बांधा गया है, वहां पर दिल्ली की ईस्ट साइड से एक और ड्रेन ले जाई जा सकती है, उसको ओखला हैडवर्क्स के साथ मिलाया जा सकता है। इसका पहले भी सर्वे हुआ था, लेकिन उस टाइम पर वह स्कीम अमल में नहीं लाई गई। इन भाब्दों के साथ राम लाल जी ने जो प्रस्ताव सदन में रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ।

चौधरी रिजक राम (राई) : डिप्टी स्पीकार साहब, यह जो प्रस्ताव आज सदन के सामने आया है इसकी अहमियत आज ही नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी बड़ी भारी है। अभी चौधरी प्रताप सिंह जी ने बोलते हुए फरमाया कि हरियाणा को आए साल जो इतनी मुसीबत उठानी पड़ती है, तबाही बरदा त करनी पड़ती है। यह उनकी अपनी बीमारी नहीं है, बल्कि पड़ौसी प्रान्त का पानी हमारी स्टेट में आता है और हमारे यहां उसके खारिज होने का रास्ता नहीं है। धांसा बांध के आसपास और रोहतक जिला ही नहीं बल्कि और भी काफी इलाके तबाह होते हैं, यह सारा पानी राजस्थान का ही नहीं, बल्कि पंजाब स्टेट का भी काफी आता है। संगरूर जिले से होते हुए घग्घर से यह पानी निकलता है, लंडोहवा नाला और नाई वाला नाले से आकर जींद के इलाके को तबाह करता हुआ ड्रेन नम्बर आठ में जाकर गिरता है। ड्रेन नम्बर आठ भी सारा पानी नहीं ले सकती क्योंकि दिल्ली वाले लाने नहीं देते। चौधरी भामे र सिंह जी तो कांग्रेस पार्टी के हैं, पहले हम में से बहुत से भाई कांग्रेस में थे, लेकिन अब वे जनता पार्टी में हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस पानी की किस पार्टी की जिम्मेदारी है। रोहतक में जो फलड आता है आरैर यह जो धांसा बांध बना है इसकी तमाम की तमाम जिम्मेदारी आज की कांग्रेस पार्टी की है। अगर उनको याद हो और न याद हो, तो मैं याद करा देता हूं, मैं इस बारे में किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि यह धांसा बांध किस टाईम पर बन्ध है ? यह सन् 1962-1963 में बना था, लेकिन

उस वक्त कौन मन्त्री थे ? डिप्टी स्पीकार साहब, आप हैरान होंगे कि उस वक्त भी साहिबी का, दूसरी नदियों जो झज्जर को वापिस पानी ले जाती हैं, उनका एवरेज डिसचार्ज था, वह 12,000 क्यूसिक्स था, लेकिन चौधरी रणबीर सिंह जी ने इस बात पर दस्तखत किए कि धांसा बांध बना दिया जाए और उसको रोकने के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया गया। उन्होंने वहां 4500 क्यूसिक्स का रेगुलेटर मिलकर लगवा दिया। 12 हजार और 14 हजार क्यूसिक्स पानी पीछे से आ रहा है और आगे 4500 क्यूसिक्स खारिज हो रहा है तो दूसरे एरियाज में नुकसान करेगा। बारि 1 ज्यादा हुई तो झज्जर के इलाके में न केवल तबाही हुई, बल्कि मकानों की छत्तों तक पानी पहुंच गया और उनके मवे 11 20-20 दिन तक और महीनों तक बारि 1 में पानी में खड़े रहे। सारी फसलें मारी गईं लेकिन दिल्ली के लोगों ने कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। आज जहां फ्लड का मसला आता है, तो हम यह महसूस करते हैं कि अगर भाहर को जरा भी पानी टच कर जाए, तो दर्द होने लगता है, लेकिन आज धांसा बांध की वजह से सारी झज्जर तहसील का सारा इलाका पानी से तबाह हुआ है। उस इलाके के साथ दिल्ली की सरकार को हमदर्दी आनी चाहिए, वह नहीं आई आज वे भी उसी जिद्द पर खड़े हैं कि पानी नहीं निकलने देना है, उनकी कालोनियों में पानी नहीं आना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि पक्के मकानात तो बच जाएंगे लेकिन आप यह भी तो देखें कि झज्जर तहसील में कितने कच्चे मकानात गिरे पड़े हैं, फसल तबाह हुई पड़ी है, मवे 11 बरबाद हो गए हैं आज हमारे

मुख्य मंत्री जी हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं जहां गुड़गांव जिले में कृष्णा नदी में लडोहा नाला आकर गिरता है, वह नुह और फिरोजपुर झिरके के सार इलाके को तबाह करता है। गोवर्धन ड्रेन है, राजस्थान और यू0 पी0 को जाती है उसके पानी को यू0 पी0 साईड रैगुलेटर लगा हुआ है। जब तक सारी स्टेट्स की को-आर्डिनेटिड स्कीम नहीं बनेगी, तब तक कोई हल नहीं निकल सकता। आप उचाना लेक में से एक और लेक बे ाक निकाल लें। आपका अन्दाजा 22 करोड़ रुपया खर्च करने का है, लेकिन जिस वक्त वह कम्पलीट होकर चलेगीय, तो आप देखेंगे कि 30-35 करोड़ से कम खर्च नहीं आ सकता। आप बे ाक फाईनैसिज का अन्दाजा लगाकर देख लें। यह सिर्फ उचाना लेक का सवाल ही नहीं है, बल्कि आपने इस प्रॉक्लम को स्टेट लेवल पर हल करना है। मैं तो यह कह नहीं सकता कि पहले कोई काम ही नहीं हुआ। अगर पहले इतनी ड्रेन्ज न बनतीं तो इस हरियाणा का बचना मुश्किल था। ड्रेन्ज बनी हैं। लेकिन बची में 7-8 साल का समय ऐसा गुजरा जो ड्राई साईकलोन का टाईम था जिस की वजह से जो ड्रेन्ज बनीं थी, वह सिल्ट अप हो गयीं। उनकी मुरम्मत नहीं की गई। उनके बैंक्स टूट गए, क्योंकि ड्राई साईक्लोन था। लेकिन आपको जैसे कि पता ही है कि पिछले दो साल से फ्लडज फिर आने शुरू हो गए हैं। जैसे कि आप सब ही जानते हैं कि ड्राई साईक्लोन के बाद वैट साईक्लोन चलता है। पहले 5-7 साल वैट साईक्लोन चला और फिर 5-7 साल ड्राई साईक्लोन चला और जब ड्राई साईक्लोन चलता है, तो हम

लापरवाह हो जाते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि बाकायदा इस बात की निगरानी आगे के लिए मास्टर प्लान बनाकर रखी जाए। हम किसी पर दोश लगाएं, यह भी ठीक बात नहीं है। हमारी पार्टी के सामने ही यह मसला नहीं है, बल्कि यह तो सक पार्टियों के सामने है। यह एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें सकबी को-ऑप्रे इन की जरूरत है। इसमें हमारे हरियाणा की ही नहीं, पंजाब, राजस्थान, यू0 पी0, दिल्ली इन सब स्टेट्स की को-आर्डिने इन की जरूरत है। मैं यह समझता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री महोदय की जो अप्रोच है, वह ठीक है कि हरेक स्टेट के चीफ मिनिस्टर से और इरीगे इन मिनिस्टर से बार-बार कान्फ्रेंस करके इस मसले का हल निकालें। हमारी पेचीदगियां इतनी हैं आप देखें कि राजस्थान का पानी साहिबी नदी और कृष्णा नदी से होकर हरियाणा में आता है और सारे गुड़गांवा जिले के काफी इलाके को तबाह करता है। वहां पर आपने झीलें भी बनाई हैं और रीमॉडलिंग भी की है, जिससे मुस्तकिल तौर पर आबपा ि हो सके। भाखड़ा और दूसरी नहरों से जितना भी पानी हरियाणा में आता है, वह उतना नहीं है जितनी हमें जरूरत है। अब हमारे सामने सवाल यह है कि फ्लड का जो पानी है, उससे एक तो तबाही से कैसे बचाया जाए और दूसरे उस पानी का इस्तेमाल कैसे हो। मुख्यमंत्री जी ने कल फरमाया था कि बाढ़ के पानी के लिए हम यह प्रबन्ध कर रहे हैं कि हम झीलें बना रहे हैं, तालाब बना रहे हैं। मेरा कहना यह है कि मैक्सिमम ऐसी स्कीम्ज़ बनानी चाहिएं जिनके जरिए से उस फ्लड के पानी का चाहे कौनाल्ज के

ज़रिए या चाहे चैनल्ज़ के ज़रिए, मैक्सिमम यूटिलाईज़ैशन किया जा सके। दूसरी जो नहरें हैं, उनमें फ्लड का पानी डालकर जो ड्राई इलाके हैं, चाहे वे महेन्द्रगढ़ का इलाका है, या नाहड़ का इलाका है। इन इलाकों को पानी पहुंचाया जा सकता है। इसी तरीके से दूसरे ऐसे इलाकों में जहां पर पानी की कमी है, यह पानी एब्जॉर्ब करके उसको इस्तेमाल किया जा सकता है और कुछ हद तक पानी का मसला हल हो सकता है। यह मसला केवल रोहतक जिले या गुड़गांव जिले का ही नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो आपको यह पता लगेगा कि अम्बाला जिला भी इससे वर्स्ट अफ़ैक्टिड है। वहां पर आज तक भी इसका इलाज नहीं हो सकता। वहां पर कितने नाले हैं, छोटी छोटी नदियां हैं जो कई दफा दरिया का पानी काट देती हैं। इसके साथ ही कई इलाके अम्बाला जिले में ऐसे पड़ते हैं जहां पर हम पानी नहीं दे सकते। वहां बारानी इलाके हैं जहां पर कोई पैदावार नहीं होती। इसके बारे में सरकार ने एक खोज इंजीनियरिंग से करवाई थी और उन्होंने यह देखा कि इस अम्बाला जिले के इलाके में और कई दूसरे जिलों के इलाकों में सायल ऐसी है जिसमें कि पानी जजब ही नहीं होता। वहां पर सायल ऐसी है कि वह लोअर लैवल तक पानी को जाने ही नहीं देती। जितना भी पानी वहां पर पहाड़ों से बह कर आता है यह बारि 1 का पड़ता है, वह सारे का सारा बहकर चला जाता है और फ्लड्स के दिनों में दूसरे इलाकों को तबाह कर देता है। इस पानी को किस तरह से नीचे सायल तक पहुंचाया जाये ताकि ट्यूबवैल की यह रिपोर्ट आयी थी कि दरिया

के साथ साथ भौलो ट्यूबवैल लगा दिये जाये। उन्होंने यह कहा कि बोरिंग करके दरिया के साथ साथ भौलो ट्यूबवैल ज लगाये जायें ताकि पानी जो बह कर आता है, वह नीचे जा सके तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस सारी प्रोब्लम को हमने कोआर्डिनेटिड-वे में तय करना है।

श्री उपाध्यक्ष : आप कितना समय और लेंगे ?

चौधरी रिजक राम : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अभी खत्म ही कर रहा हूँ। इस बारे में एक मसला हमारा अपना ही पैदा किया हुआ है। वह मसला है कि फलड्ज के बारे में डिपार्टमेंट्स में कोआर्डिनेशन नहीं है। सड़क वाले सड़क बना देते हैं, नहर वाले नहर बना देते हैं। ड्रेन्ज जो थीं वह तो कन्सोलीडेशन वालों ने खत्म कर दी। उसक वक्त तो किसी ने ख्याल नहीं किया कि ड्रेन्ज की जरूरत पड़ेगी। अब पुराने वाटर गेज जो थे, वे बन्द हो गये हैं। मैं इस बात को यहां फिर दोहराना चाहता हूँ कि कोआर्डिनेशन से काफी रुपया बच सकता है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से आपके जरिये से यह प्रार्थना करूंगा कि इन्टर स्टेट कोआर्डिनेशन के साथ ही साथ डिपार्टमेंट्स की आपस में कोआर्डिनेशन करने के लिये कदम उठाये और इस पानी को दया में फैंकने की बजाये जितना मैक्सिमम कन्जर्व कर सकते हैं उतना तो कन्जर्व करने के लिये कदम उठाये जायें। इन भावों के साथ मैं आपका भुक्ति अदा करता हूँ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू (पाई) : डिप्टी स्पीकर साहब, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं तो अपने चीफ मिनिस्टर साहब से यह प्रार्थना करूंगा कि इस रैज्योलू इन में जो दो तीन जिले दिये गये हैं, उन दो तीन जिलों को ही नहीं बल्कि सारे हरियाणा को एज ए होल टेक अप किया जाये और सब जिलों को लेकर एक स्कीम या एक प्लान बनायी जाये। हरियाणा एक घर जैसा है जो कि एक छोटा सा सूबा है। इस तरह बात कहने से कुछ नहीं बनेगा कि पिछली गवर्नमेंट ने यह नहीं किया वह नहीं किया। किसी गवर्नमेंट पर इल्जाम लगाना गलत बात है। (We should forget about the past and talk about the future) हम सब मिलकर हरियाणा को ऊंचा उठाना चाहते हैं। इसलिये चाहे हमें छोटे मोटे काम दूसरे जो हैं, वे बन्द भी कर देने पड़ें, लेकिन हमें इस साल ड्रेन्ज की कन्स्ट्रक्शन और दूसरे फलड से राहत के काम वार-फुटिंग पर करने चाहिए ताकि जो इस साल तबाही आयी है वह आईन्दा आने वाले सालों में न आने पाय। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से यह कहूंगा कि इस काम में हम सब चीफ मिनिस्टर साहब के साथ हैं। वे एक छोटे छोटे कामों को अभी फिलहाल बन्द कर दिया जाये मगर यह काम सबसे पहले करना चाहिए। मेरे इलाके की एक मांग यह भी है कि उनका लगान माफ कर दिया जाये। इन्होंने सस्पेंड कर दिया है, यह ठीक नहीं है। अगर यह मामला मुआफ कर दें तो इनकी बहुत मेहरबानी होगी वरना सस्पेंड भी न करे तो अच्छा है। लेकिन जो दूसरे बैडली अफैक्टिड एरियाज हैं, उनमें वे एक

यह सस्पेंड रखें मगर हमारे इलाके कैथल डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में या तो मुआफ करें वरना सस्पेंड भी न करें। दूसरी और इम्पोर्टेन्ट बात यह है कि अगला बरसात आने तक यह बन कर तैयार हो जायें। बे तक दूसरे काम बन्द करने पड़े लेकिन यह काम पहले पूरा होना चाहिए ताकि दोबारा हरियाणा में फ्लडज तबाही न मचा सकें। (व्यवधान) मैं जनता पार्टी के मैम्बरान से यह प्रार्थना करूंगा कि आपको तो कांग्रेस पार्टी के मैम्बरान का भुक्र गुजार होना चाहिए कि इन्होंने गलती की तो आपको राज मिल गया। (व्यवधान) इसलिये मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि मेरे हलके में 5-6 गांव ऐसे हैं जैसे कापत है, पाई है, रवाना, रवानी, करोडा, काकोच, पिलनी हैं, जहां पर अभी भी पानी खड़ा है। तहसील कैथल में 20 पम्पस तो लगा दिये हैं। मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि इस इलाके में फौरी तौर पर पानी निकालने के लिये प्रबन्ध किया जाये ताकि जो खेत पानी से भरे पड़े हैं, वह काबलेका त हो सकें बे तक इसके लिये वहां के लिये और ज्यादा पम्पस दिये जायें।

अगर आप चने के बीज पर सबसिडी देते हैं, या उस कंसै न देते हैं या तो आप बीज बिल्कुल न दें और अगर देते हैं तो पूरा बीज दें, क्योंकि थोड़ा बीज होने से लड़ाई होती है। नम्बर दो बात यह है कि पाई एक गांव है। वहां 25 मन बीज गया है। डिप्टी स्पीकर साहब, 25 मन बीज से कैसे काम चल सकता है

या तो पूरा बीज दें, वरना बिल्कुल न दें। मेरी प्रार्थना है कि हमारे इलाके से फौरी तौर पर पानी निकाला जाए। धन्यवाद।

कैप्टन मांगे राम (झज्जर-एस0सी0) : उपाध्यक्ष महोदय, फलड के बारे में हर इलाके और हर जिले से आवाज आ रही है। झज्जर में जितना फलड का प्रकोप हुआ, उतना किसी इलाके में नहीं हुआ है। मेरे ख्याल में 125 बाढ़ पीड़ित गांवों में 41 गांव फलड की चपेट में हैं और उन 41 गांवों में से 36 गांवों में अभी तक चारों तरफ पानी भरा हुआ है। सारे इलाके के लोगों की यह आवाज है कि अगर 15 नवम्बर तक पानी न निकाला गया तो वहां जमनी के बीजने के कोई आसार नहीं है। जब तक पानी नहीं निकलेगा, वह जमीन बीजने के काबिल नहीं होगी। मेरे हल्के में आई0 पी0 एम0 साहब और फाइनेंियल कमि नर साहब और प्लानिंग कमि न की टीम आई थी और चौधरी चांद राम ने भी दौरा किया था और उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया था कि 31 अक्टूबर या 15 नवम्बर तक पानी निकाल देंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि यह पानी इतनी जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि पानी निकालने की रफ्तार काफी कम है। डिप्टी स्पीकर साहब, इन 36 गांवों में काफी पानी है और कुछ ग्रामों के लोग बाहर सरकियों में पड़े हैं जैसे कलोई, निवादा, सुरहती आदि। वहां पर लोगों के घर तबाह हो गए हैं। रा न बाढ़ पीड़ित ग्रामों में एक बार ही दिया गया। सैकिण्ड राउण्ड के बाद केवल पानी से धिरे हुए गांवों को ही दिया गया। वे लोग बेघर हैं और उनको ठीक तरह से ग्राण्ट

नहीं मिल रही है। रिलीफ के काम में उनको मदद नहीं मिल रही है। वहां बीमारी फैलने का खतरा है, क्योंकि पानी भरा हुआ है। लोगों की यह आवाज है कि अगर तहसील लेवल पर एक एम्प्लायमेंट आफिसर तथा उचित संख्या में क्लर्क और चपरासी रख दिए जाएं तो जो बेकारी की समस्या है, वह कुछ हल हो जाएगी क्योंकि बाढ़ के कारण बहुत लोग बेकार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह फलड के बारे में रेजोल्यूशन है आप इसी पर बोलें।

कैप्टन मांगे राम : डिप्टी स्पीकर साहब, वहां पर लोगों की आवाज है कि पुलिस और फौज की रिक्रूटमेंट अगर भुय कर दी जाए, तो इससे भी बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है। डिप्टी स्पीकर साहब, पानी को निकालने का बन्दोबस्त अगर जल्दी न किया गया तो बहुत तबाही होगी और इसका असर जनता पार्टी पर पड़ेगा। इसके लिए आपके द्वारा सरकार से मेरी प्रार्थना है कि जितना जल्दी हो सके वहां से पानी निकाला जाए, और फसल बिजवाने का माकूल इन्तजाम किया जाए।

श्री मूल चन्द मंगला (पलवल) : डिप्टी स्पीकर साहब, गुड़गांव जिले में फलड से काफी नुकसान हुआ है लेकिन पलवल, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद के क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। इस

क्षेत्र में यू0 पी0 की 12 ड्रेनें हैं और ये ड्रेन्ज सौ साल पुरानी हैं। वे अब काम नहीं करती क्योंकि यू0 पी0 की सरकार उनका ठीक इन्तजाम नहीं करती। यू0 पी0 की सरकार उनकी सफाई नहीं करती इसलिए उन ड्रेन्ज से पानी नहीं निकलता और उसकी वजह से फलड ज्यादा आते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, आपके द्वारा मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि या तो हरियाणा सरकार उन ड्रेन्ज को यू0 पी0 सरकार से ले ले और अगर यू0 पी0 सरकार उनको देने के लिए तैयार नहीं है तो उनका इन्तजाम हरियाणा सरकार अपने हाथ में ले ले ताकि उनकी सफाई अच्छी तरह से हो सके। अगर उन ड्रेन्ज की सफाई ठीक से हो जाए तो पानी ठीक तरह से निकल जाएगा। पानी न निकलने से ही फलड का जोर रहता है। इनकी सफाई होने से फलड की समस्या हल हो जाएगी। यही मेरी प्रार्थना है।

चौधरी पीर चन्द (रतिया-अनुसूचित जाति) : उपाध्यक्ष महोदय, कई दफा खड़े होने के बाद आपने मुझे बोलने का टाईम दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी सरकार ने, जहां फलड आता है उस फलड को रोकने के लिए जो स्कीम बनाई है, वह बहुत अच्छी स्कीम है और फलड को खत्म करने के लिए सरकार जो स्कीम बना रही है यह सरकार का बहुत सराहनीय काम है। मैं आपके द्वारा इरीगे टन मन्त्री और मुख्य मन्त्री से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे यहां रजिया के 18 गांव हैं वहां पर पिछले दस साल से फलड आता है और इस

दफा भी काफी पलड आए हैं। मुख्य मंत्री जी और सैन्टर के मिनिस्टर साहब वहां पर देखकर आए हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, वहां रमोही के नाम से एक नहर है। वह नहर अंग्रेजों के टाईम की है। वह नहर बन्द हो जाती थी और नहर की भाकल खत्म हो जाती है। उसका तमाम पानी जहां रेतीला इलका है वहां पहुंच जाता है। अगर वह नहर ठीक से काम करे तो वह उस इलाके की फसल को काफी फायदा पहुंचा सकती है लेकिन पानी पलड की भाकल में बदल जाता है और इन अठारह गांवों की फसल को तबाह करता है। दस साल से यहां के लोग इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। पिछली कांग्रेस की सरकार ने इस पर गौर नहीं किया। मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि तीन चार इलाकों के लिए जिस तरह की स्कीम बनी है, उस स्कीम के अन्दर इस इलाके को भी भामिल कर लिया जाए और यहां के लोगों को बचाने की कोशिश की जाए। मुझे इस सरकार के बारे में यह कहने में खुशी है कि इतनी बड़ी जो एक मुसीबत हरियाणा में आई। हमारी सरकार ने उसको बहुत अच्छी तरह से निभाया और यहां के आफिसर्ज ने भी बड़ी हिम्मत के साथ काम किया। अन्त में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि मैंने सरकार से जो प्रार्थना की है कि वह मेरे इलाके को भी उस पलड की

स्कीम में भामिल कर ले, मुझे आशा है कि सरकार मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करेगी।

चौधरी सन्त कंवर (हसनगढ़) : डिप्टी स्पीकर साहब, थोड़ा-थोड़ा समय दिया जा रहा है, लेकिन यह अच्छा है इससे सबको समय मिल जाएगा। डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा में जो बाढ़ आई है वह इतनी जोर से क्यों आई इसकी तरफ मैं आपकी मारफत सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पहली भी बरसात होती रही हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जितनी ड्रेनें निकाली गई हैं वह पोलिटिकल प्रैर से निकाली गई हैं। जिसके खेत में से यह ड्रेनें निकाली गई वह किसी मन्त्री की सिफारिश से निकाली गई। जहां खेत में लेवल नहीं था वहां भी ड्रेन निकाल दी गई और इस तरह से पानी निकलने में रूकावट आई।

दूसरी बात यह है जो कि चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि जो ड्रेन्ज डिपार्टमेंट है, वह पिछले दिनों इतना कष्ट रहा है कि जिसकी मिसाल और डिपार्टमेंट में नहीं मिलती। मैं अपने हल्के की दो ड्रेन्ज गान्धारा ड्रेन और पाकसमा ड्रेन का जिक्र करना चाहता हूँ। कागजों के ऊपर तो हम वहां से जो पानी लेते हैं, वह 70 क्यूसिक्स है लेकिन असल में वहां से 10 क्यूसिक्स पानी भी नहीं मिलता। दो-दो मीत तक की ड्रेन्ज ऐसी हैं जो कागजों में तो दिखा दी गई हैं कि निकाल रखी हैं लेकिन अगर मौके पर जाकर देखा जाए तो कोई ड्रेन नहीं है। मैंने नए एक्सियन साहब से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि 80-80 हजार की पेमेंट की गई है लेकिन वहां पर कस्सी

नहीं लगाई गई। सबसे जरूरी चीज यह है कि सरकार का ड्रेन्ज के ऊपर जो पैसा लगे, वह ड्रेन खोदने के लिए ही लगे, अफसरों और ठेकेदारों की जेबों में न जाए। तीसरी बात यह है कि जो धांसा बांध है इसके बंधने से सारे का सारा पानी रोहतक जिले की झज्जर तहसील में और रोहतक तहसील में जाता है। मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर कोई ड्रेन दिल्ली रोहतक रोड से साउथ की तरफ नहीं निकाली गई तो उस पानी का कोई इन्तजाम नहीं होगा। अगर कोई ड्रेन निकालें तो वह कम से कम इतनी बड़ी होनी चाहिए जितनी बड़ी डाईव रिन ड्रेन नम्बर 8 है। वैस्ट जुआं जो ड्रेन बाढ़ आने से पहले ही ओवर फ्लो कर गई थी। धांसा बांध के बारे में मैं यह बात बता देना चाहता हूँ कि वहां के लोग इस साल की बाढ़ से इतने परे गान हो गए हैं कि वे बेघर हो गए हैं। अगले साल भी अगर इस किस्म का वाकया हुआ तो वे लोग चाहे हमारी या सैन्टर की सरकार रोकने की कितनी ही कोशिश करे, उस बांध को तोड़ देंगे और भायद हम भी उसमें शामिल हों। लेकिन इससे पहले मैं यह चाहता हूँ कि सरकार इसी साल में पूरे तरीके से अपनी ड्रेन्ज का इन्तजाम करे और सारा पैसा ड्रेन्ज के ऊपर लगाया जाए। धन्यवाद।

चौधरी खुरश्रीर अहमद (ताउडू) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत हाउस

चौधरी सन्त कंवर : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि मैं सरकारी चेयरमैन की बात कहना भूल गया

था। ये जो तनखा लेते हैं, ये यही काम करते हैं या कुछ और भी काम करते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह प्वांयट आफ आर्डर नहीं है।

कामरेड भांकर लाल : हमें भी बोलने के लिए समय दिया जाए। हमारे साथ कल भी यही हुआ और आज भी वही हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए आपको भी समय मिलेगा। अब खुर गीद जी ने बोलना भुरु कर दिया है।

चौधरी खुर गीद अहमद : डिप्टी स्पीकार साहिब, आपकी मार्फत मैं एक चीज हाउस के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि हमारा मेवात का इलाका इस साल ही नहीं क्योंकि इस साल तो बहुत गैर मामूली तौर पर बारि ों ज्यादा हुई हैं, आम तौर पर बाढ़ की लपेट में आ जाता है। बारि 1 की वजह से हरियाणा का हर इलाका आज बाढ़ की लपेट में है, लेकिन अगर मामूली भी बारि 1 हो तो मेवात का इलाका ऐसा है कि मामूली बारि 1 से इसे बाढ़ की लपेट में आना पड़ता है। वह इसलिए आता है कि हरियाणा का यह आखिरी इलाका है। पानी का जो भी निकास है वह इसमें से होकर राजस्थान और यू0 पी0 को डेढ़ दो सौ मील की एक छोटी ड्रेन से निकालना पड़ता है और इस साल जबकि रिकार्ड बारि 1 हुई, तो नूंह और फिरोजपुर झिरका के इलाके में जो पानी आया वह तकरीबन आठ लाख एकड़ फीट पानी आया

जिसको निकालने का रास्ता सिर्फ एक छोटी से ड्रेन है, जिसे पहाड़ी ड्रेन कहा जाता है और हरियाणा के इलाके में उसे उजीना ड्रेन कहा जाता है। अगर वह ड्रेन सारा साल भी चलती रहे, तो भी यह पानी नहीं निकल सकता। आज बहुत से इलाकों का पानी तो निकल गया लेकिन तहसील नूह और फिरोजपूर झिरका में ऐसे गांव हैं, जिनके मकानों के दरवाजों तक आज भी पानी भरा हुआ है। खिड़कियों तक नहीं, दरवाजों तक भरा हुआ है और लोग गांवों से निकल कर अलग-अलग सरकियों में पनाह लिए हुए हैं। उसके लिए एक इलाज तो मुस्तकिल है जैसे कि कल हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की तकरीर में आया। उन्होंने फरमाया था कि कुल 22 करोड़ रुपये की लागत से एक उजीना डाइवर्न ड्रेन तैयार की जाएगी। तो मेरी उसके बारे में यह तजवीज है कि उजीना डाइवर्न ड्रेन कम से कम आउटफाल एरिया में पांच हजार क्यूबिक्स की हो और जहां से भुरू होती है। उस एरिया में यह कम से कम चार हजार या साढ़े चार हजार क्यूबिक्स की हो। जो पहले कभी इन्टर स्टेट एग्रीमेंट हुआ था, उसके भरसे पर उजीना के मुकाम पर एक उजीना रैगुलेटर के नाम से एक रैगुलेटर बनाया गया। रैगुलेटर तो उन स्कीमों के तहत बनाया गया था लेकिन इस साल तो वह हमारे तममा इलाके के लिए एक फांसी का फंदा साबित हुआ और लोगों के गले में यह फांसी लग गई। भाई संत कंवर ने तो कहा कि अगले साल धांसा बांध को तोड़ेंगे, लेकिन हमें तो डूबते हुआ को वह इस साल की तोड़ देना पड़ा। तो मेरी यह भी दरखास्त है कि उजीना रैगुलेटर को उखाड़कर हमें गा के

लिए खत्म कर दिया जाए, ताकि हमारे पर सैन्टर के दबाव से या दूसरी स्टेट्स के दबाव से यह फांसी हर साल फिट न हो और इस ड्रेन पर जो काम है वह इसी साल भुरु कर दिया जाए ताकि इस साल का पानी भी जो कि 6 महीने इसलिए लगेंगे क्योंकि यह चार सौ क्यूसिक ही पानी लेता है। दूसरी ड्रेन जो उजीना डाइव रिन के नाम से भुरु करने वाले हैं अगर उसके पायलट चैनल का काम अभी से भुरु करवा दिया जाए और कुछ थोड़ी कैपेसिटी की वह बनाकर अगले साल तक चालू करवा दी जाये तो हो सकता है कि हमारा इलाका अगले साल इसकी ज़द से बच जाए। आज वहां जो मौजूदा पोजी रान है, रा रान और रिलीफ जिस तरह से दिया जा रहा है। गवर्नमेंट ने रा रान दिया है, रिलीफ दिया है लेकिन जिस किसान का और जिस इलाके के आदमी का चार सौ विंटल गल्ला जाया हुआ हो तो उसको चार सौ ग्राम देकर तसल्ली नहीं हो सकती है, यह कोई उसका इलाज नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने मुसीबत में जितना भी किया है, उसके लिए मैं उसका भुक्रिया अदा करता हूं। इसका असली इलाज तब होगा जब हमारे इलाके से इस फलड का खात्मा किया जाएगा। सारी नूंह तहसील में मुझे पता चला है कि इन्होंने दौ सौ विंटल के करीब भेजा है। तो अगर इतना थोड़ा बीज हो तो जिस तरह मिस्टर जगजीत सिंह पोहलू अपनी स्पीच में कह रहे थे कि 20-30 किलो अगर गांव के नाम में आए या एक गांव में एक विंटल अनाज पहुंचे तो बताइए कि वह गांव को कितनी जमीन में डाला जाएगा। एक एकड़, दो एकड़ था अढ़ाई एकड़ से फालतू जमीन में

एक किंवटल बीज से बीजाई नहीं हो सकती। गेहूं का भी यही हिसाब है। इसलिए गवर्नमेंट जितना भी ज्यादा से ज्यादा बीज का इंतजाम कर सके उसे जल्द वहां पहुंचाए ताकि लोगों को बीज के सिलसिले में राहत मिल जाए। जिन गांवों में जितना भी राशन वगैरह का प्रोग्राम चल रहा है। वहां लोगों के सामने एक बड़ी टेक्नीकल डिफिकल्टी आ रही है जिसकी डैफिनेशन मैंने यह दी हुई है कि अगर गांव चारों तरफ से घिर जाए, तो मैरून डिक्लेयर किया जाता है। डिप्टी स्पीकर साहब, आपने वह इलाका देखा है और आपको पता भी है। रिवासन गांव को आप देखिए। सड़क उसके साथ से गुजरती है तो सड़क गांव के बीच में से गुजरने के कारण चारों तरफ से पानी से नहीं घिर सकती, सड़क खाली रह जाती है। घासेड़ा गांव में इसी तरह से सड़क खाली रह जाती है, मालब गांव में भी इसी तरह से सड़क खाली रह जाती है, लेकिन रकबा उनका एक इंच भी नहीं बचता इस वजह से वह मैरून की डैफिनेशन में नहीं आते। उनके लिए राहत का जो भी काम है वह पहुंचाया जाए। तो सरकार से मेरी यह भी दरखास्त है कि मैरून की डैफिनेशन को इस तरह से एक्सटेंड किया जाये कि अगर एक सड़क की वजह से कोई गांव चारों तरफ से न घिर सके और जमीन उसकी पानी से न बचे, तो उनको भी मैरून की डैफिनेशन में लिया जाए, ताकि उनको भी पूरी राहत मिल सके। मैं बहुत सी बातें कहना चाहता था, लेकिन आप बार बार मेरी ओर देख रहे हैं इसलिए आपका लिहाज करते हुए मैं आपसे इजाजत लेता हूँ।

श्रीमती भान्ति देवी (कलियाना) : उपाध्यक्ष महोदय, काफी देर से फलड के मसले पर बहस हो रही है। जैसा कि यहां चर्चा चलती रही कि 104 सालों से ऐसी कोई मिसाल हरियाणा में नहीं मिलती कि इतनी बाढ़ पहले कभी आई हो, लेकिन इसके लिए मैं अपने मुख्य मंत्री को, मन्त्रीगण को और अपने नव निर्वाचित साथियों को बधाई देती हूं कि इन्होंने किस निपुणता से गांव-गांव में जाकर, गहरे पानी में घुस कर गरीब जनता को राहत दी है। बाढ़ पीड़ितों को अनेक प्रकार की मदद दी गई, वस्त्र दिए गए, पैसे दिये गये खाने पीने का सामान, भोजन इत्यादि दिया गया, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे विपक्ष के भाई कांग्रेस पार्टी के सदस्य चौधरी भाम और सिंह जी ने इस बात को सच्चाई के साथ स्वीकारा है कि देहात के अन्दर सहायता कार्य जो हुआ है, उसकी मिसाल कायम कर दी। यह प्रमाणित कर दिया कि मुख्य मंत्री महोदय के दिल में किसानों के प्रति गरीबों के प्रति कितना दर्द है। लेकिन इसके साथ ही साथ मेरे मन में एक आंका है। मैं नहीं चाहती कि यह बाढ़ समस्या, जो इतना प्रबल रूप धारण किए हुए है, अनेकों वर्षों से कांग्रेस सरकार ने किस तरह इग्नोर किया है, क्यों नहीं इस ओर ध्यान दिया गया। इस गरीब किसान मजदूर की मजबूरियों को क्यों नहीं देखा गया। मैं सरकार से स्पष्ट रूप से कह देना चाहती हूं कि सड़के बनें या न बनें, कोई अन्य कार्य हो या न हो, स्कूल अपग्रेड हों या न हों, लेकिन जैसा कि इन्होंने आवासन दिया है कि आने वाले वर्ष में हरियाणा के अन्दर बाढ़ नहीं आएगी। तो मैं

चाहूंगी कि इस समस्या की ओर पूरी गम्भीरता के साथ विचार किया जाए। आ वासन देना और कोई बात कह देना बड़ा आसान होता है। इसका सर्वेक्षण करवा कर, आफिसरों को हिदायतें देकर सरकार को इस ओर कड़े कदम उठाने होंगे। जिस तरह से पिछली कांग्रेस सरकार करवाती रही, सर्वेक्षण गलत करवाती रही, योजनाएं गलत बनाई गई, कहीं यहां भी इन गलतियों की पुनरावृत्ति न हो जाए, और अगले साल फिर हमें यह दिन देखने न पड़ें। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि आने वाले वर्ष में यह नाटक दोबारा न देखना पड़े।

कंवर राम पाल सिंह (घरौंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, फलड के ऊपर सदन में रैजोल्यूशन आया है और हाउस में बहुत देर से चर्चा हो रही है। सबसे पहले मैं जनता सरकार को बधाई दूंगा जिन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बाढ़ पीड़ितों की सहायता की। इसके बाद मैं तमाम विधायकों को बधाई दूंगा जो जहां-जहां भी थे, बड़ी तेजी के साथ बाढ़ग्रस्त लोगों को सुविधा देने में सहायता की। फलड का कारण क्या था, क्या इसको रोकने के लिए स्कीमें नहीं बनीं थीं या जो स्कीमें बनाई गई थीं उन पर अमल नहीं किया था। कोई काम नहीं हुआ था? मैं कांग्रेस सरकार से पूछना चाहता हूं, जैसा मुझे पता लगा है कि ड्रेन्ज निकालने के लिए अफसरों ने स्कीमें बनाई थीं, लेकिन पैसा उन पर खर्च नहीं किया और कांग्रेस सरकार ने इस पैसे को काम्पलैक्स बनाने के लिए खर्च किया है और जगह-जगह एक-एक सफेद हाथी खड़ा कर

दिया। अगर यही पैसा ड्रेन्ज पर खर्च किया जाता तो हरियाणा की इस बुरी तरह से तबाही न होती। मैं, डिप्टी स्पीकर साहब, आपके द्वारा सरकार से दो तीन बातें कहना चाहता हूं और सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं। बड़ी खुशी की बात है कि मुख्य मंत्री जी ने कल एक ब्यान दिया था जिसमें बताया कि पानी से काफी एदिया खाली हो गया है, फसल बीजने के लिए ट्रैक्टर वगैरह का प्रबन्ध किया गया है, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। लेकिन मेरे यहां तो खास कर जमुना नदी का समस्या है। इसका बहाव पूरी तरह हरियाणा की तरफ आ गया है, क्योंकि यू0 पी0 गवर्नमेंट ने सारी जमुना नदी पर स्पर लगा दिए हैं, जिसकी वजह से पानी का बहाव हरियाणा की तरफ हो गया है। पानी को जहां कच्ची जगह मिलती है, उसकी तफर आया करता है। जमना के ऊपर बरसात से पहले सरकार ने स्पर नहीं लगाए। उजीना ड्रेन की तरह हो सकता है जमना का प्रकोप हरियाणा के ऊपर आ जाए। मैंने देखा है और मैं अपने जिले के कुछ अफसरों को साथ लेकर गया था और उनको दिखाया था कि 3 एकड़ जमीन बीच में आती है पुरानी जमुना और आज की जमुना के बहाव के बीच में 3 एकड़ जमीन का कटाव बाकी है। जैसे भुरु में बाढ़ आई थी, अगर ऐसी बाढ़ आ जाए, तो हो सकता है कि जमना का बहाव बदलने से पहले ही इसका फौरी तौर पर प्रबन्ध किया जाए। अगर बहाव बदल गया तो हो सकता है रास्ता खुल मसंद जिसके नाम से यह हल्का मसंद है, इसके कस्बे में इतनी बुरी हालत है कि तमाम मकान और दुकानें पानी के अन्दर हैं। अगर वहां फौरन ड्रेन न निकाली गई,

तो आज वहां हाल है, इससे भी बुरी हालत हो जाएगी। यहां का काफी रकबा पानी के नीचे है। लोगों के पास पंपिंग सैट्स भी नहीं है। अगर इस पानी को जल्दी से जल्दी न निकाला गया तो यह रकबा ज़ेरे का त आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्वामी अग्निवेश जी के हल्के के कुछ आदमी आए थे, वे कह रहे थे कि वहां 500 एकड़ भूमि में पानी भर गया है। इसको काटने का रास्ता भी नहीं है, पंपिंग सैट्स भी नहीं मिलते। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वहां पर पंपिंग सैट्स भिजवाए जाएं और पानी निकलवाया जाये। जो फसलें पानी के अन्दर खड़ी हैं, धान वगैरा, वे काबू आ सकें और दूसरी बीजाई हो सके। दूसरी सुझावन यह है कि दो तीन दिनों के लिए नहर बन्द करके और पानी काट करके सारा फलड का पानी निकल सकता है और लोगों को राहत मिल सकती है।

मास्टर रिजक राम (अम्बाला सिटी) : डिप्टी स्पीकर साहब, पिछले दिनों में हरियाणा में जो बाढ़ आई है इससे 80-90 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और सरकार में दिमाग में यह प्रश्न था कि किस तरह से इस समस्या को हल करें। बड़े पैमाने पर बाढ़ आई। हरियाणा के और भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, जहां थोड़े-थोड़े इलाके में 10, 20 या 50 गांवों में बाढ़ आती है और घरों को बहाकर ले जाती है। जहां मनुष्यों और पशुओं का जानी तथा माली नुकसान होता है। अम्बाला जिले के बारे में चौधरी रिजक राम ने बताया कि मारकंडा और टांगरी नदियां बड़ा

नुक्सान करती हैं। अम्बाला में तीन समस्याएं हैं – मारकंडा, टांगरी द्वारा नुक्सान, पीने का पानी और सिंचाई के साधनों की कमी; अम्बाला में पीने का पानी नहीं मिलता लेकिन दूसरी तरफ बाढ़ के दिनों में ये नदियां गांवों में मकानों को नुक्सान पहुंचाती हैं और लोगों और पशुओं को बहा कर ले जाती हैं। जहां से पानी जाता है, वहां की जमनी प्यासी रह जाती है, इसलिए सरकार द्वारा इन नदियों पर छोटे-छोटे बांध लगा कर पानी को रोक लिया जाए और इस पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाय। इससे जमीन की पानी की प्यास भी बुझ जाएगी, बाढ़ से बचाव भी हो जाएगा और लोगों को पीने का भी पानी मिल जाएगा।

चौधरी लाल सिंह (नारायणगढ़) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि इसमें कोई भाक नहीं कि चौधरी देवी लाल की सरकार ने बाढ़ वाले क्षेत्रों में इतना ज्यादा काम किया है जिसकी तारीफ मैं कर नहीं सकता। आज तो अपोजी उन वाले भी तारीफ कर रहे हैं, जिन्होंने किसी चीफ मिनिस्टर की तारीफ नहीं की थी। इन्होंने रात दिन फिर कर काम किया है। लेकिन एक बात मैं सरकार को बताना चाहता हूं। हमारी नारायणगढ़ तहसील में से बहुत सी नदियां गुजरती हैं। वे गांव को रातों रात गिरा जाती हैं। वे लोगों के खेतों को और घरों को भी नुक्सान पहुंचाती हैं। पिछले दिनों फाइनेंशियल कमिशनर साहब ने जिनका मैं नाम नहीं लेना

चाहता, क्योंकि ऐसा विधान में नहीं है, इमीजिएटली वायरलैस के जरिरु मेरे साथ एस0डी0एम0 को भेजा, अफसरों ने मुआयना किया और सारे एस्टीमेट्स बनाए गए, लेकिन मैं मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत मेहरबानी होगी, कृपा होगी यदि वहां पर स्पर लगा दिए जाएं। ऐसा करने से वहां के गांव गिरने से बच जाएंगे। वहां एक गांव बादवाली है। वहां राजपूत फौजी कुछ थे, वे रहते हैं। यह तबाह हो गया है। सारे का सारा नदी ने खत्म कर दिया है। तीन दफा वहां कमि नर साहब और डी0सी0 साहब गए। मैं अर्ज करूंगा कि यहां स्पर लगाये जाएं ताकि गांव की जमीन बच जाए। ऐसे और भी 45 गांव हैं। मैं अपने मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि नारायणगढ़ तहसील में जिन जगहों के एस्टीमेट्स बन गए हैं, वहां जल्दी से जल्दी स्पर लगवाने की कृपा की जाए और जहां स्पर लगे हुए हैं, उनकी मुरम्मत के आर्डर दे दिए जाएं। चौधरी देवी लाल जी, चूंकि गरीबों के नेता हैं इसलिए मेरी उनसे इस ओर ध्यान देने की हाथ जोड़कर प्रार्थना है।

चौधरी राम किान (सफीदों) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने एक बहुत अहम मामला फ्लड के सम्बंध में चला हुआ है। मैं सदन का ज्यादा समय लेना इसलिए उचित नहीं समझता क्योंकि इसके बारे में अपने-अपने जिले के बारे में सभी मैंबरो ने अपने-अपने विचार रखे हैं। लेकिन भगवान का कुछ ऐसा प्रकोप इस साल हुआ जिससे हरियाणा का एक तिहाई भाग बहुत बुरे

तरीके से पलड से अफैक्ट हुआ। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि हमारे मुख्य मंत्री जी, इरीगे इन ऐंड पावर मिनिस्टर साहब, बाकी मन्त्रिगण और बाढ़ पीड़ित इलाके के विधायकों ने खूब काम किया। पहली सरकार ने सिवाय रैस्ट हाउसिज़ खोलने के कोई काम नहीं किया। जिस पलड की वजह से हरियाणा का वीकर सैव इन और जमींदार लोग बुरी तरह तबाह होते हैं, उसकी तरफ उसने कोई ध्यान नहीं दिया। यह बड़ी भार्म की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, जिला जींद सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। खासकर सफीदों, जुलाना और बड़ौदा हल्कों के साथ तो सौतेली मां की तरह व्यवहार होता रहा है। इस इलाके के 65 गांव में से 45 गांव तो कम्पलीटली मैरुन्ड हुए पड़े हैं। 29 गांव में करीब अढ़ाई फुट पानी खड़ा है। इसी तरह 9376 एकड़ भूमि में अढ़ाई फुट पानी खड़ा है जिसकी वजह से किसान खेतों में बिजाई नहीं कर सकता। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सफीदों में जल्दी से जल्दी पानी निकालने का प्रबन्ध करें ताकि गरीब किसान अपनी फसल बो सके। सावनी की फसल तो वैसे बरबाद हो गई और यदि रबी की फसल भी बरबाद हो गई तो बेचारा किसान कहीं का नहीं रहेगा। मैं सरकार का वैसे बड़ा म कूर हूं क्योंकि अब की दफा इसने जिला जींद में कलायत और सफीदों के हल्के के अन्दर काफी सहूलियतें मुहैया की हैं। इसके बावजूद भी मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उस इलाके की यह मांग है कि यदि उस इलाके में तमाम का तमाम मालिया माफ कर दिया जाऊ तो वह इलाका सरकार का बहुत आभारी होगा। आगे के लिए मेरी सरकार

से यह प्रार्थना है कि चाहे दूसरे कामों में देरी हो जाए मगर बाढ़ की रोकथाम के लिए अभी से प्रबन्ध कर लिए जाएं ताकि यह दिन हरियाणा को फिर न देखने पड़े। इन भावों के साथ मैं दुबारा जितना इस सरकार ने इस दफा पलड अफैक्टिड एरिया में लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिए काम किया है और उनसे हमदर्दी दिखाई है उसकी सराहना करता हूँ।

श्री दीप चन्द भाटिया (फरीदाबाद) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत सदन के सामने कहना चाहता हूँ कि मैं जिला गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मेरे यहां चीफ मिनिस्टर साहब और बाकी अन्य इलाका देखा। मैं भी उनके साथ था। मैं सरकार से चाहूंगा कि मेवात का इलाका चूंकि बहुत अफैक्टिड है इसलिए उसकी ओर खास ध्यान दिया जाय। डिप्टी स्पीकर साहब, जैसा मेरे भाई खुरीद ने कहा, मैं भी अपने इलाके के बारे में कहना चाहता हूँ। मेरे हल्के में 29 गांव हैं। फरीदाबाद टाउन के साथ जो सबसे ज्यादा अमृत देने वाला इलाका है। मेरी कांस्टीच्यूएंसी में 29 गांव हैं। 20 गांव पानी से अफैक्टिड हैं। मैं यह चाहूंगा कि कम से कम मेरे हल्के को जरूर देखा जाय। जहां पर खेतों में पानी पड़ा हुआ है उसका खास ध्यान किया जाये। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि वहां एक नाला निकलना था। उसकी स्कीम पास है, लेकिन वहां जो एस0डी0एम0 मिस्टर चेटर्जी हैं, उसकी पावन पता नहीं कहां गई, वह नाले की खुदवाई ही नहीं करवा सकता। मेरी प्रार्थना है कि उन सभी अफसरान को उस काम को

करने के लिए हिदायत की जाय। जो अफसर काम करने के योग्य नहीं हैं उनको या तो हटाया जाए या मुअत्तिल किया जाए।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात इस सदन को बताना चाहता हूँ कि पिछली सरकार ने जो नाले बनाए, ड्रेन्ज बनाई, उनमें यदि आप सीमेंट देखेंगे, तो सीमेंट नजर नहीं आएगा। पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट के तहत हुडा के अन्दर जिन कान्ट्रैक्टर्ज ने काम किया है, उन्होंने बहुत गड़बड़ की है। नालों में आपको सीमेंट नहीं मिलेगा। रोड़ी, चिप्स वगैरह भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर इनक्वायरी की जाए तो सारी बात का साफ साफ पता लग जाएगा। इसलिए मैं मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा जैसा कि मैं वरबली भी कर चुका हूँ कि इस मामले की जरूर इनक्वायरी की जाये। कोई इनक्वायरी कमी न बैठना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि यह दे 1 का पैसा है। इसे हम गरीब जनता पर टैक्स लगा करके बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करते हैं। इसका प्रयोग ठीक तरह से होना चाहिए। इतना कहकर आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूँ।

चौधरी हर स्वरूप बूरा (महम) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए थोड़ा टाईम दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। फ्लड के बारे में चूंकि काफी बातें आ चुकी हैं इसलिए मैं ज्यादा अर्ज नहीं करना चाहता लेकिन कुछेक बातें जरूर कहना चाहूंगा। हमारे बुजुर्ग सदस्य चौधरी रिज़क राम जी ने कहा कि इस महकमे के लोगों के अन्दर तालमेल नहीं है

जिसकी वजह से फलड का कारण बना हुआ है लेकिन इससे ज्यादा मैं एक और कारण समझता हूँ। पानी का नैचुरल बहाव होता है। जिन लोगों के खेत उस बहाव में आते हैं वे एम0एल0ए0 की सहायता लेते हैं, जो गलत बात है। इस बात की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ और सुझाव देता हूँ कि अथॉरिटीज़ को स्वतन्त्रत ढंग से काम करने दिया जाए। जो नैचुरल फलो है अगर उसको देखकर पानी को ड्रेन आउट करने में मदद की जाय तो बहुत अच्छी बात होगी। यह निहायत ही ज़रूरी बात है। इसमें अगर हम इमदाद करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि फलड रिलीफ के काम में हम बहुत बड़ा योगदान करेंगे। मेरे हलके में क्योंकि बाढ़ का ज्यादा कोप नहीं है इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए सिर्फ एक प्रार्थना सरकार से करना चाहता हूँ मेरे हलके में एक बड़ी नहर है लेकिन वह कच्ची है अगर उसे पक्का कर दिया जाये तो सीपेज की वजह से जो फलड की सिंचुए ान बनी हुई है वह दूर हो सकती है। धन्यवाद!

स्वामी आदित्यवे । (हथीन) : डिप्टी स्पीकर साहब, आपने जो समय दिया इस के लिए मैं आपका आभारी हूँ लेकिन मुझे दुःख है कि हमारे गुड़गांव की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं हुआ है। मेरी सीट भी कोने पर लगी हुई है। मुझे समय भी आखरी में दिया गया है। (विघ्न) मैं आपका ध्यान दो तीन बातों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री जी ने बहुत अहम घोशणा की है। उन्होंने यहां कहा है कि मेवात के इलाके को बचाने के लिए 22 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। मैं इस विषय में सरकार से यह निवेदन करूंगा कि इस रुपए से जो भी ड्रेनें खोदी जाएं, वे हरियाणा की सीमा में से ही खोदी जाएं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की जमीन में से नहीं। अगर वहां से खोदने का सिलसिला बन गया तो वहां की जमीन को इक्वायर करना, एक और समस्या बन जाएगी। इसलिए ये ड्रेनें हरियाणा की सीमा में से ही खोदी जाएं। इसमें कोई भाक नहीं है कि फ्लड के टाईम पर सरकार ने जो सहायता की वह सराहनीय है परन्तु मेरा निवेदन है कि वे इस इलाके की ओर भविष्य में भी ध्यान रखेंगे। सरकार की ओर से अब जो वर्तमान में राशन दिया जा रहा है वह पर्याप्त नहीं है। आजकल चार सौ ग्राम आटा दिया जा रहा है, वह केवल 56 पैसे का होता है इसका मतलब यह हुआ कि 28 पैसे पर डाइट खर्च किया गया। 28 पैसे डाइट में आजकल के समय में कैसे गुजारा किया जा सकता है ? मैं आपके थरु सरकार के सम्मुख एक तजवीज़ रखना चाहता हूँ, अगर इस हिसाब से उन लोगों को राशन दिया जाए तो अच्छा होगा और उनका गुजारा भी ठीक प्रकार से चल सकेगा। उन लोगों को आटा 500 ग्राम, चावल 150 ग्राम, दाल 100 ग्राम, मसाला 50 ग्राम, गुड सौ ग्राम और अढ़ाई किलो लकड़ी दिया जाना चाहिए। मेवात के गांवों का अब भी कितना ही ऐसा एरिया है जहां पर बीजाई नहीं की जा

सकती है। जहां पर ऐसी स्थिति है वहां पर राशन की परमानैन्ट व्यवस्था की जाये, तो बेहतर रहेगा।

बाढ़ के कारण से वहां पर काफी बीमारियां भी फैली हैं। मेवात के क्षेत्र में मलेरिया का भी भयंकर प्रकोप हुआ है। वहां पर मलेरिया से करीब 500 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, और अन्य बीमारियों से भी लोग करे हैं, उनकी तादाद 3000 हजार है। इसके साथ ही मैं यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि सरकार की ओर से दवाईयां तो दी गई परन्तु उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। मेरे पास लिस्ट मौजूद है प्राइमरी हेल्थ सैन्टर औरंगाबाद से पांच हजार 600 टेबलैट्स की स्मलिंग हुई। औरंगाबाद हेल्थ सैन्टर की ये पोजीशन है। जनता सरकार तो लोगों तक दवाईयां पहुंचाने का प्रयास कर रही है लेकिन जो बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं वे सही जगह पहुंचने नहीं देते हैं। इसलिए सरकार को दवाईयों के डिस्ट्रीब्यूशन की ओर अवधान देना चाहिए और जो उन लोगों को सरकार की ओर से इमदाद मिल रही है वह सही ढंग से मिलनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : स्वामी जी आपने काल अटैंशन नोटिस दिया था, उसमें ये सभी बातें आ गई हैं और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बड़े विस्तार से उत्तर दिया है।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, कल हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री चौधरी देवी लाल जी ने

स्वामी अदित्यवे 1 की काल-अटैं 1न मो 1न पर वक्तव्य दिया था और वह काफी तफसील के साथ दिया था। उन्होंने कल यहां यह बता दिया था कि हरियाणा में फ्लड क्यों आया। उन्होंने यह भी बता दिया था कि फ्लड ने हरियाणा को कितना बरबाद किया ? आदरणीय चौधरी साहब ने यह भी बता दिया था कि इस फ्लड से हरियाणा की जनता को कितना जानी या माली नुकसान सहना पड़ा है। यह बात भी यहां बताई गई कि सरकार ने इस फ्लड के आने पर क्या-क्या किया और कितना रिलीफ का काम किया और हरियाणा में फ्लड की तबाही के असर को दूर करने के लिए कितने एफर्ट की जरूरत है, कितना पैसा दरकार होगा, कितना पैसा मर्कजी सरकार से ले सकेंगे, यह सब तफसील में वक्तव्य चीफ मिनिस्टर साहब ने दिया। आज यहां हाउस में एक रैजोल्यू 1न मूव हुआ है जिस पर मैबर साहेबान ने भी अपने विचार रखें। मैबर साहेबान ने जो विचार यहां रखे, उनके बारे में कुछ अर्ज करना चाहूंगा।

बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे से पहले वाली सरकार ने जितना भी रुपया यहां उपलब्ध किया था वह बाढ़ की समस्या या हरियाणा की तरक्की या बहबूदी पर खर्च नहीं किया, ऐसी ऐ 1गाहों के बनाने पर खर्च किया गया, जैसे भिवानी की ऐ 1 गाह, सोहना की ऐ 1गाह और भी ऐसे-ऐसे रैस्ट हाउसिज हैं, जिनमें 17-17 कमरों के सूट्स हैं और सतरह-सतरह लाख रुपए की लागत से बने हुए हैं। कितना अच्छा होता अगर पिछली

सरकार जैसा कि हमारे बुजुर्ग सदस्या चौधरी रिजक राम जी ने सदन को बताया कि नार्दन जोन में कभी वैट साइकिल और कभी ड्राई साइकिल आते हैं। हर आठ-दस साल बाद साइकिल बदलते रहे हैं। जब ये पता था कि हर आठ-दस साल के बाद बाढ़ की समस्या आ सकती है, तो पहली सरकार ने क्यों नहीं प्रबन्ध किया ? चौधरी भाम सिंह जी यहां से उठ कर चले गए, वरना मैं उनसे पूछता कि उस टाइम पर बाढ़ को रोकने का क्यों नहीं इन्तमाज किया गया ? क्या आवकता थी ऐसा फर्नीचर उन रैस्ट हाउसिज के लिए खरीदने की जिस पर आम आदमी को बैठते हुए भी डर लगता है, लेकिन उन लोगों के तो भाँक ही और थे ? वे लोग तो एय्या गी और अपने को खुशहाल व अमीर बनाने के लिए आए थे ?

उस हुकूमत के पचात् जनता पार्टी की हुकूमत आई। 21 जून को जनता पार्टी ने भापथ ग्रहण की, मुझे याद है कि उसी दिन से बून्दा बांदी भुरू हो चुकी थी यानि कहने का मतलब यह है कि जिस दिन से जनता पार्टी की सरकार बनी उसी दिन से बारि ग भुरू हुई। उस बारि ग से हरियाणा का एक तिहाई हिस्सा फलड की लपेट में आ गया। हम लोग हरियाणा के बाढ़ के मसले को नैशनल लेवल पर ले गए। आदरणीय प्रधान मन्त्री मोरार जी देसाई हरियाणा के फलड अफैक्टिड एरिया को देखने के लिए आए, गुह मन्त्री चौधरी चरण सिंह भी इस एरिया में दौरा करके गए और सरदार सुरजीत सिंह बरनाला ने भी दौरा किया,

इन सभी लोगों की तवज्जों हरियाणा में बरबादी हुई है, नुकसान हुआ है, उस ओर दिलाई गई। हरियाणा में फलड को रोकने के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यू० पी० के लिए ब्रॉडर प्लान बने, यानी सब स्टेट्स के लिए एक प्लान बने जो कि बहुत ही निहायत जरूरी है। हमें इस किस्म के छोटे विचार नहीं रखने चाहिए, कि वे अलग स्टेट हैं, हमारा उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। हमें यह सोचना होगा कि राजस्थान में हमारे अपने भाई हैं, क्या राजस्थान में कोई विदे गी सरकार है, क्या वह कोई विदे गी स्टेट है ? हमें अब इस भावना से चलना होगा कि चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो और चाहे उत्तर प्रदेश हो, सब एक हैं। ऐसा हल सोचना है कि सभी स्टेटों की समस्याओं का समाधान हो सके, ऐसा प्लान बनाना होगा। हमें भावावे गी में आकर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। चौधरी भाम गेर सिंह जी फरमा रहे थे कि धांसा बांध तबाही लाया है उसके लिए दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है और धांसा बांध के गेट इसलिए खोले गए कि चौधरी रणबीर सिंह जी उस बांध पर पहुंचे। चौधरी भाम गेर सिंह जी तो बड़े सभ्य और सुलझे हुए आदमी होते थे, लेकिन जब से कांग्रेस में आए हैं, तब से अजीब सी बातें करने लग गए हैं। मुझे तो उनकी बातें सुनकर अचम्भा होता है कि हजारों वर्कर्स कांग्रेस के वहां पर गए।

तभी किसी भाई ने बताया था कि दो व्यक्ति बहादुरगढ़ गए धांसा बांध तक वह भी नहीं पहुंच सके। उनमें एक तो चौधरी

रणबीर सिंह थे और दूसरे थे श्री हरि सिंह जी जो कोई प्रोफ़ैसर थे। चौधरी रणबीर सिंह ने पब्लिसिटी गेन करने के लिए प्रैस के द्वारा यह ब्यान भी दिया था कि मैं भूख हड़ताल भी करूंगा। न तो वह भूख हड़ताल ही हुई और न उसके बाद उसका जिक्र ही आया। चौधरी रणबीर सिंह का किस्सा तो यह है। इस बारे में दिल्ली की सरकार ने ड्रेनेज के सिलसिले में फ्लड वाटर की निकासी के सिलसिले में जितना सहयोग दिया, वह सराहनीय है। इसके लिए मैं दिल्ली की सरकार को मुबारिकबाद देता हूँ। --- (थम्पिंग) --- कुछ सदस्यगणों ने कई बातें उठायीं। उन्होंने अपने-अपने इलाकों की अपनी अपनी समस्याएं सरकार के सामने रखीं हैं। मैं सारे सदस्यों को यह वि वाय दिलाना चाहता हूँ कि इस मसले को हल करने के लिए जनता पार्टी की सरकार ने यह तहैया कर लिया है कि इस मसले को हरियाणा लेवल पर ही तय किया जाएगा, ऐज़ ए होल तया किया जाएगा। किसी भी इलाके में जहां पर बाढ़ आती है, या फ्लड आता है, को छोड़ा नहीं जाएगा। इन सारे इलाकों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार की यह मन् ता है कि इस मसले को हल किया जाए। कुछ और माननीय सदस्यों ने भी यहां पर अपने विचार रखें। वहां पर चौधरी भाम ार सिंह जी ने कहा कि उनके इलाके में फ्लड वाटर की निकासी के काम के लिए अफसरान ने कोई ध्यान नहीं दिया। बड़े अफसोस की बात है। वह उठकर चले गए। मैं दो तीन बार नरवाना हल्के का दौरा कर चुका हूँ। चौधरी भाम ार सिंह जी मेरे साथ थे। उन्होंने यह इल्जाम भी लगाया कि अफसरों ने वह

काम भी नहीं किया जो कांग्रेस के जमाने में किया करते थे। मैं आपके जरिए हाउस को यह बता देना चाहता हूँ कि चौधरी भाम ार सिंह जी मेरे सथ थे। वे फ्लड एडवाइज़री कमेटी के मेंबर भी हैं। हम जगह-जगह लोगों के पास जाते थे। उनसे यह पूछते थे कि सरकार की तरफ से किसी काम में कोई कमी है, या किसी अफसर ने कोई काम करने में कमी दिखाई हो, तो आप बताएं। चौधरी भाम ार सिंह जी के रूबरू वे लोग यह कहते थे कि इस बार सरकार ने और सरकारी अफसरान ने जितना काम किया है, उतना पहले कभी काम नहीं हुआ। इनके सामने लोगों ने यह बातें कही हैं। चौधरी भाम ार सिंह जी से जब मैंने कहा कि आप भी कोई सुजै ान दो कि क्या सरकार के काम में कोई कमी है तो चौधरी भाम ार सिंह जी ने कहा कि मेरे ख्याल में कोई कमी नहीं है। उन्होंने यहां पर यह भी कहा कि अफसरान ने काम नहीं किया। मैं हाउस की इन्फर्मे ान के लिए बता देना चाहता हूँ कि हमारे फाइने ायल कमि ानर श्री कैपरिहन साहब के बारे में खुद मुझे लोगों ने बताया कि वे भी निकर और कमीज पहने 4-4 फुट पानी में खड़े रहे। मैं पिछले दिनों मेवात के इलाके में श्री भाकरुल्लाह और चौधरी सरदार खां साहब के साथ दौरे पर गया। वे भी इस बस बार के गवाह हैं कि वहां पर सारे अफसर यानी एस0डी0ओ0, बी0डी0ओ0 वगैरह वहां पर मौजूद थे। आप इस बारे में श्री भाकरुल्लाह साहब से पूछ सकते हैं क्योंकि चौधरी सरदार खां तो मेरी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। श्री भाकरुल्लाह साहब इस बात के गवाह हैं और आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने

भी अफसरान के काम में कोई कमी नहीं देखी। इसके लिए मैं अपने अफसरान का अपनी पार्टी की तरफ से माफ़ कर हूँ। नरवाने हलके से जहाँ का चौधरी भामदेर सिंह जी जिक्र कर रहे थे, नारायणा, कैथल, उझाना इन जगहों का पानी निकाल दिया गया है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हम वहाँ पर रबी की फसल जरूर काट करवा देंगे। वहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं छोड़ेंगे, यह मैं हाउस को अयोरेंस देना चाहता हूँ। एक बात और मैं आपके माध्यम से इस सदन में कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस इलाके के लिए जिस इलाके से चौधरी भामदेर सिंह जी ताल्लुक रखते हैं और हमारे एक मन्त्री महोदय चौधरी प्रीत सिंह राठी भी वहाँ से ताल्लुक रखते हैं। हमने एक पुण्ड्री ड्रेन बनाने की स्कीम बनाई है, जिसके बाद उस इलाके में बाढ़ का प्रकोप बिल्कुल नहीं रहेगा। झज्जर एरिया के लिए कैप्टन मांगे राम ने कहा। इसमें कोई भाक नहीं है कि झज्जर एरिया में काफी भारी बाढ़ थी, वहाँ पर बाढ़ का काफी प्रकोप था, लेकिन उसमें भी मैं इस सदन के माध्यम से उनको यह यकीन दिलाना चाहता हूँ कि नवम्बर के मिडल तक वहाँ से भी पानी निकाल दिया जायेगा। और लोगों की रबी की काट जरूर करवा दी जाएगी। असन्ध टाउन के लिए रामपाल सिंह जी ने कहा क्योंकि मास्टर जोगी राम जी बीमार थे। वे मेरे पास भी आए थे, वे बोल नहीं पाए। उनके लिए मैं सरकार की तरफ से एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ। उस इलाके के लिए भी एक ड्रेन प्रोजेक्ट की जा रही है जिससे कुदरती तौर पर बहाक के साथ ही वहाँ का सारा पानी निकल जाएगा और आगे

को भाहर की ऐसी हालत भी नहीं होगी जो इस बार हुई है। तो यह थोड़ी सी बातें मैं आपसे अर्ज करना चाहता था, मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूँ कि इस मसले को हल करने के लिए हरियाणा सरकार टाप प्रायरिटी देना चाहती है। हमारे 5-6 स्टेट के मुख्य मन्त्री की एक कान्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर की सदरत में हो चुकी है। मैं चौधरी देवी लाल की सरकार की तरफ से इस सदन के मेंबरान को यह वि वास दिलाना चाहता हूँ कि हम फलड के मसले को टाप प्रॉयरिटी पर रखेंगे। मैं यह भी यकीन दिलाऊँ कि जितना हो सकेगा, इस बात का बन्दोबस्त किया जाएगा कि अगले साल अगर यह स्कीमें जैसे हमने बनाई हैं, परमात्मा ने चाहा कामयाब हो गयीं, तो जितना प्रकोप इस बार हुआ है, उससे 90 फीसदी कम हो जाएगा। अगर यही हालत रही, तो अब के मुकाबले में 10 फीसदी की बाढ़ का प्रकोप रह जाएगा। इसके बाद स्वामी आदित्यवे 1 ने हाउस में यह कहा कि 3000 लोग बीमारी से मर गए। यह फिगर उन्होंने आज दी: लेकिन जो फिगर उन्होंने अपने काल-अटैं 1न मो 1न में दी थी, उसें उन्होंने 5,000 कहा था। तो 5000 से अब वे 3000 पर आ गए। इस बात का जवाब कल ही मुख्य मंत्री महोदय ने दे दिया था।

--- (व्यवधान) --- ऐसी कोई बात नहीं है। इनके पास गलत फिगर्ज हैं। जो मुख्य मन्त्री जी ने कल ब्यान दिया कि सिर्फ 54 व्यक्ति मरे हैं और वे भी घरों के गिरने से मरे हैं, कोई मलेरिया से या कोई कौलरा से नहीं मरा। इन बीमारियों से कोई व्यक्ति मरा हो, ऐसी इनफर्में 1न सरकार के पास नहीं है। तो फलड के

बारे में सरकार क्या करने जा रही है, इसको मैं दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता क्योंकि उन सारी बातों को दोहराना तो रैपीटी वन ही होगा। कल इस बारे में तफसील के साथ एक मुकम्मल स्टेटमेंट मुख्य मन्त्री जी दे चुके हैं। एक बात उन्होंने कही कि जो खाना उन्हें दिया जाता है उसका रा वन बड़ा कम दिया जाता है। उन्होंने यह कहा कि 400 ग्राम गेहूं का रा वन थोड़ा है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि हमें तो जेलों में 350 ग्राम मिलता था और वह भी बच जाता था। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि सरकार उन्हें 400 ग्राम गेहूं का रा वन देती है, तो इसके साथ ही 100 ग्राम दाल भी तो सरकार देती है तो इस प्रकार 500 ग्राम रा वन हो जाता है। मैं उन्हें यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति 100 ग्राम अपनी दाल न लेकर उसके बदले में गेहूं का रा वन लेना चाहे, तो उसको 500 ग्राम रा वन गेहूं का भी हम पूरा कर सकते हैं।

मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिस रकबे में पानी है या नहीं है हरियाणा सरकार इस बात की जिम्मेदारी लेती है कि हरियाणा के किसी भी व्यक्ति को सर्दी के कारण या भूख के कारण नहीं मरने दिया जाएगा।

चौधरी भाम ोर सिंह : ** ** ** ** ** **

** **

** **

**

डा० मंगल सिंह : यह किस मो तान पर बोल रहे हैं ।

चौधरी खुर पीद अहमद : डिप्टी स्पीकर साहब, यह इर-रैलेवैन्ट बोल रहे हैं, इसलिए यह एक्सपंज किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, यह एक्सपंज कर दिया जाये ।

Now I will putt the amendment to the vote of the House.

Question is-

That in line 2 in between the word 'Government' and the word 'that', insert the words 'to move the Central Government.'

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now I will put the resolution, as amendmend, to the vote of the House.

That the House recommends to the State Government to move the Central Government that maximum Financial and every kind of other help be given to the flood affected people, as the unprecedented flood has caused heavy damage to their lives, properties and crops.

This House further recommends that concrete steps be taken to prevent the occurence of such flood in future in the State.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: The next resolution is in the name of Rao Dalip Singh. He is not present in the House.

The next resolution is in the name of Shri Mool Chand Jain. He is also not present in the House.

12.52 p.m.

Mr. Deputy Speaker: The House stands adjourned sine-die.

(The Sabha then adjourned sine-die.)*